चिंतन

कांग्रेस की हार से मिला सहयोगियों को हथियार

हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस हार से तो परेशान है ही, इसे हजम करने के लिए तरह-तरह के बहाने गढ़ रही है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े कंपटीशन वाले एग्जाम को क्लियर करने से चूक जाता है, तब वह अक्सर यह कहता है कि थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो बात कुछ और होती। काश उसका उत्तर ये किया होता आदि। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के पास भी बताने को ऐसी ही मिलती-जुलती बातें हैं। कभी ईवीएम तो कभी भीतरघात, सीएम फेस को लेकर तनातनी, कुमारी सैलजा का प्रचार से दूर होना। हुड्डा परिवार पर हद से अधिक भरोसा, नतीजों के बाद कांग्रेस की हार के यही प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। यह सही है कि चुनाव में पार्टी का बंटाधार हो गया, लेकिन इससे बड़ी परेशानी एक और है। इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों को कांग्रेस पर प्रहार करने और उसे दबाव में लेने का मौका मिल गया है। हार पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए। शिवसेना (उद्धव गुट) ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ना चाहते है तो पहले बता दे। राउत ने कहा कि भाजपा ने हारी हुई बाजी जीत ली। हर कोई मानता था कि कांग्रेस जीत रही है लेकिन वह फिर भी हार गई। भाजपा जीती क्योंकि उसके पास एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से सोचना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एग्जिट पोल इतने गलत होंगे। 30, 60 बन गए और 60, 30 बन गए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप के नगर पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा था- देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। इन नेताओं के बयानों में साफ इशारा है कि ये सब कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के बाद महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी जानते हैं कि अगर कांग्रेस दबाव में रहेगी तो गठबंधन में सहजता होगी। कांग्रेस ज्यादा सीट की मांग भी नहीं कर पाएगी। संजय राऊत के शब्द साफ-साफ साफ यही संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस नेता भी जानते हैं कि इस हार ने पार्टी का गणित बिगाड़ दिया है। इसी को देखते हुए ही राहुल ने एक्स पर लिखा, 'हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे।' राहुल अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा में हार से सहयोगियों को दबाव बनाने का हथियार मिल गया है, जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसका तोड़ किस तरह से निकालती है। जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। यह चुनाव न केवल एक राज्य बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय करेगा।

विमर्श
अवधेश कुमार

विकास पर भारी घाटी का जनादेश

जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग पूर्व अनुमानों के अनुरूप ही हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर अभियान तक यह साफ हो गया था कि जम्मू क्षेत्र में भाजपा प्रभावी है लेकिन कश्मीर में उसका जनाधार नहीं बढ़ा है। दूसरी ओर नेशनल कांफ्रेंस का जनाधार कश्मीर के साथ जम्मू क्षेत्र में भी है। हालांकि जम्मू की 43 में से भाजपा को 29 सीटें मिलने से उनके समर्थकों को निराशा हो सकती है। सच्चाई व जमीनी वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। वैसे तीन-चार सीट भाजपा काफी कम अंतर से हारी है। चूंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने एवं संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था इसलिए भी इसके परिणाम को देखने के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। भाजपा समर्थकों एवं कश्मीर की क्षेत्रिय पार्टियों के स्वाभाविक विरोधियों के अंदर निराशा इसलिए है कि वहां के लोग ही खुलकर बता रहे थे कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जितना विकास किया, उसकी पहले कल्पना नहीं थी। आतंकवाद के भय से सहमे रहने वाले दूरस्थ इलाकों तक भी विकास पहुंचा।

स्थानीय निकायों के चुनाव से निचले स्तर पर विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ी, शिक्षण संस्थान सुचारू रूप से चलने लगे, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद आदि सामान्य गतिविधियों की तरह हो गए जिनकी पिछले तीन दशक से कल्पना भी नहीं थी। यह सच है कि भाजपा ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और 2021 में पंचों एवं सरपंचों के चुनाव कराए। बावजूद कश्मीर में उसका खाता न खुलना चिंता का विषय होना चाहिए। इसे अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। भाजपा ने जम्मू में 41 तथा कश्मीर में 19 सीटों यानी कुल 60 स्थानों पर चुनाव लड़ा। पार्टी ने पहली बार 23 मुस्लिम प्रत्याशी दिए। दूसरी ओर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का गठबंधन में कांग्रेस 32 और नेकां ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा 5 सीटों पर दोनों के बीच मुकाबला था। जम्मू क्षेत्र के बारे में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वहां एक तिहाई आबादी मुस्लिम है। केवल चार जिले जम्मू, कठुआ, सांभा और उधमपुर में हिंदू बहुमत में हैं, चिनाब घाटी के तीनों जिले मिले-जुले हैं तथा पीर पंजाल के पूंछ और डोडा मुस्लिम बहुल हैं। जम्मू कश्मीर आतंकवादी, अलगाववादी हिंसा की अस्थिर स्थिति में लंबे समय से रहा। उसमें 370 हटाने के बाद परिस्थितियों को एकाएक सामान्य करना तथा प्रशासनिक व राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से लोगों तक पहुंचकर उन्हें समझा पाना असंभव था। भाजपा घाटी में कहीं थी नहीं और मुसलमानों के बीच उसे लेकर हमेशा गलतफहमी बनाई गई।

जम्मू-कश्मीर को मुस्लिम पहचान से जोड़ने का षड्यंत्र आजादी के पूर्व से आरंभ हुआ और केन्द्रीय सत्ता ने नीतियों और व्यवहार से उस मानसिकता को सशक्त किया। भाजपा स्थापित की गई भारत की अखंडता सिद्धांत के विपरीत धारणा के विरुद्ध रही है। इस विचार की सहयात्री नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस वहां की स्थापित पार्टियां रहीं हैं। बाद में पीडीपी भी मुख्य पार्टी बन गई और इनका जनाधार दोनों क्षेत्रों में रहा है। उनको काट

पाना आसान नहीं था। हालांकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से समाप्त पार्टी साबित हुई क्योंकि उसे 5 सीटें घाटी से मिलीं जिनके कारण नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन है और एक सीट केवल पीर पंजाल से। बाकी जम्मू में वह कहीं भी जनाधार साबित नहीं कर पाई। भाजपा को अकेले सबसे ज्यादा 25.64% मत मिले हैं। इसके समानांतर नेशनल कांफ्रेंस का मत 23.43 प्रतिशत तथा कांग्रेस का 11.27 प्रतिशत है। कांग्रेस का अपना एक अलग जनाधार जम्मू और घाटी दोनों क्षेत्रों में रहा है जो इस चुनाव में लगभग खत्म है। अगर नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन नहीं होता तो संभव था उसे सीटें नहीं आती। पीडीपी केवल 8.7% मत पाने वाली पार्टी रह गई और उसके बाद एकमात्र एनपी है जिसे 1 प्रतिशत से अधिक मत मिले। भाजपा का यह आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि यह चिंता का विषय है कि धारा 370 हटाने के बाद आम लोग भी मीडिया में बोल रहे थे कि उन्हें शासन में भागीदारी का अवसर मिला, शैक्षिक- सांस्कृतिक -खेलकूद आदि गतिविधियां बढ़ी, विकास के जबरदस्त काम हुए , लेकिन ये भाजपा को मत देने के लिए तैयार नहीं थे। कश्मीर की मुस्लिम पहचान की विरोधी पार्टी की छवि के साथ पूरे देश में इस समय मुसलमानों की सामूहिक प्रवृत्ति भाजपा के विरुद्ध मतदान की है। इसी कारण सभी मतदाताओं ने लगभग रणनीतिक मतदान किया। विकल्प के रूप में नेशनल कांफ्रेंस ही मजबूत दिखा रही थी। इसीलिए प्रभावी निर्दलीय और शेष दल वहां नकारे गये। पीडीपी केवल तीन सीटों तक सिमट गई और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बीजबेहरा जैसे परंपरागत क्षेत्र से चुनाव हार गई। पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन कुपवाड़ा से हारे और हीदवाड़ा से भी केवल 662 मतों से जीते। राशिद इंजीनियर का न्यायालय के आदेश पर जेल से बाहर जाकर प्रचार करना काम नहीं आया।

जमात ए इस्लामी से लेकर हुर्रियत से जुड़े उम्मीदवारों को भी लोगों ने समर्थन नहीं दिया क्योंकि उनके सामने वोट बंटने और भाजपा के मजबूत होने का खतरा दिखाया जा रहा था। मुस्लिम बहुल एक क्षेत्र जम्मू के किश्तवाड़ से भाजपा की शगुन परिहार की जीत थी जिन्होंने नेशनल कांफ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू को 521 मतों से हराया। भाजपा ने पीर पंजाल के क्षेत्र में गुर्जरों और पहाड़ियों के लिए भले तीन दशक पुरानी अनुसूचित जनजाति के दर्जे को पूरा किया, आरक्षण दिया लेकिन वहां की आठ में से एक सीट नहीं जीत पाई। नेशनल कांफ्रेंस सहित सभी पार्टियों ने अलगाववादी वायदे किए थे जिनमें धारा 370 की वापसी, 1954 के पहले की स्थिति की बहाली, राजनीतिक कैदियों की रिहाई ,उन सारे कानूनों को समाप्त करना जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को प्रभावित करते हैं, भूस्वामित्व संबंधी बदले कानूनों का अंत, पाकिस्तान के साथ बातचीत आदि शामिल थे। नेशनल कांफ्रेंस ने तो शंकराचार्य पर्वत को तख्त ए सुलेमान तथा हरी पर्वत को कोहे मारन तक में बदलने की घोषणा कर दी। इस तरह की कट्टर मजहबी घोषणाओं का भी वहां असर हुआ। भाजपा ने इसके विपरीत विकास, भविष्य के निर्माण, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद आदि को खत्म कर सच्चे लोकतंत्र कायम रखने जैसी सकारात्मक घोषणाएं कीं। अब नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन रही है तो देखना होगा कि अपने वादों को लेकर वो कितना आगे बढ़ते हैं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के साथ संबंध बनाकर काम करने की बात की है जिनमें अभी तक किसी तरह की आक्रामकता या विरोध की भाषा नहीं है। संभव है यह बयान रणनीतिक भी हो। इसलिए उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के रीति-नीति, व्यवहार तथा भविष्य के राजनीतिक समीकरणों का स्पष्ट स्वरूप आने में थोड़ा समय लगेगा।

(लेखक राजनीतिक समीक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

दो टूक
विकेश कुमार बडोला

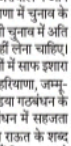

जम्मू-कश्मीर में जनता की प्रतिक्रिया निराश करने वाली

हरियाणा में बहुमत के लिए 46 से दो अधिक यानि 48 निर्वाचन-क्षेत्रों पर विजयी होकर भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर तृतीयावधि के लिए अपना शासन स्थापित करने की दिशा में पग बढ़ा दिया है। दो प्रकार के राज्य-नीतिक ध्रुवों में बंटी देश की लोकतांत्रिक यात्रा में भाजपा व इसके समर्थकों के लिए यह शुभ पड़ाव हो सकता है, किंतु जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय विभिन्न कोणों से भारतीय लोकतांत्रिक चुनावी-धारणा को ही संदिग्ध बनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत उक्त केंद्र शासित राज्य के लिए वर्षों से लागू धारा 370 और 35ए के हटने के बाद राज्य में सामाजिक-राजनीतिक वातावरण शेष भारतीय प्रांतों की तरह बनने-होने की आशा की गई थी। केंद्र में शासनरत भाजपा ने उक्त धाराओं को हटाकर राज्य के लिए जितने भी लोकतांत्रिक प्रयास किए, सभी संतुलित व विकासपरक थे। किंतु इस विधानसभा चुनाव में प्रांत की जनता ने जो प्रतिक्रिया दी है, वह निराश करने वाली है। भले ही भाजपा इसे बढ़े हुए मत प्रतिशत, पहले से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विजयी होने अथवा राज्य में 29 निर्वाचन-क्षेत्रों में विजित होने के प्रतीक को अपने लिए प्रेरणादायी बता रही है, किंतु वास्तव में भाजपा के केंद्रीय शासन ने गत चौदह वर्षों में जितने अपूर्व कार्य राज्य में किए थे, उसके बदले में वह राजनीतिक व लोकतांत्रिक प्राप्ति कुछ भी नहीं है। यह यही सिद्ध करती है कि राज्य में अभी भी उन्हीं लोकतांत्रिक दलों, उनके नेताओं और उनके समर्थकों का बोलबाला है, जो भारत की सुविधाओं पर भारत के ही विरुद्ध अनेक षड्यंत्रों में लिप्त रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और मुस्लिमवाद का प्रसारण स्थानीय जनपीड़ा की प्रतिक्रिया नहीं, अपितु पड़ोसी मुल्क पाक की साजिश पर होने वाला घात-प्रतिघात रहा है। ऐसा घातक-प्रतिघातक वातावरण राज्य में स्थापित, विकसित और प्रसारित हुआ तो क्योंकर, इस बिंदु पर गहराई से विचार किए बिना ही केंद्रीय शासन ने वहां पुनः मतदान करवाने का निर्णय लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है। इस राष्ट्र की, इसके नेताओं और यहां की तटस्थ जनता की समस्या यह है कि ये सभी इकाइयां समस्या के मूल कारण को स्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं करते। इस कारणवश नेताओं, अधिकारियों व स्वार्थी जनता को तात्कालिक लाभ प्राप्त हो जाता है किंतु राष्ट्र की मौलिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। जम्मू कश्मीर के संबंध में भी उक्त इकाइयों का यह विचार ही गहराई तक व्यर्थ है कि वहां की जनता भारतीय संविधान के अनुरूप शासन-प्रशासन की गतिविधियों में विश्वास रखती है। सर्वप्रथम उक्त इकाइयों को स्पष्ट करना होगा कि जनता के स्वरूप में वहां अधिसंख्या मुस्लिमों की है, जो किसी भी दृष्टि से भारतीय संविधान, भारतीय शासन-प्रशासन और हिन्दू जन-गण-मन को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करती। ये जनसंख्या भाजपा को उसके विकास कार्यों, सुरक्षा, आतंक उन्मूलन नीतियों व कार्यों, इत्यादि सकारात्मक राष्ट्रीय कार्यों के लिए राजनीतिक समर्थन देगी, यह विचार ही भाजपा का थोथरा है। भले ही कांग्रेस समेत अधिकतर राजनीतिक दल, इनके संरक्षण वाले मीडिया हाउस, बुद्धिजीवी व समर्थक इस बात से भिन्न होकर भी अनभिज्ञ बनने की कुचेष्टा करने में लिप्त हैं, किंतु सच यही है। ऐसे में लोकतंत्र के नाम पर हिंदुओं को भाजपा से आशा थी कि वह 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद हिंदू हितों को ध्यान में रखकर राजनीतक कर्मदान करती। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। भाजपा के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास की धारणा अंगीकार कर ली। पांच वर्ष बाद 2019 में पुनः पहले से अधिक प्रचंड बहुमत के साथ सत्तारूढ़ होने पर हिंदुओं की आशा पुनः बिखरी, जब प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास में सबका विश्वास की उक्ति और जोड़ दी। हिंदू विचित्र मनःस्थिति से गुजरे कि जो हिंदू बहुमत के साथ प्रधानमंत्री को सत्ता की शक्ति, संसाधन, उपलब्ध करा रहे हैं, उनका उपयोग वे अहिंदू यानी मुस्लिमों को गणतांत्रिक रूप में प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। मुस्लिमों की मंशा से अनभिज्ञ रहने की सुस्त इच्छा के कारण आज जम्मू कश्मीर में भाजपा के हाथ से राष्ट्रपति शासन की समयावधि में अर्जित शासकीय-प्रशासकीय उपलब्धियां रेत बनकर झड़ चुकी हैं। नेशनल कांग्रेस व कांग्रेस के गठबंधन में वर्षों पूर्व जैसी अराजकता प्रांत में मची थी, फिर उसकी आशंका मंडराने लगी है। नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला चुनाव में अपने दल को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

वार्ता से निकल सकता है हर समस्या का हल

संकलित
दर्शन

वार्ता से प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार है। जब मन में संदेह उपजे, हृदय अविश्वास से घिर जाए, मस्तिष्क में विचार न ठहरे, तब वार्ता से ही रास्ता निकलेगा। कोई भी विवाद हो, कैसी भी समस्या हो, फिर भी वार्ता से हल निकल सकता है। संबंधों में कितना भी ठहराव क्यों न आ जाए, लेकिन वार्ता के ताप से रिश्तों पर जमा बर्फ भी पिघल जाती है। वार्ता में शिथिलता के लिए केवल अहंकार दोषी होता है। किसी भी विध्वंस का कारण अंहकार ही रहा है। विश्व शांति की अवधारणा परस्पर संवाद पर ही टिकी है। संवादहीनता से कूटनीति और राजनीति अकेली पड़ सकती है। बातचीत चलती रहे तो विकल्प निकलने की संभावना बढ़ जाती है। चर्चाओं में तर्क, सुझाव और मतों का विभाजन होता रहता है। यह अनवरत प्रक्रिया है। जनता के मध्य निरंतर जनमत पर चर्चा चलती रहती है। लोक चर्चा और लोकमत से संसार की बड़ी समस्याओं पर सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकते है। चर्चा या वार्ता को प्रोत्साहित करना उचित है। संवादहीनता को हतोत्साहित करना चाहिए। सभी द्वार भले ही बंद हो जाएं, लेकिन बातचीत का द्वार सदैव खुला रहे। लोग कहते हैं कि पैसों का काम पैसों से ही चलता है, बातों से नहीं। यह बात सच है कि बातों से कोई काम नहीं होता, काम तो काम करने से ही सकता है, लेकिन काम तभी हो सकता है, जब उस काम से पहले कोई विचार स्थिर हो। विचार स्थिर होगा तो उससे संबंधित बात पूरी हो सकेगी और बात होगी तो काम का आदेश होगा।

ईर्ष्यालु किसी को सुखी-संपन्न नहीं देख सकता

संकलित
प्रेरणा

एक महिला कुबड़ी थी जिसकी वजह से वह झुककर चलती थी। सभी लोग उसका उपहास उड़ाते थे। बच्चे तो जब-तब उसे 'कुबड़ी-कुबड़ी' कहकर परेशान करते रहते थे। एक दिन वह कहीं जा रही थी कि सहसा रास्ते में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद ने उस महिला पर तरस खाते हुए कहा, 'आओ बहन! मेरे पास आओ। मैं अपने योगबल से तुम्हारा कूबड़ ठीक कर दूंगा।' महिला बोली, 'भगवान! आप अंतर्यामी हैं। आप तो जानते ही है कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मुझे सदैव यह कहकर चिढ़ाते रहते हैं कि, देखो वह कुबड़ी जा रही है। यदि आप मुझ पर मेहरबानी कर ही रहे हैं तो मेरे कूबड़ की फिक्र मत कीजिए। आप बस इतना कर दीजिए कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, उन सबके भी कूबड़ निकल आए।' नारद जी ने उस महिला का उत्तर सुना तो हक्के-बक्के रह गए। आश्चर्यचकित होकर बोले, 'बहन, दूसरों के कूबड़ निकल आने से तुम्हें क्या मिलेगा!' बुढ़िया बोली, 'मैं उन्हें भी अपनी तरह चलते और दूसरों द्वारा उपहास होते देखूंगी तो मन को शांति मिलेगी।' नारद जी सोचने लगे यह महिला चाहती तो मेरी कृपा से अपना कूबड़ ठीक करा सकती थी। लेकिन उसने हाथ आए अवसर को दूसरों के नुकसान के रूप में ही भुनाने की कामना की। ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रकृति यही होती है कि वह दूसरों को सुखी-संपन्न देखकर उनके जैसा उन्नत, संपन्न और सुखी होने की प्रेरणा ग्रहण नहीं करता, बल्कि सुखी लोगों को दुखी करने और नीचे गिराने का प्रयास करता है।

अंतर्मन

आज की पाती

दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार हो

हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कुछ दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया। इनमें लगभग 53 दवाओं की गुणवत्ता को फेल बताया, लेकिन उम्मीद है कि संबंधित दवाओं की कंपनियां इन दवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। कुछ समय पहले हमारे देश की एक कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप उज्बेकिस्तान में वहां के कुछ बच्चों की जान के दुश्मन बन गए थे। हालांकि इसका कारण यह बताया गया कि यह सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को दिया गया। कोई भी दवा कंपनी जब कोई दवा बनाती है तो वो कंपनी उस दवाई की गुणवत्ता की जांच उचित तरीकों से करती है, लेकिन लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवा ले लें, यह गलत है। फिर भी दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। *-महेंद्र विश्वकर्मा, धमतरी*

ट्रेंड

विकसित भारत का संकल्प

हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी ऐतिहासिक जीत के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

लोकतंत्र की जीत

जम्मू-कश्मीर के लोगों का तहेदिल से शुक्रिया, प्रदेश में लोकतांत्रिक स्थापना की जीत है। हम हरियाणा के आगामी नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। लड़ाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे।
- राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

कांशीराम को श्रद्धांजलि

बसपा के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम को उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत-शत नमन व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित। उन्हें विनम्र स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले पार्टी के लोगों व अनुयायियों का तहेदिल से आभार।
-मायावती, बसपा प्रमुख

तहेदिल से धन्यवाद

राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर हम गौरवान्वित है, डरपा पुरस्कृत से उत्साह हुआ है। इस सम्मान को समाज सेवा के लिए तहेदिल से धन्यवाद। 'पंचायत' जिसकी आपबीती कहानी है उसको ही हमारी भी है। हम स्टैंड अलोन हैं।
-जगन शेट्टी, फिल्म निर्देशक

करंट अफेयर

ब्रिटेन ने 'नगा मानव खोपड़ी' की बिक्री रोकी

ब्रिटेन के एक नीलामी गृह ने बुधवार को अपने 'नगा मानव खोपड़ी' को अपने 'लाइव ऑनलाइन बिक्री' की सूची से हटा लिया है। नीलामी गृह ने इस मुद्दे पर भारत के विरोध के बाद यह कदम उठाया। ऑक्सफोर्डशायर के टेस्टवर्थ में स्थॉन नीलामी गृह के पास उसके 'द क्यूरियस वर्ल्डवर्ट सेल, एंटीक्वेरियन बुक्स, मैनुस्क्रिप्ट्स एंड पेंटिंग्स' के तहत दुनियाभर से प्राप्त खोपड़ियों और अन्य अवशेषों का संग्रह है। 'एक शताब्दी की सीमा युक्त नगा मानव मानव खोपड़ी, नगा जनजाति' को बिक्री के लिए सूची में लॉट नंबर 64 पर रखा गया था। इसकी बिक्री को लेकर नगालैंड के मुख्यमंत्री नेयपु रियो ने विरोध जताया था और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस बिक्री को रोकने में दखल की मांग की थी। रियो ने अपने पत्र में लिखा, 'ब्रिटेन में नगा मानव खोपड़ी की नीलामी के प्रस्ताव की खबर ने सभी वर्ग के लोगों पर नकारात्मक असर डाला है क्योंकि हमारे लोगों के लिए यह बेहद भावनात्मक और पवित्र मामला है। दिवंगत लोगों के अवशेषों को सर्वोच्च सम्मान और आदर देने की हमारे लोगों की पारंपरिक प्रथा रही है।' फोरम फॉर नगा रिकॉन्सिलीएशन (एफएनआर) द्वारा इस मामले को लेकर चिंता जताने के बाद रियो ने विदेश मंत्री से यह मामला लंदन में भारतीय उच्चायोग के समक्ष उठाने का अनुरोध किया।

ऑफ बीट

रूक-रूक कर उपवास से बचा जा सकता है अल्जाइमर से

जैसे-जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, अल्जाइमर रोग तेजी से आम होता जा रहा है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे प्रचलित रूप है।

डिमेंशिया एक बीमारी है जिसका उपयोग उम्र के साथ मस्तिष्क की कार्यक्षमता में गिरावट से जुड़े लक्षणों की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लक्षणों में स्मृति हानि, संचार कठिनाइयाँ, समस्या-समाधान संघर्ष और व्यक्तित्व या व्यवहार परिवर्तन शामिल हैं। हाल के वर्षों में, अल्जाइमर रोग जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों पर शोध के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक मस्तिष्क में हानिकारक प्रोटीन का संचय रहा है। विशेष रूप से अमाइलॉइड। अमाइलॉइड अल्जाइमर रोग में अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है क्योंकि इसका बढ़ना इस स्थिति के विकास से जुड़ा है। रोग प्रक्रिया में इसकी भागीदारी को समझना हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने और रोग के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अमाइलॉइड के संचय से प्लाक का निर्माण हो सकता है। ये प्लाक मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संचार में बाधा डाल सकते हैं। यह अंततः संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर रोग से जुड़े अन्य लक्षणों में योगदान देता है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
पहले मन का कार्य तय करो और फिर उसे पूरे मन से करो

कांग्रेस का रुदन

हरियाणा में अपनी गलतियों से जीती बाजी हारने वाली कांग्रेस ने जिस तरह यह कहा कि उसे चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं और उसके नेता मतगणना में कथित गड़बड़ी का रोना रोते हुए जिस प्रकार चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गए, उससे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत ही चरितार्थ होती दिख रही है। भले ही चुनाव आयोग ने हरियाणा के नतीजों पर जयराम रमेश और अन्य कांग्रेस नेताओं के अनर्गल बयानों को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे को कड़ी चिट्ठी लिखकर यह कहा हो कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन लगता नहीं कि इससे कांग्रेस की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। इसके आसार इसलिए नहीं, क्योंकि उसके नेता मनमाफिक नतीजे न आने पर मनगढ़ंत आरोप लगाने में माहिर हो चुके हैं। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनावों के समय जयराम रमेश ने ही यह सनसनीखेज आरोप उछाला था कि केंद्रीय गृहमंत्री विभिन्न जिलों के डीएम को फोन कर धमका रहे हैं। जब उनसे इसके प्रमाण देने को कहा गया था तो वह बगलें झांकने लगे थे। यदि चुनाव आयोग ने तभी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की होती तो शायद वह हरियाणा के नतीजों पर नया झूठ नहीं गढ़ते।

हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस का व्यवहार यही बताता है कि उसे न तो जीत पचती है और न ही हार हजम होती है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने पर वह ऐसे पेश आ रही थी, जैसे उसने बहुमत हासिल कर लिया है। अब हरियाणा में भाजपा को तीसरी बार सत्ता हासिल करने का मौका देने वाली कांग्रेस अपनी गलतियों पर गौर करने के बजाय चुनाव आयोग पर दोष मढ़कर अपनी खीझ उतार रही है। ऐसा करके वह भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के साथ लोगों को गुमराह ही नहीं कर रही है, बल्कि उन सवालों से मुंह भी चुरा रही है, जो हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद उसके समक्ष उभर आए हैं। इनमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर उसने उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जरूरत से ज्यादा महत्व क्यों दिया, जिन्होंने कुमारी सैलजा समेत अन्य नेताओं को किनारे किया, आम आदमी पार्टी से समझौते पर अड़ंगा लगाया और संगठन का निर्माण नहीं होने दिया? हरियाणा में दस वर्ष से सत्ता में होने के चलते भाजपा के खिलाफ एक सत्तारोधी रुझान तैयार हो गया था। यह स्वाभाविक ही था, लेकिन कांग्रेस ने उसका लाभ उठाने के लिए केवल दुष्प्रचार को अपना हथियार बनाना बेहतर समझा। यह मानने के भी अच्छे-भले कारण हैं कि कांग्रेस यह फर्जी माहौल बनाने वालों के झांसे में आ गई कि वह बहुत आसानी से हरियाणा में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। उसे पता होना चाहिए कि अति हर चीज की बुरी होती है और इसमें आत्मविश्वास भी शामिल है। यदि कांग्रेस ने अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत नहीं छोड़ी तो आगे उसका और नुकसान होगा।

विशेष निगरानी जरूरी

चारों ओर दुर्गापूजा का उल्लास है। आम दिनों की अपेक्षा सड़क और बाजार में अधिक संख्या में लोग दिखने लगे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष चुनौती खड़ी हो जाती है। जरूरी है कि शासन-प्रशासन ऐसे कदम उठाए, जिससे सबकुछ शांतिपूर्वक निपट जाए। दरअसल सोमवार को झारखंड के धनबाद में छेड़खानी की एक घटना हुई, जिसमें युवती ने हिम्मत दिखाई और मनचलों को खदेड़ कर पकड़ा। पूजा के दौरान ऐसी और घटनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। दशहरा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के अपने-अपने घर जाने तथा पूजा पंडालों के भ्रमण से गली-मोहल्ले सुनसान पड़ जाते हैं। अपराधी तत्व इसे अवसर मानकर अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते हैं। अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन को इसका भान है और उसने संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल निगरानी कार्य में होगा। पंडालों के आसपास सादे लिबास में पुलिसकर्मी तो रहेंगे ही, विक्कल रिस्पांस टीम भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। लोक शिकायतों के निवारण के टोल फ्री नंबर जारी किए जा रहे हैं, जिस नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी अवांछनीय स्थिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जरूरी है कि शासन-प्रशासन के साथ-साथ पूजा समितियां भी इस मामले में तत्पर रहें और अधिकाधिक संख्या में स्वयंसेवकों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपें। ऐसे अवसरों पर शांति समिति के साथ-साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता को भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है।

> पूजा पंडालों के भ्रमण से गली-मोहल्ले सुनसान पड़ जाते हैं। अपराधी तत्व इसे अवसर मानकर अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते हैं

एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहानी कहता सिनेमा

अश्विनी वैष्णव

भारतीय सिनेमा ऐसी कहानियां कह रहा है, जो न केवल हमारी विविधता को दर्शाती हैं, बल्कि साझा भविष्य की कल्पना भी करती हैं

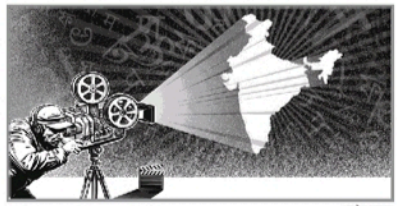

अवधेश राजपूत

कालजयी फिल्मकार सत्यजीत रे ने लोगों को एकसूत्र में बांधने की सिनेमा की ताकत के सार को पकड़ते हुए कहा था, 'सिनेमा एक सार्वभौमिक भाषा बोलता है।' अपनी व्यापक भाषाएं एवं सांस्कृतिक विविधता के साथ भारतीय सिनेमा देश के हर कोने के लोगों को एक साथ लाता है। चाहे वह तमिल फिल्म हो या हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुद्ध मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटते और हमें 'सभी मतभेदों के बावजूद हम एक हैं' की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। भारतीय सिनेमा की सार्वभौमिकता क्षेत्रीय एवं भाषाई सीमाओं के परे जाने की इसकी क्षमता में निहित है, जो इसे राष्ट्रीय एकता की एक मजबूत शक्ति बनाती है। राज कपूर की 'श्री 420' जैसी शास्त्रीय फिल्म से लेकर मणिरत्नम की 'रोजा' तक भारतीय फिल्में भावनाओं की भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। 'श्री 420' की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं 'रोजा' को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एमएस सथ्यू की 'गरम हवा' और बिमल राय की 'दो बीघा जमीन' जैसी फिल्में यह याद दिलाती हैं कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की कहानियां किसी सीमा से बंधी नहीं हैं और यह साबित करती हैं कि सिनेमा सही अर्थों में एक राष्ट्रीय बंधनकारी शक्ति है।

यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है, जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, निर्देशकों और अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह चकाचौंध कर देने वाला कार्यक्रम नहीं है, जो आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किया जाता है। यह कहानी प्रस्तुत करने वालों की प्रतिभा की गरिमापूर्ण स्वीकृति है। यह भारत की भाषाओं और बोलियों की बहुरंगी विविधता की भी गरिमामयी पुष्टि है, जो इस महान राष्ट्र की एकता का जादुई ताना-बाना बुनती है और लगभग डेढ़ अरब लोगों को सूत्रबद्ध करती है, जो सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विशिष्टता इससे स्पष्ट होती है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाने वालों में तिवा भाषा में बनी फिल्म 'सिकीसला' (काश सिर्फ पेड़ ही बोल पाते) शामिल है। यह तिवा लोगों की भाषा है, जो तिब्बती-बर्मी जातीय समूह के सदस्य हैं और जो पूर्वोत्तर भारत के के साथ बांग्लादेश एवं म्यांमार में रहते हैं।

70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए फीचर फिल्म की श्रेणी में 32 विभिन्न भाषाओं की 309 फिल्में और गैर-फीचर श्रेणी में 17 भाषाओं की 128 फिल्में प्राप्त हुईं। फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार चार भारतीय भाषाओं की फिल्मों ने जीता। इनमें एक फिल्म हरियाणवी में थी। इस श्रेणी में हिंदी और तमिल भाषा की पांच-पांच फिल्मों ने रजत कमल पुरस्कार जीता। मलयालम, गुजराती, कन्नड़, हरियाणवी और बांग्ला भाषा की फिल्मों ने भी पुरस्कार जीता। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की दस फिल्मों को भी रजत कमल जीता। हिंदी और उर्दू की एक फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म श्रेणी का स्वर्ण कमल पुरस्कार जीता।

भाषाई राजनीति के शून्यवादी (नाइलीस्ट) चाहे जो तर्क दें, लेकिन तथ्य यह है कि भाषाई राज्यों के साथ भारतीय गणराज्य के निर्माण के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद अतीत की बाधएं पिछले कुछ दशकों के दौरान काफी हद तक समाप्त हो गई हैं। इससे इन्कार नहीं कि बालीवुड की फिल्मों ने हिंदी को व्यापक रूप से स्वीकार्य बना दिया है, लेकिन यह भारतीय समाज के विविध पहलुओं पर फिल्मों का केवल एक बड़ा प्रभाव है। इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की विविधता में एकता की एक गहरी एवं स्थायी भावना को बढ़ावा देते हुए लोगों को अन्य भाषाई समूहों एवं पहचानों के बारे में जागरूक करना है। भारतीय सिनेमा अकल्पनीय रूप से उन रचनाकारों के व्यापक समुदाय की कलाओं को प्रदर्शित करता है, जो विविध प्रकार की संस्कृतियों के बीच सार्वभौमिक मान्यताओं पर आधारित जादुई मनोरंजन का सृजन करने के लिए अपनी प्रतिभा को एक साथ लाते हैं। कोई भी भारतीय कहानी उन सार्वभौमिक तत्वों के बिना कभी नहीं कही गई, जो मूल्यों और नैतिकता पर जोर न देती हो। अब तक की दो सबसे बड़ी कहानियां रामायण और महाभारत इसकी पुष्टि करती हैं। हमारे सिनेमा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू वह साहसता है, जिसके साथ फिल्मकार सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विघटन के मूल में मौजूद विभाजनकारी चिह्नों को मिटा देते हैं। यही भारत की कहानी कहने की कला की अनूठी ताकत है। तेलुगु फिल्म 'आरआरआर' का गान 'नाटू नाटू', जिसने आस्कर और गोल्डन ग्लोब जीता है, भाषा, जातीयता और राष्ट्रीयता के बंधनों से परे जाकर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सुसरहित साबित हुआ।

भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर ऊंचा उठाने के लिए सरकार तीन मुख्य स्तंभों पर काम कर रही है: प्रतिभा की एक मजबूत पाइपलाइन विकसित करना, फिल्मकारों के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और कहानीकारों को सशक्त बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना। सरकार ने हाल में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइसीटी) की स्थापना का प्लान किया, जो रचनात्मकता को प्रोत्साहन की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय सिनेमा नवीनतम तकनीकों, अप्रतिम अनुभवों और संवादात्मक मनोरंजन को अपनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में मजबूत शक्ति बना रहे।

जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के संदर्भ में सिनेमा की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में भारतीय सिनेमा लगातार नवप्रवर्तन करते हुए अपने क्षितिज का विस्तार कर रहा है और ऐसी कहानियां कह रहा है, जो हमारी विविधता को दर्शाने के साथ एक साझा भविष्य की कल्पना भी करती हैं। भारतीय फिल्मकार यह सुनिश्चित करते हुए कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं कि सिनेमा एक सूत्रबद्ध एवं दूरदर्शी भारत में एकता और प्रगति का एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बना रहे।

(लेखक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं)

response@jagran.com

एक्ट ईस्ट को साकार करता भारत

श्रीराम चौलिया

जिस क्षेत्र में कभी चीन, अमेरिका को ही प्रमुख और निर्णायक शक्ति माना जाता था, उसमें अब भारत की साख बढ़ी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस जा रहे हैं। वैसे तो प्रति वर्ष इन दोनों सम्मेलनों में प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति आम है, लेकिन इस साल भारत की एक्ट ईस्ट नीति यानी कि पूर्वी छोर को साधने की पहल के दस वर्ष पूरे होने के चलते यह पड़ाव विशेष मायने रखता है। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने 1992 से लागू लुक ईस्ट नीति को गतिशील और व्यापक बनाने के उद्देश्य से उसका नामांतरण एक्ट ईस्ट के रूप में किया। पिछले एक दशक के घटनाक्रम के आधार पर कहा जा सकता है कि यह कोई सतही बदलाव नहीं था। एक्ट ईस्ट के तहत भारत ने व्यापार, सैन्य और सांस्कृतिक कार्यक्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया (आसियान के दस देशों), उत्तर पूर्वी एशिया (जापान, कोरिया और मंगोलिया) तथा ओशनिया (आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक द्वीपीय देश) के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाया है। इसी दौरान भारत ने अमेरिका के साथ अपनी सामरिक साझेदारी भी मजबूत की है, जिसका सीधा सरोकार पूर्वी एशिया के आर्थिक और भूराजनीतिक परिदृश्य से है।

एक्ट ईस्ट के युग में भारत पूर्वी एशिया में गहरी पैठ बना चुका है। भारत कभी केवल दक्षिण एशियाई देश कहलाता था, लेकिन अब पूर्वी एशिया की नियति तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जिस इलाके में कभी केवल चीन और अमेरिका की ही प्रमुख और निर्णायक शक्ति माना जाता था, आज वहां भारत की साख बढ़ी है और वह आगे और भी ज्यादा प्रभावी होने वाली है। आस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान ने 2024 के एशिया शक्ति सूचकांक में अमेरिका और चीन के बाद भारत को सबसे शक्तिशाली देश का दर्जा दिया है। यह बात पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों से छिपी नहीं है कि उनके क्षेत्र में संतुलन कायम करने के लिए भारत अहम खिलाड़ी है। 2004 में सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग ने कहा था कि आसियान अगर हवाई जहाज का ढांचा है तो चीन उसका एक पंख है और भारत दूसरा पंख और इन दोनों पंखों के बगैर उड़ान नहीं भरी जा सकती।

आज एक्ट ईस्ट के अंतर्गत भारत-आसियान व्यापार 2014 की तुलना में दोगुना होकर 131 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया है। आसियान ने भारत को सामरिक साझेदार से ऊपर व्यापक सामरिक साझेदार का भी दर्जा दिया है। हालांकि पूर्वी एशियाई देशों को उम्मीद थी कि 2022 में हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी आरसेप समझौते में भारत भी शामिल होगा और उससे उन्हें भारत के विशाल बाजार में अधिक अवसर मिलेंगे, लेकिन आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा और उनके यहां चीन के भारी निवेश के कारण भारत ने उस समझौते से परहेज किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन से प्रतिस्पर्धा तेज करने के मकसद से 2022 में ही इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा (आइपीईएफ) बनाया था, जिसमें भारत संस्थापक सदस्य बना। आरसेप को ठुकराने की क्षतिपूर्ति आइपीईएफ द्वारा करना भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौती है।

अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी पूर्वी एशिया को परस्पर आर्थिक फायदे की स्थिति में लाने के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा में भी इजाफा करेगी। इस क्षेत्र में अमेरिका की अव्वल रक्षा सहभागी और चीन को प्राथमिक आर्थिक सहभागी माना गया है, पर चीन ने बीते दशक में विस्तारवादी व्यवहार और धमक से अपने से छोटे देशों को दहशत में डाल रखा है। आए दिन फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान और जापान पर चीन क्षेत्रीय दावा करता है और सैन्य बल से उन पर हावी होने की चेष्टा करता है। ऐसे में भारत अकेले पूर्वी एशिया जैसे दूरस्थ एवं विस्तारित क्षेत्र में चीन का प्रतिरोध नहीं कर सकता। भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने क्वाड समूह को 2017 से पुनः सक्रिय किया है। क्वाड सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य नियम और अंतरराष्ट्रीय विधि आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था बनाना है। सफ शब्दों में क्वाड पूर्वी एशिया के चीन-केंद्रित होने के विरुद्ध खड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के मध्य घोषित आकस गठबंधन और अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और फिलीपींस के मध्य स्वब्राड का भी भारत ने समर्थन किया है। इन नए समूहों के साथ मिल-जुलकर भूराजनीतिक संतुलन बनाने में भारत का ही हित है। हालांकि ऐसे गुटों के साथ सहयोग का यह मतलब नहीं है कि भारत केवल अमेरिका और उसके मित्रों पर ही पूरी तरह निर्भर रहेगा।

लुक ईस्ट की तुलना में एक्ट ईस्ट नीति में भारत ने रक्षा के मुद्दे को अधिक उभारा है और हिंद-प्रशांत में नए त्रिकोणीय समीकरणों का सृजन किया है। इसी के मद्देनजर भारत-इंडोनेशिया-आस्ट्रेलिया, भारत-फ्रांस-आस्ट्रेलिया और भारत-सिंगापुर-थाइलैंड जैसे उपयोगी संयोजन कुछ वर्षों से क्रियाशील हुए हैं। इसी कड़ी में अगर भारत-जापान-दक्षिण कोरिया और भारत-वियतनाम-इंडोनेशिया के भी त्रिकोणीय गुट बन जाएं तो भारत न सिर्फ हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदाता के रूप में रहेगा, बल्कि समूचे हिंद-प्रशांत का नेतृत्व भी कर सकेगा। देखें तो एक्ट ईस्ट के दस वर्षों के दौरान एशिया-प्रशांत हिंद-प्रशांत में तब्दील हुआ है और इस परिवर्तन के प्रति चीन के अलावा अधिकतर देश सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अब हिंद-प्रशांत की अवधारणा को सफल बनाने के लिए भारत को अपनी हिंद-प्रशांत सागर पहल (आइपीओआइ) और अन्य देशों के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोणों के बीच तालमेल बनाना होगा। भारत को चीन के खतरे का सामना करते हुए यथार्थवाद और रणनीतिक खुबूबूझ के सहारे आगे बढ़ना होगा।

(स्तंभकार अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एवं 'प्रेंड्स: इंडिया'ज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स' के लेखक हैं)

response@jagran.com

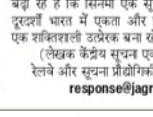

आनंद का अनुभव

शरीर की इंद्रियों से भोगे जाने वाला सुख क्षणिक होता है। विज्ञान के नियम के अनुसार प्रतिक्रिया स्वरूप मनुष्य को उसका उतना ही दुख भी झेलना पड़ता है। जीव परमेश्वर का अंश है। यही अंश जब कर्म फल के अनुसार मानव शरीर धारण करता है तो उसे जीवात्मा के नाम से पुकारा जाता है। अपरा प्रकृति से निर्मित होने के कारण मनुष्य पर प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधरी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न ही शरीर को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही उस कर्म के फल की रचना करता है। यह सब प्रकृति के सती, रजो और तमो गुणों द्वारा किया जाता है। इन गुणों के प्रभाव में मनुष्य इच्छा करता है।

मनुष्य अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है। फिर इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह हर तरह के काम करने लगता है, जिसका प्रतिफल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। आत्मा कभी तथा इच्छित फल की प्राप्ति के मोह से ग्रस्त होकर दुखों के भंवर में फंसकर जन्म-मृत्यु के भवसागर में फंस जाता है। मनुष्य विवेक द्वारा आत्मा को प्रकृति के गुणों से बचाता हुआ कर्म फलों में फंसने से बच सकता है। इसके लिए उसे लोभ, काम, क्रोध और मोह जैसे विकारों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले ज्ञानेंद्रियों द्वारा वह किसी वस्तु की ओर देखता है। फिर उसमें उसे पाने की इच्छा जागृत होती है। इच्छित वस्तु के प्राप्त न होने पर क्रोध पैदा होता है। उसके बाद उसकी बुद्धि का पतन हो जाता है और अपना नाश कर लेता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए जिससे काम एवं क्रोध जैसे विकारों से वह ग्रस्त न हो। ऐसा करने से उसके आत्मा पर मायालाज अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। फिर आत्मा शुद्ध हृदय से अपने पूर्ण स्वरूप परमात्मा से संबंध स्थापित करके दिव्यानंद का अनुभव कर सकेगा।

कर्नल शिवदान सिंह

लालच में खाली होते बैंक खाते

डा. महेश परिमल

> लोग यह क्यों नहीं समझ पाते कि बिना मेहनत किए यदि उन्हें किसी बड़ी राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो वह गलत ही होगा

इन दिनों साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा है। लोगों में अधिक की जो आदत होती है, वे ठग उसे ही भुनाते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक धन की प्राप्ति की जो चाहत होती है, उसी चाहत को ये ठग पानी देने का काम करते हैं। ईमान यह क्यों नहीं समझ पाता कि बिना मेहनत किए यदि उसे किसी बड़ी राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो वह गलत ही होगा। शुरू में यह गलत रास्ता उन्हें सही लगता है, पर अपना सबकुछ लुटा देने के बाद वे किसी को सलाह देने के लायक भी नहीं रहते। अधिक से अधिक धन लौपुलता हो उन्हें कंगाल बना रही है। इसे आज कोई समझने को तैयार ही नहीं है।

साइबर अपराधी लोगों के भीतर पनपने वाले लालच का पूरा फायदा उठाते हैं। ये ऐसे ही लोगों को लोकलुभावन संदेश भेजते रहते हैं। उनकी नजर वर्तमान में होने वाली घटनाओं और नागरिकों की आवश्यकताओं पर होती है। आजकल लोगों को आयकर के रिफंड की बड़ी चिंता लगी रहती है। ऐसे ही लोगों के पास इनका संदेश पहुंचता है। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्हें रिफंड लेने का लालच हो, उन्हें एक फोन करने की जरूरत है, वे फंस जाएंगे। एक बार व्यक्ति ने फोन उठा लिया, तो फिर वे पूरी तरह से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यह स्थिति उस समय है, जब आयकर विभाग से बार-बार यह संदेश दिया जाता है कि विभाग द्वारा कभी किसी को फोन नहीं किया जाता, न ही रिफंड संबंधी बात की जाती है। संदेश में यह भी कहा जाता है कि यदि आपके पास आयकर अधिकारी के नाम पर कोई फोन आता है, तो उसे अनदेखा कर दें। फिर भी लोग इन अपराधियों के संदेश, फोन या ई-मेल के जाल में फंस जाते हैं।

सवाल यह उठता है कि इससे बचा कैसे जाए? करदाताओं को रिफंड संबंधी मेल की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि यह ई मेल अथवा फोन नंबर उन्हें किस वेबसाइट से भेजा गया है। सरकार द्वारा भेजे गए ई मेल को कोई भी सरलता से जान सकता है। इन अपराधियों के एसएमएस कैसे आते हैं, इसे भी जान लें, तो बेहतर होगा। लोग यह समझें कि आजकल कोई भी बिना स्वार्थ के एक कप चाय भी नहीं पिलाता। ऐसे में कोई किसी अनजान को इतनी बड़ी राशि आसानी से कैसे दे सकता है? न जाने किस झांसे में आकर वे अपनी सारी बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी सामने वाले को दे देते हैं। साइबर अपराधी भी ऐसे लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं, जो इस तरह के लालच में पड़ते रहते हैं। पहले ये छोटी-छोटी राशि देकर उन्हें अपने जाल में फांसते हैं, फिर बड़ी राशि लेकर चंपत हो जाते हैं। यदि लोग संभलकर अपने भीतर के लालचरूपी राक्षस को मार दें, तो अपनी जमा-पूंजी बचाने में कामयाब हो सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मंथन करें कांग्रेस

'फिर भारी पड़ी भाजपा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने में सफल रही और कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आम चुनाव में मतदाता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। जबकि स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में मूलभूत सुविधाओं और अन्य स्थानीय मुद्दों को तरजीह देते हैं। भाजपा को ज्यादा सीटों पर जीत मिलना यह भी साबित कर रहा है कि मतदाता अब डबल इंजन की सरकार को ध्यान में रख रहे हैं। मतदाता अब यह भलीभांति समझ चुके हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से राजनीतिक भेदभाव न होने कारण विकास के काम अच्छी तरह समय पर हो सकते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार होने के कारण राज्य सरकार केंद्र की नीतियों को अपने यहां उचित तरीके से लागू नहीं करती है। कांग्रेस को अपनी हार पर गंभीरता से मंथन जरूर करना चाहिए और पार्टी के नेतृत्व के लिए ऐसा चेहरा तलाशना चाहिए जो राजनीति और सरकार चलाने के काबिल हो और जिस पर देश भी भरोसा करे। हो सके तो कांग्रेस को राहुल गांधी का भी विकल्प खोजना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन्हें सोच-समझकर और एक सुलझे नेता के रूप में राजनीति करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी

मेलबाक्स

इस पर विचार करना चाहिए कि प्री वाली उसकी जो नीति पंजाब और दिल्ली में चल गई वह पड़ोसी राज्य हरियाणा में क्यों नहीं चला सकी। कुछ जगहों पर तो उसके उम्मीदवारों को नोटा से भी कम मत मिले हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मतदाता ही सर्वोपरि

हरियाणा विधानसभा चुनाव के एक्जिट पोल ने दिखा दिया कि मतदाता ही सर्वोपरि है। उसके दिल की बात कोई नहीं जान सकता। मंगलवार की सुबह नौ बजे तक सभी समाचार चैनल कांग्रेस को 58-60 सीट दिखा रहे थे और भाजपा को 19-20 सीट घोषित कर रहे थे। साढ़े दस बजे के बाद परिणाम बदलने का क्रम बना है तो वह परिणाम तक पूर्णतः विलोमावस्था में आ गया। उसने बता दिया कि योग गुरु बाबा रामदेव भी इतना बढ़िया शीर्षासन नहीं कर सकते जितना इस एक्जिट पोल ने करके दिखा दिया। 2019 से एक्जिट पोल झूठे प्रमाणित हो रहे हैं। हरियाणा में चुनाव समाप्त होते ही सभी समाचार चैनलों पर एक्जिट पोल पर बहस छिड़ गई, जो परिणाम आने तक चलती रही, समाचार चैनलों के पास समाचारों का अभाव है, एक ही समाचार को बार-बार दोहराया जाता है इसकी पूर्ति एक्जिट पोल से करते हैं।

सुधीर गोयल, पिलखुवा हापुड़

लोकतंत्र की जीत

आज के दौर में सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता तक पहुंचने के लिए धन, बल, छल, कपट आदि जैसी गंदी रास्तों में से होकर जाने से परहेज नहीं करतीं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के कुल 90 सीटों में से 29 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। भाजपा को पता था कि वह सरकार नहीं बना सकती। भाजपा को पूरी दुनिया को दिखाना था कि अनुच्छेद-370 हटाने के बाद पूरी घाटी में शांति की स्थापना हुई है और आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर है। जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नगण्य हो गई हैं। बड़े स्तर पर आतंकियों का सफाया हो चुका है। पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए हैं कि जम्मू-कश्मीर की अवाम लोकतंत्र में विश्वास करती है, उसे पाकिस्तान की नापाक हरकतें कतई पसंद नहीं है। भारत के इस भू-भाग में लोकतंत्र सशक्त और जीवंत है। नरेन्द्र मोदी पर जनता का विश्वास कम नहीं हुआ है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार और अब तक की सबसे अधिक सीट के साथ भाजपा सत्ता में आई है और जम्मू-कश्मीर को कांग्रेस मुक्त करने का काम किया है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

1200 प्रवाल द्वीपों वाला देश है मालदीव, जो लगभग 90 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व के समुद्री जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है।

आजकल

भारत की महत्ता समझने के लिए मालदीव बाध्य

भारत और मालदीव के संबंध इन दोनों के आपसी हितों के साथ ही हिंद महासागर और दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए समय समय पर संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों देश स्वाभाविक रूप से समझ जाते हैं कि उन्हें क्या रास्ता अपनाना है, ताकि बाद में उन्हें कोई पछताना न हो। मालदीव यदि आज भारत के साथ सकारात्मक होता दिख रहा है तो इसका श्रेय मालदीव को कम और भारत को अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि मालदीव के व्यवहार में सुधार की व्यूह रचना भारत ही रचता है

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और नरेन्द्र मोदी : भारत की महत्ता को स्वीकारता मालदीव। फाइल

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अभी भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और भारत की यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मालदीव और भारत के हालिया तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए यह एक बेहतर निर्णय है जिससे आपसी संबंधों में विश्वास और सहयोग की नई सिरे से शुरुआत हो। मालदीव के राष्ट्रपति की यह यात्रा इस बात का सूचक है कि भारत जैसे देश की महत्ता को वह किसी भी हाल में नजरंदाज नहीं कर सकता है। भारत और मालदीव ने आर्थिक संबंध और मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। भारत ने एक बार फिर मालदीव को दिखा दिया कि वह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बल्कि पड़ोसियों के आर्थिक हितों का संरक्षक बनने से कभी पीछे नहीं रहा। मालदीव का चीन के साथ एफटीए है, पर भारत के साथ नहीं। मालदीव में ऐसे नेतृत्व नहीं रहे हैं जो इस दिशा में पहल करते, लेकिन अब समय और जरूरत के साथ दोनों तरफ से आर्थिक कूटनीतिक स्थितों को पुनः परिभाषित किया जा रहा है।

भारत द्वारा मालदीव को लगातार दी जाने वाली आर्थिक मदद को बहुत से लोग सही निर्णय नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मालदीव को भारत द्वारा सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन भारत एक छोटे देश को सबक सिखाने के बजाए एक बड़े देश चीन को काउंटर करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है और इसलिए आरबीआइ के नेतृत्व में हर समय भारत मालदीव को यह भरोसा दिला रहा है कि उसके देशिदी मुद्रा भंडार संकट की स्थिति में उसे भारत ही बचाएगा, चीन नहीं। इसलिए भारत और मालदीव ने 40 करोड़ डालर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह एक ऐसा कदम है जो द्वीपीय देश मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार की समस्याओं से उबारने में मदद करेगा। नकदी संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत बड़ी मदद देने को आगे आया है।

इंडिया आउट कैंपेन : मालदीव के कई निर्णय ऐसे रहे हैं जो भारत के साथ उसके रक्षा, कूटनीतिक संबंधों, हिंद महासागर की सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करते रहे हैं जिससे दोनों देशों के पर्यटन संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिसके बाद खासकर मालदीव पर दबाव था कि वह भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल न ले। मुइज्जू के भारत विरोधी स्टैंड पर मालदीव की जनता तक ने असंतोष दिखाया। समझदार जनता अक्सर जानती है कि 'इंडिया आउट' जैसे कैंपेन मालदीव की अर्थव्यवस्था को ही गर्त में ले जाएंगे। मुइज्जू ने भी 'इंडिया आउट' जैसे कैंपेन की अपने चुनाव जीतने का हथियार बनाया था, भारतीय कंपनियों, सैनिकों को देश से बाहर करने, हाइड्रोग्राफिक समझौतों को रद्द करने में रुचि दिखाई और चीन एवं तुर्किये जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। चीन के द्वारा मालदीव को अपने यहां सैन्य प्रशिक्षण पसंद आया, चीन से हथियार खरीदने का समझौता भी उसे नागवार न गुजरा, लेकिन कुछ ही समय में मालदीव की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, क्योंकि उसे उस तरह का सतत और समावेशी तरीके का सहयोग समर्थन चीन या अन्य देशों से नहीं मिल पा रहा था, जैसा भारत से निर्बाध रूप से मिलता था। कोई भी देश कितना भी वैचारिक स्तर पर तुष्टीकरण करने की आदत सीख ले, अच्छे और पुराने विश्वसनीय सहयोगियों को दरकिनार करने लगे, लेकिन जब क्रूर वास्तविकताएं सामने आती हैं तो सारी कट्टरता को किनारे रखना पड़ता है। मालदीव के मामले में भी यही है।

भारत से एकतरफा दुश्मनी मोल लेने के बाद मालदीव को भीषण जल संकट झेलना पड़ा था। तिब्बत से 1500 टन पानी तक मंगाना पड़ गया था। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की मार पहले से ही झेलनी पड़ रही थी, जिससे पर्यटकों के स्तर पर भी आर्थिक क्षति पहुंची। ऐसे में मुइज्जू का यह सोचना स्वाभाविक ही है कि भारत के साथ रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया जाए और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ समारोह में शपथ ग्रहण समारोह में मुइज्जू भी सम्मिलित हुए और अब एक बार फिर से उन्होंने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की है। इससे पहले वह जून 2024 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए थे। विदेश मंत्री की हाल की मालदीव यात्रा के बाद मुइज्जू की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है तथा इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत जन-जन संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और प्रधानमंत्री के 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण और भारत की 'पड़ोसी पहले नीति' में एक विशेष स्थान रखता है।

दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा

भारत और मालदीव के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यावसायिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट से मालदीव की भौगोलिक नजदीकी ने दोनों देशों के संबंधों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारत के मिनिकाय द्वीप से मात्र 70 नाटिकल मील (130 किमी) और भारत के पश्चिमी तट से मात्र 300 नाटिकल मील दूर है। भारत के कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनकी मालदीव से दूरी मात्र 700 किमी है। मालदीव 1200 प्रवाल द्वीपों वाला 90 हजार वर्ग किमी में फैला देश है जो समुद्री जहाजों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। प्रवाल द्वीप मूंगे से बने द्वीप या द्वीपों की शृंखला होते हैं। ये द्वीप, समुद्र तल से कुछ मीटर ऊपर बने होते हैं।

भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसैनिक रणनीति के दायरे में यह क्षेत्र रहे। मालदीव अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के चलते भारत के लिए ब्लू इकोनमी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभा सकता है। महासागरीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से मालदीव भारत के लिए सामरिक-आर्थिक महत्व रखता है। मालदीव भौगोलिक रूप से विश्व के सबसे बिखरे देशों में से एक है। यह भू-क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। समुद्र तल से इस देश की ऊंचाई बहुत ही कम है।

हिंद महासागर में मालदीव की सामरिक अवस्थिति भारत के हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में मालदीव क्षेत्र में स्थित अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग मध्य पूर्व के तेल की आपूर्ति भारत, जापान और चीन को करते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से भारत का 97 प्रतिशत और मूल्यात्मक दृष्टि से 75 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर में बैठे मालदीव के अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग लेंस के जरिए होता है। मालदीव भारत के लिए सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

वस्तुतः वर्ष 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली विदेश यात्रा के रूप में मालदीव को चुना। मालदीव की नवनिर्मित संसद मजलिस को पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। भारत ने कहा कि मालदीव के साथ उसका संबंध इतिहास से भी पुराना है। मालदीव ने पिछली सदी के छठे दशक में जिस 'भारत प्रथम' की नीति अपनाई थी, उसी नीति को उन्नत देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव के साथ दक्षिण एशिया में राज्य प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के मिल-जुल कर कार्य करने की बात की। इसके साथ ही भारत मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफी, हेल्थ सेक्टर, समुद्री मार्ग से पैसेंजर और कार्गो सेवाएं, कस्टम्स के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और सिविल सेवा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और असैन्य जहाजों की आवाजाही के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के लिए व्हाइट शिपिंग इंफार्मेशन के विनिमय के लिए तकनीकी समझौता हुआ है। इस समझौते का महत्व भारत अमेरिका के सैन्य सूचना विनिमय हेतु हुए कामकेसा पैक्ट जैसा है। भारत मालदीव को अपने 'पड़ोसी प्रथम' की नीति का अंग मानता है और उसने मालदीव के प्रति इस प्रकार का सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपना रखा है जिससे मालदीव 'इंडिया फर्स्ट पालिसी' के तहत कार्य कर सके। चीन को हिंद महासागर में प्रतिस्तुलित करने के लिए मालदीव के साथ गहजोड़ को भारत जरूरी समझता है। वर्ष 2018 में मालदीव के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति के पूर्व मालदीव के विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अपने विदेश संबंध में भारत को जगह चीन को प्राथमिकता दी। वर्ष 2017 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। 2014 में चीन उन्मुख अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में मालदीव ने चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' पहल पर हस्ताक्षर किया। इस समय मालदीव चीन कूटनीतिक संबंधों को मजबूती दे गई। मालदीव ने चीन के समुद्री रेशम मार्ग परियोजना का समर्थन किया। यामीन सरकार ने चीनी कंपनियों को मालदीव में निवेश हेतु समझौते किए।

वैसे भारत ने सदैव अपने पड़ोसी देशों से बेहतर आर्थिक संबंध बनाने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने का प्रयास किया है। भारत ने मालदीव जैसे पड़ोसी देशों को व्यापारिक सुविधाएं देने और उनके आर्थिक लाभ के पक्ष में भी काम किया है। कोविड महामारी से बचाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन देने की बात हो या आपरेशन नीर चलाकर जल संकट से बाहर निकालने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी धर्म निभाया है। लाइन आफ क्रेडिट, ऋण सुविधा, करेंसी स्वैप, रुपे कार्ड के स्तर पर सहयोग की बात हो, भारत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। अब जरूरत इस बात की है कि मालदीव भी इस तरीके के बिना शर्त सहयोग को समझे और मिल-जुलकर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की सुरक्षा में अपना योगदान करे। (विवेक ओझा)

खरी-खरी

भ्रष्टाचार की धारा

अभिषेक

बड़े बाबू राम सहाय जी के कार्यालय का माहौल हमेशा सुस्त रहता था। फाइलों का ढेर और चाय के कप के बीच भ्रष्टाचार की बू महकती रहती थी। बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती- यह उनका सबसे प्रिय मुहावरा था। एक दिन कार्यालय में एक नया क्लर्क आया रामू। उसने भ्रष्टाचार का नाम तो सुना था, पर कभी अनुभव नहीं किया था। उसने सोचा था कि सरकारी नौकरी में सब कुछ नियम और कायदे से चलता होगा। पर उसकी उम्मीदें उस दिन धराशयी हो गईं जब उसे पहली बार राम सहाय जी के पास एक जरूरी फाइल लेकर जाना पड़ा।

'रामू, यह फाइल महत्वपूर्ण है,' राम सहाय जी ने कहा, 'लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो न?'

रामू ने भोलेपन से पूछा, 'कैसी मदद, बाबूजी?'

'अरे, बिना मिठाई के तो भगवान भी पूजा स्वीकार नहीं करते। तुम्हें समझना होगा।'

रामू कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा, शायद चाय-नाश्ते की बात हो रही है। उसने जेब से पचास रुपये निकाल कर टेबल पर रख दिया। बड़े बाबू ने कहा, 'इतनी बड़ी फाइल के लिए इतनी छोटी रकम?'

रामू ने फिर से पचास रुपये रखे। बड़े बाबू ने वापस कर दिया, 'अरे रामू, इसे रखो, ये तुम्हारे गांव के मेले में काम आएंगे। यहां शहर में 'बड़ी मिठाई' की जरूरत होती है।'

अगले दिन वह घर से एक किलो लड्डू लेकर कार्यालय पहुंचा। बड़े बाबू बोले, 'रामू, मिठाई तो अच्छी है, पर यहां बात कुछ और है।' फिर धीरे से कान में फुसफुसाए, 'मिठाई का मतलब है थोड़ी- हरी पत्तियां।'

अब रामू को बात समझ में आ गई थी। कुछ दिनों बाद रामू ने अपने दोस्तों से बात की और अपनी पहली रिश्वत के पैसे जमा किए। बड़े बाबू के पास गया और गर्व से कहा, 'ये लीजिए, आपकी हरी पत्तियां।'

बड़े बाबू बोले, 'शाबाश, अब तुम भी खेल में शामिल हो गए हो।'

रामू ने जल्द ही भ्रष्टाचार की कला में महारत हासिल कर ली। इस तरह भ्रष्टाचार की धारा निरंतर बहती रही, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को 'खेल' का ज्ञान सौंपा जा रहा हो। यह 'खेल' कभी खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं।

पोस्ट

हाल के विधानसभा चुनाव एक्जिट पोल उद्योग के तबूत में अंतिम कील साबित हुए। हमें ऐसे फर्जी आकलनों के ऊपर ऐसे और समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए।
वीर सांघवी@virsanghvi

जो भी लोग विदेश में जाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, उन्हें चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।
मिन्हाज मर्चंट@MinhazMerchant

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का एक सुखद पहलू यह भी रहा कि राज्य में सभी 30 पूर्व अलगाववादी और अलगाववादी चुनाव हारे हैं। उन्हें अफजल गुरु का भाई भी शामिल है।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

गुरुनाम सिंह चढ़ूनी पूरे भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते रहे, लेकिन चुनाव में उन्हें 1,200 वोट भी नहीं मिले। घाघ और खांटी नेता जो न समझ पाए, वह कमना रनौत को बखूबी समझ आ रहा था।
साकेत@saket71

पता नहीं पाकिस्तान ने क्या सोचकर जाकिर नाइक जैसे रंगी विरोधी और कपटी व्यक्ति को सरकारी-राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ऐसा व्यक्ति इस्लाम के नाम पर धब्बा है।
एस. इरफान हबीब@irfhabib

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या एक्जिट पोल अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं?

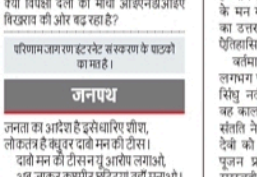

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या विपक्षी दलों का मोर्चा आइएनडीआइए विकल्प की ओर बढ़ रहा है?

परिणाम जागरण डाट नेट सर्वेक्षण के घंटों का सार है।

जनपथ

जनता का आदेश है इसे धारिए शीश,
लोकतंत्र है बंधुवर दाबो मन की टीस।
दाबो मन की टीस न यूं आंसू लगाओ,
अब जाकर कश्मीर छुट्टियां वहीं मनाओ।
'तंत्र-फंत्र' की बातन कोई है अब सुनता,
निर्णय सोच-विचार सुनाती है यह जनता!
- ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

ओबीसी चेहरे के रूप में उभरते मोहन यादव

हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित विजय ने भाजपा को संजीवनी तो दी ही है, साथ में ओबीसी नेताओं का कद भी बढ़ाया है। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का नाम भी शीर्ष पर है। मोहन यादव ने हरियाणा की पांच विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से चार पर जीत मिली। इसका जश्न स्वाभाविक है, लेकिन सीएम यादव के चुनाव प्रचार के नतीजे उनके लिए बड़ी उपलब्धि हैं। इससे उनका राजनीतिक कद तय होगा। कम समय में ओबीसी वर्ग में अन्य बड़े नेताओं के समानांतर राष्ट्रीय राजनीति में डा. मोहन यादव का ओबीसी नेता के रूप में उभरना बड़ी राजनीतिक घटना है। उन्होंने हरियाणा की जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, उनमें दादरी से सुनील सतपाल सांगवान, भिवानी से घनश्याम सर्राफ, बवानी खेड़ा से कपूर सिंह वाल्मीकि और तोशाम से श्रुति चौधरी विजयी हुईं हैं। केवल एक सीट झज्जर में भाजपा को हार मिली है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर की सांबा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में भी मुख्यमंत्री डा. यादव ने 22 सितंबर को प्रचार किया था। सलाथिया ने यहां से जीत दर्ज की है। बाहरी राज्यों में चुनाव प्रचार करना और छह में से पांच सीट पर पार्टी को विजय दिलाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव चार दिन बाद यानी 13 अक्टूबर को अपनी 10 माह की सरकार का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इतने कम दिनों में ही उन्होंने लोकसभा में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में प्रचार किया, बल्कि विजय पताका फहराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति के जानकारों का कहना है कि स्टार प्रचारक रहे डा. मोहन यादव की स्वीकार्यता केंद्रीय भाजपा नेतृत्व तक बढ़ी है। अब उनका राजनीतिक दायरा मध्य प्रदेश तक सीमित न होकर आगे बढ़ रहा है। इस सियासी घटनाक्रम ने उन नेताओं, अधिकारियों और कुछ पत्रकारों को अपने राजनीतिक चश्मे का नंबर जांच करवाने के लिए मजबूर कर दिया है, जो कहते हैं कि डा. यादव नए नेता हैं। कांग्रेस के उन आलोचकों को भी गंभीर चिंतन करना होगा, जो कहते हैं- एमपी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

डा. मोहन यादव। फाइल

परिस्थितियां बता रही हैं कि यादव का केंद्र में प्रभाव बढ़ रहा है। यादव की पहली परीक्षा तो तभी हुई थी जब 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तीन महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जितवा दीं। प्रदेश के इतिहास का यह पहला कीर्तिमान रचने वाले डा. मोहन यादव की ही कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा को ढहाने का श्रेय मिला है। यही देखकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान डा. मोहन यादव के अंदर छिपे राजनीतिक रणनीतिक कौशल का लाभ उठाया। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर लोकसभा चुनाव में एमपी के सीएम ने जहां-जहां प्रचार किया, वे सभी सीटें भाजपा जीत गईं। वे देश के 12 राज्यों की 72 लोकसभा सीटों तक पहुंचे। यहां पर 180 जनसभाएं, 58 रोड शो किए थे।

भाजपा आखिर मोहन यादव के चेहरे को आगे क्यों बढ़ा रही है, इस पर विचार करना चाहिए। इसके भी अपने सियासी मायने हैं। भाजपा डा. यादव को झारखंड विधानसभा चुनाव में भेज रही है। इससे आदिवासी समुदाय के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीदों की भी बल मिल रहा है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के उस प्रयोग का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां किसी कार्यकर्ता को अपेक्षाकृत बड़े पद तक पहुंचने के लिए लंबे और कठिन सफर से गुजरना नहीं पड़ता। ऐसे में झारखंड हो या कोई अन्य राज्य, डा. यादव को देखकर भाजपा के पहली पंक्ति के नेताओं के अलावा जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता अपने भविष्य को लेकर खासे उत्साहित रहते हैं। इसका फायदा भाजपा को चुनाव में मिलेगा। यादव का ज्यादा फोकस भाजपा के उन वादों के पूरा किए जाने की जानकारी देने पर रहता है, जो सीधे गरीब, किसान, महिला के साथ आदिवासियों से किए गए थे। इसमें लाड़ली बहना योजना और किसान सम्मान योजना के अलावा आदिवासी वर्ग के कल्याण से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। यही वजह है कि यादव मध्य प्रदेश के बाहर केवल स्टार प्रचारक तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सभाएं, रोड शो तो किया है, लेकिन इन सीटों में कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और बैठकें भी कीं। इसका असर भी दिखाई दिया है। हरियाणा में जो सीटें जीती हैं, वे केवल ओबीसी बहुल नहीं हैं, वहां एससी समुदाय मतदाता भी कम नहीं।

जब विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग पर अड़ा हो और चुनावी मुद्दा बन रहा हो तो इसका जवाब भी मोहन यादव के चेहरे को आगे करके दिया जा सकता है। यह भी बताया जा सकता है कि जिस विपक्ष के पास ओबीसी चेहरे नहीं है, वह जातिगत जनगणना के नाम पर देश को गुमराह कर रहा है। यादव उसी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी देश में लगभग 54 प्रतिशत अनुमानित है। प्रदेश में यह संख्या 52 प्रतिशत के आसपास है। यह तय है कि डा. यादव आने वाले महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए शुभंकर साबित होंगे।

मंथन

भारत में मातृपूजा का इतिहास

आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व सरस्वती एवं सिंधु नदी की घाटी में भारतीय संतति ने जगतजननी स्वरूपा मां अथवा देवी को आराध्य मानकर उनकी पूजा आरंभ की थी

शुभम केवलिया
असिस्टेंट प्रोफेसर, भगत सिंह कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय संस्कृति में मातृपूजा का प्रचलन सुदीर्घ काल से चला आ रहा है, परंतु इस काल की परिभाषा क्या है? मातृपूजा का प्रचलन इस पावन धरा पर कब प्रारंभ हुआ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पर आम जनमानस के मन में उपजते होंगे। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर केवल पुरातात्विक अध्ययन व ऐतिहासिक ग्रंथों में ही निहित है।

वर्तमान भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व सरस्वती व सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। यही वह काल व पावन क्षेत्र था जहां भारतीय संतति ने जगतजननी स्वरूपा मां अथवा देवी को अपना आराध्य मानकर उनका पूजन प्रारंभ किया। हमारे पूर्वजों ने सरस्वती एवं सिंधु नदी के किनारों पर उन्नत सभ्यता का सृजन किया और वे मातृपूजक थे। इन क्षेत्रों से मिलने वाली मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्तियां इसी ओर संकेत करती हैं। इस क्षेत्र में हुए पुरातात्विक उत्खननों से मिट्टी की पक्का करके बनाई गई मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां सौम्य एवं रौद्र रूप धारण किए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुल्ली नामक पुरास्थल से मातृदेवी की रौद्र रूप वाली मूर्तियां मिली हैं। यह मां के चंडी स्वरूप की ओर इंगित करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 52 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज पीठ भी बलूचिस्तान में ही है।

कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि देवी का एक स्वरूप जिसे हम महिषासुरमर्दिनी के नाम से जानते हैं, उसका प्रथम अंकन भी सर्वप्रथम सरस्वती सिंधु सभ्यता में ही है। इस मत का आधार है कि इसी सभ्यता के एक पुरास्थल से मिली पकी मिट्टी की एक पट्टिका जिस पर एक मानव आकृति को भाले के द्वारा एक भैंसे का संहार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। हम सब जानते हैं कि महिषासुरमर्दिनी की कहानी इस प्रकार की ही है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के ही नौशारों से मातृदेवियों की ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिनके मस्तक पर सिंदूर लगे होने के प्रमाण मिले हैं। हम सब भली-भांति जानते हैं कि विवाहित स्त्रियों द्वारा मांग में सिंदूर लगाना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह साक्ष्य इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों का मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन आज से लगभग पांच हजार वर्ष प्राचीन है।

भारतीय वैदिक परंपरा में यह मान्यता है कि यह भूमि सबकी मां स्वरूपा है। इसी भूमि से सभी जीव-जंतु, पेड़-पौधे आदि का जन्म हुआ है। उपरोक्त सभ्यता के हड़प्पा नामक नगर के उत्खनन से पकी मिट्टी की एक पट्टिका प्राप्त हुई है। इस पट्टिका पर एक स्त्री का अंकन है, जिसके गर्भ से एक पौधे की आकृति निकलते हुए दिखाई गई है। यह आकृति उस मान्यता का अंकन है जिसमें मातृदेवी स्वरूपा धरती को सृजनकर्ता बताया गया है।

हमारी संस्कृति में सप्तमातृकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विद्वान सप्तमातृकाओं का सर्वप्रथम अंकन भी इसी सभ्यता में बताते हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो से एक मुद्रिका मिली है जिस पर एक पंक्ति में खड़ी सात मानव आकृतियां हैं। कुछ पुरातत्ववेत्ता इन्हें सप्तमातृकाओं से संबंधित करते हैं। वस्तुतः सप्तमातृकाओं का सुव्यवस्थित अंकन हमें 2400 वर्ष पूर्व से प्राप्त होता दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त धातु निर्मित एक प्रतिमा है जिसे कई विद्वानों ने मृतकों कहा है। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की पत्रिका में ठाकुर प्रसाद वर्मा ने उपरोक्त मूर्ति को पार्वती की मूर्ति बताया था। वैसे उनके मत से कई विद्वान सहमत नहीं थे।

इस सभ्यता के पतन के पश्चात हमें भारतभूमि पर मूर्तिकला का अभाव देखने को मिलता है। मूर्तियों के माध्यम से देवी की आराधना का प्रचलन आज से लगभग दो हजार से अधिक वर्षों पूर्व पुनः प्रारंभ हुआ। वर्तमान मथुरा जो भगवान श्रीकृष्ण की नगरी है, वहां उस काल में देवी पूजा अत्यंत प्रचलित थी। मथुरा में हुए पुरातात्विक उत्खननों से हमें देवी के विभिन्न स्वरूप जैसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती व पूर्व में उल्लेखित सप्तमातृकाएं जैसे वराही, चामुंडा, इंद्राणी, वैष्णवी आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा में बनी मूर्तियों ने ही भविष्य में बनने वाली मातृदेवियों की मूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मातृदेवी का पूजन या उनका भारतीय जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान यह कोई कुछ वर्षों के पूर्व की उत्पत्ति नहीं है। मातृपूजा की जड़ें तो अत्यंत गहरी हैं, यही कारण है कि यह भारतीय समाज में रची बसी है। हम शरदीय नवरात्र में जिस मां की आराधना कर रहे हैं, उनकी अर्चना तो हमारे पूर्वज पांच हजार वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। आज जो भूभाग भारत के हिस्से में नहीं हैं, वहां पर ही किसी काल में मातृपूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था जो समय के साथ बाधित हुआ है। वर्तमान के भारतीय भूभाग पर रहने वाला वह समाज, जो सनातन संस्कृति का वाहक है, यह वही भारतीय समाज है जिसकी संस्कृति इस पृथ्वी पर निरासरत सबसे प्राचीनतम जीवंत संस्कृति है। इस संस्कृति पर भारतवासियों का गर्व महसूस करना स्वाभाविक है।

सरस्वती सिंधु सभ्यता में भैंसे (महिषासुर) का मर्दन करती मानव आकृति। हड़प्पा ब्रांट काम

****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • साहस • सेवा

निशाने पर कांग्रेस

विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक जहां हरियाणा में नदारद था, वहीं जम्मू-कश्मीर में भी आधे-अधूरे रूप में मैदान में था। कश्मीर में पीडीपी को साथ लिए बिना ही इंडिया ब्लॉक की नैया पार लग गई, पर हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस वाकई अपने कथित सहयोगियों के निशाने पर आ गई है। शायद ही कोई ऐसा सहयोगी होगा, जो कांग्रेस को इस समय नसीहत नहीं दे रहा। कांग्रेस हरियाणा में एक प्रतिशत से भी कम वोटों के अंतर से पिछड़ी है, पर यह उसकी हार बड़ी है। शिव सेना (उद्धव ठाकरे) ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के उसके फैसले पर सवाल उठाया, तो तृणमूल कांग्रेस ने उस पर अहंकारी होने का आरोप जड़ दिया है। कांग्रेस के साथ लड़कर सफल होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी उसे हार की समीक्षा करने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी ने नसीहत से आगे बढ़ते हुए ऐलान तक कर दिया है कि दिल्ली में वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जो उप-चुनाव होने हैं, उनमें समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को साथ लिए बिना अपने छह उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।

इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के खिलाफ खुलकर चर्चा हो रही है। यह कहा जा रहा है कि जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है, वहां वह अपने सहयोगियों को भाव नहीं देती है, जबकि वह जहां खुद को कमजोर मानती है, वहां सहयोगियों से पूरी मदद लेना चाहती है। इस शिकायत में कितनी सच्चाई है, इसकी समीक्षा स्वयं कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए? गठबंधन के मामले में कांग्रेस पहले भी अनुदार रही है और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सहयोगियों के साथ हर चुनाव में तालमेल करके चलेगी। अनेक मौकों पर इंडिया ब्लॉक का जो चरित्र विगत एक वर्ष में देखने को मिला है, उससे विपक्षी एकता की दलदली जमीन का साफ-साफ पता चलता है। विश्लेषक यह मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक दिखावे के लिए एकजुट है, इसलिए उसे चुनावों में पर्याप्त फायदा नहीं हो रहा है। अगर यह ब्लॉक सही मायने में मिलकर लड़े, तो उसे भाजपा को घेरने में आसानी हो सकती है। हालांकि, क्षेत्रीय सहयोगियों को भी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के लिए कितने प्रयास किए हैं? ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अपने-अपने क्षेत्रों में दोयम दर्जे की पार्टी मानकर चलती हैं। शायद इन क्षेत्रीय दलों को यह अंदाजा है कि वे दरअसल, कांग्रेस की छोड़ी हुई जमीन पर ही खड़ी हैं और अगर यह जमीन कांग्रेस के पास वापस गई, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सबको अपनी-अपनी चिंता है और ऐसे में, इंडिया ब्लॉक की चिंता करने वालों का टोटा है।

अनेक मौकों पर इंडिया ब्लॉक का जो चरित्र विगत एक वर्ष में देखने को मिला है, उससे विपक्षी एकता की दलदली जमीन का साफ-साफ पता चलता है।

हालांकि, बुनियादी बात यही है कि विपक्ष भाजपा को तभी चुनौती दे सकता है, जब वह एकजुट दिखे भी और मन से एकजुट हो भी। इंडिया ब्लॉक के एकजुट दिखने मात्र से अब कोई भी प्रभावित नहीं होगा। अगर हरियाणा चुनाव की मिसाल लें, तो कांग्रेस महज 0.85 प्रतिशत मतों के अंतर से पराजित हुई है। यहां अगर आम आदमी पार्टी को मिले 1.79 प्रतिशत वोट इंडिया ब्लॉक को मिले होते, तो जाहिर है, भाजपा तीसरी बार शायद ताज बचा न पाती और संभव है, आम आदमी पार्टी की झोली में भी हरियाणा में सीटें दर्ज हो जातीं। साथ न लड़ने का नुकसान कांग्रेस को हुआ है, तो क्षेत्रीय दलों को भी अपने नुकसान का जायजा लेना चाहिए। हां, यह जरूर है कि कांग्रेस को बड़प्पन का परिचय देते हुए अपना विचार-व्यवहार तय करना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 10 अक्तूबर, 1949

राजनीतिक चलचित्र

चीन की साम्यवादी सरकार का रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य राष्ट्रों द्वारा नियमित माना जाना; वहां की लड़खड़ाती हुई राष्ट्रीय सरकार का रूस से संबंध विच्छेद करना; जर्मनी के रूसी-क्षेत्र में जनतंत्र की घोषणा; संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री का जनरल ड्रेलबोई को जिनेवा में उपस्थित होकर अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण करने का आदेश देना; नेहरूजी का अमरीका के लिए प्रस्थान और भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को गले लगाने का निश्चय करना- ये कुछ प्रमुख चलचित्र हैं, जो पिछले सप्ताह हमें विश्व के विस्तृत रजत-पट पर दिखाई दिये।

चीन का संघर्ष- अभी दो सप्ताह भी नहीं हुए, चीन के विजयी साम्यवादियों ने पीपिंग में जनतंत्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। जैसी कि आशा की जा सकती थी, उसे नियमित मानने वाले देशों में रूस अग्रगण्य रहा। रविवार २ अक्तूबर को वहां के उप-परराष्ट्र मंत्री श्री ऐन्द्री ग्रोमिको ने चीन के साम्यवादी जनतंत्र के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई को तार द्वारा सूचना दी कि रूस ने उनकी नव-निर्मित शासन-व्यवस्था को नियमित मान लिया है। उसी दिन रूस की ओर से यह भी घोषणा की गई कि कैंटन से, जो चीन की राष्ट्रीय सरकार की वर्तमान राजधानी है, रूसी प्रतिनिधि हटा लिया जायेगा। इनका समर्थन करते हुए मास्को रेडियो ने यहां तक कहा कि कैंटन की सरकार अब केवल एक प्रांतीय सरकार रह गई है, इसलिए रूस उसे चीन की प्रतिनिधि सरकार नहीं मान सकता।

रूस के इस कार्य का अनुकरण पूर्वी यूरोप के कई देश कर चुके हैं और आशा की जाती है कि वहां के अन्य राष्ट्र भी निकट भविष्य में ऐसा ही करेंगे। कहा जा सकता है कि ये राष्ट्र तो रूस के पिट्ठू और दब्बू हैं, इसलिए वे चीन की साम्यवादी शासन व्यवस्था को नियमित न मानने की धृष्टता कर ही कैसे सकते थे? किंतु लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि अनेकानेक बड़े राष्ट्र भी साम्यवादी सरकार को स्वीकार करने में अधिक आनाकानी नहीं करेंगे। अमरीका की बात तो छोड़िए, ब्रिटेन और भारत की ओर से कोई विरोधाभास नहीं मिला है और इन दोनों देशों में समय-समय पर जो उद्गार व्यक्त किये गये हैं, उनसे यह विश्वास करने की प्रेरणा मिलती है कि इन्हें चीन की साम्यवादी शासन-व्यवस्था को नियमित मानने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होगी।

अमेरिकी महा-मुकाबले का आखिरी दौर

यहां स्कैन करें

फ्रैंक एफ इस्लाम | अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी

डोनाल्ड ट्रंप पूरी आक्रामकता के साथ फिर राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हैं। चिंता तो यहां तक है कि वह कमला हैरिस से मात खा गए, तो क्या आसानी से हार मान जाएंगे?

अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 5 नवंबर को मत डाले जाएंगे, यानी मतदान में एक महीना भी नहीं बचा है। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली बहस पूरी हो चुकी है और कई राज्यों में प्रारंभिक मतदान भी शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मतदाताओं का एक हिस्सा अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुका है। दोनों प्रमुख उम्मीदवार- डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी व मौजूदा उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूरी वोट की उम्मीद में अब देश भर में घूम रहे हैं।

इस समय विशेषकर, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन जैसे अहम राज्यों के जनमत सर्वेक्षण बता रहे हैं कि इन दोनों प्रत्याशियों की दौड़ फिलहाल बराबरी पर है। हैरिस को जरूर कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन मत-संख्या के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहा। राजनीतिक विश्लेषक बेहद नजदीकी मुकाबले की संभावना जता रहे हैं और मतों को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं हैं। पिछले 10 चुनावों में से नौ में सटीक भविष्यवाणी करने वाले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इतिहासकार एलन लिक्टमैन भी उप-राष्ट्रपति को बढ़त दे रहे हैं, पर सर्वेक्षणों की तरह यह भी मुकाबले को काफी नजदीकी मान रहे हैं।

दरअसल, राष्ट्रपति चुनाव का माहौल उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की दावेदारी के बाद बदला। उनका नाम तब सामने आया, जब राष्ट्रपति जो बाइडन ने बीमारी का हवाला देकर यह चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बाइडन तमाम सर्वेक्षणों में ट्रंप से पीछे चल रहे थे और ट्रंप भी बाइडन की कमजोर नसें लगातार दबा रहे थे। वह उनकी उम्र, कार्यकाल, महंगाई व आव्रजन चुनौती आदि मसलों पर लगातार हमलावर थे। मगर ट्रंप की तुलना में अधिक युवा और सक्रिय कमला हैरिस के मैदान में आते ही पूरा समीकरण बदल गया।

हैरिस विशेष रूप से डेमोक्रेटिक मतदाताओं और उदार वोटरों पर अपनी पकड़ बनाने में सफल साबित हुई हैं। उनका चुनाव अभियान बाइडन की नीतिगत सफलता को आगे बढ़ाने, खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी का नया चेहरा पेश करने और देश को आगे ले जाने के वायदे के आस-पास केंद्रित है। इसी का नतीजा है कि चुनावी दौड़ काफी नजदीकी और दिलचस्प बन गई है। हालांकि, आने वाले हफ्तों में काफी कुछ बदल भी सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव का अभियान काफी अप्रत्याशित होता है और चुनाव न सिर्फ प्रत्याशियों द्वारा, बल्कि बाहरी घटनाओं से भी प्रभावित होता है। इनमें से कुछ घटनाएं तो राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती हैं। राष्ट्रपति के लिए पूर्व में चुनाव लड़ चुकीं डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन ने हाल ही में अपने एक भाषण में 'अक्तूबर सरप्राइज' की उचित याद दिलाई। 'अक्तूबर सरप्राइज' उस अप्रत्याशित घटना को कहते हैं, जो चुनाव के अंतिम दिनों में हवा का रुख बदल देती है। हिलेरी क्लिंटन खुद भी इसकी शिकार रही हैं, जब साल 2016 में एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी की आखिरी वक्त में उनकी ई-मेल जांच के बारे में की गई घोषणा से चुनावी बयार अचानक बदल गई। अधिकांश विश्लेषक मानते हैं कि इसी कारण हिलेरी क्लिंटन को हराने में ट्रंप सफल रहे, जबकि जनमत सर्वेक्षणों में वह भारी अंतर से आगे चल रही थीं।

इस साल भी अक्तूबर में चार 'घटनाएं' हुई हैं, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। पहली, हेलेन तूफान के कारण हुई अभूतपूर्व तबाही। इसने पिछले दिनों छह दक्षिण-पूर्वी राज्यों को प्रभावित किया। इस तूफान में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने और लाखों डॉलर के नुकसान की खबर है। बेशक, कई प्रभावित राज्यों में रिपब्लिकन गवर्नर हैं, लेकिन मतदाता इस संकट से निपटने में बाइडन प्रशासन की सक्रियता को मतदान करते हुए आंक सकते हैं। दूसरी, मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव, खासतौर से इजरायल और ईरान का संकट, जिसने एक अलग तरह की चुनौती पेश की है। इस संघर्ष का वैश्विक असर पड़ सकता है और अगर हैरिस व बाइडन प्रशासन स्थिति को संभालने में नाकाम मान लिए गए, तो मतदाताओं में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति कमजोर पड़ सकती है।

तीसरी, पूर्वी और खाड़ी तट के बंदरगाहों में 40 हजार डॉकवर्कर्स की हड़ताल। यह अगर लंबा खत्म नहीं हुई होती, तो देश के भीतर आपूर्ति शृंखला प्रभावित हो सकती थी। इससे कारोबारियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता था और उपभोक्ता महंगाई झेलने को मजबूर हो सकते थे। इससे कमला हैरिस की स्थिति प्रभावित होती। और आखिरी घटना है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने के प्रयासों से संबंधित अदालती मामलों में विशेष वकील जैक स्मिथ द्वारा हाल ही में दायर की गई याचिका। इसमें ट्रंप की संलिप्तता को लेकर नए विवरण और पर्याप्त सुबूतों का जिक्र किया गया है। यह याचिका ट्रंप की उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचा सकती है।

ये सभी बाहरी कारक चुनाव अभियान के अंतिम दिनों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनका खासा प्रभाव उन सात राज्यों में हो सकता है, जिनका जिक्र शुरुआती पंक्तियों में किया गया है। जाहिर है, उम्मीदवारों द्वारा खुद को पेश करने, अपनी नीतियां जनता को समझाने और प्रभावी चुनावी रणनीति से ही इस बार चुनावी नैया पार नहीं लगेगी, बल्कि अमेरिकी राजनीति के अस्थिर चरित्र को ये कितना संभाल पाते हैं, इस कसौटी पर भी लोग उनको कसेंगे।

वैसे, 5 नवंबर को चुनाव जरूर हो रहा है, लेकिन नतीजा तुरंत आ जाए, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी से ही मेल से आए मतपत्रों व प्रारंभिक मतदान की वैधता पर सवाल उठाने लगे हैं। यदि नतीजे पिछले चुनाव जैसे नजदीकी आते हैं, तो ट्रंप की नीति आसन्न विवाद का मंच तैयार कर रही है। उस वक्त ट्रंप ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया था। लिहाजा, चिंता यह भी है कि हार-जीत का कम अंतर लंबी कानूनी लड़ाई का कारण बन सकता है। इसका मतलब है कि अंतिम परिणाम की पुष्टि होने में चुनाव के बाद कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं।

अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिका का दुर्भाग्य ही होगा। हालांकि, यही अमेरिका की सच्चाई भी है। राष्ट्र के संस्थापकों ने जो कल्पना की थी, उस दिशा में अमेरिकी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने और 'अधिक पूर्ण संघ' बनाने के लिए उसे इन तमाम सवालों से रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से निपटना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नमक के गरीब कारीगरों की जिंदगी में बढ़ती कड़वाहट

यहां स्कैन करें

रमेश ठाकुर | वरिष्ठ पत्रकार

इंसानी जिंदगी में नमक का किरदार बहुत बड़ा है। भोजन में नमक न डला हो, तो बेस्वाद हो जाता है। नमक के सही अनुपात से हमारा शरीर सही काम करता है। हमें हर हाल में नमक चाहिए, पर हम नहीं देखते कि हमारे लिए कौन नमक बनाता है, कौन नमक कौन भेजता है? हमें नमक बनाने वाले कारीगरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए।

ध्यान रहे, नमक के कारीगर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हमारे लिए साफ-सुथरा नमक तैयार करते हैं, पर बीते कुछ महीनों से समुद्र के खारे पानी से नमक बनाने वाले कारीगरों के सामने अचानक से परेशानियों का अंबार लग गया है। परेशानी यह है कि उन्हें बेदखली का आदेश दे दिया गया है। वैसे भी भारत में नमक निर्माण कार्य बहुत सीमित है। मात्र गुजरात के खड़गौड़ा, भावनगर, पोरबंदर और कच्छ के रण में ही नमक उत्पादन होता है। देश में सालाना करीब तीन करोड़ टन नमक का उत्पादन होता है। नमक निर्माण में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है।

पिछले वर्ष-2023 में भारत ने करीब 33.80 करोड़ डॉलर के नमक का निर्यात किया है। टाटा नमक भारत का सबसे बड़ा पैकेट बंद नमक ब्रांड है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 17 फीसदी है। भारत में नमक उद्योग से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब पांच लाख लोग जुड़े हैं। समुद्र के खारेपानी से नमक बनाने में इस वक्त तकरीबन 8,000 कारीगर सीधे जुड़े हैं, पर अब उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गुजरात सरकार ने उन्हें काम रोकने और अपना बोरिया-बिस्तर समेटने के लिए कह दिया है।

खुले बाजार में नमक 20 रुपये किलो बिकता है, पर उसमें से केवल एक रुपया नमक के कारीगरों या श्रमिकों की जेब में जाता है।

गौरतलब है, दशकों से गुजरात का कच्छ जिला, जो समुद्री खारे पानी के लिए प्रसिद्ध रहा है, 'नमक रण' बेहत कहा जाता रहा है। पुराने जमाने में उसे 'नोनिक' भी कहते थे। नोनिक का मतलब होता है 'नून', यानी नमक बनाने का स्थान। यह क्षेत्र कभी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। हालांकि, सरकार के सामने भी 'नमक श्रमिकों' को एकाएक बेदखल करने की तमाम कानूनी दिक्कतें हैं। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने नमक मजदूरों को यह धंधा 'वन अधिकार कानून' के तहत आवंटित किया था। सरकार के पास कोई अधिकृत कागजी दस्तावेज नहीं है, इसलिए अड़चनें सरकार के सामने भी खड़ी हैं। यह मामला निश्चित रूप से अदालत में जाएगा और वहीं से कोई समाधान निकलेगा। अदालत सरकार से पहला सवाल यही करेगी कि किस अधिकार से उन्होंने वहां अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया है और विना वैकल्पिक व्यवस्था के नमक के कारीगरों को कैसे बेदखली का आदेश पारित किया है? नमक के कारीगरों के हितों को देखते हुए अदालत हुकूमत के समक्ष मानवीय पक्ष का भी हवाला जरूर देगी और देना भी चाहिए।

यह भी गौर करने की बात है कि नमक निर्माण का काम साल भर नहीं चलता है। कारीगरों के हिस्से काम के मात्र चार महीने आते हैं, बाकी 8 महीने काम बंद रहता है। समुद्री तूफानों के आने से धंधा पूरी तरह चौपट हो जाता है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि नमक कारीगरों के हिस्से मेहनत की पूरी कमाई नहीं आती है। बाजार में नमक 20 रुपये किलो बिकता है, पर उसमें से केवल एक रुपया कारीगरों की जेब में जाता है। बिचौलिए इनकी कमाई खा जाते हैं। इनके हक-हकूक के लिए बोलने वाला कोई नहीं होता, इसलिए इनका खुलेआम शोषण होता है। श्रमिकों के हालात देखकर कोई भी इनकी परेशानियों का अंदाजा लगा सकता है। असली और नकली नमक की पहचान इन्हीं कारीगरों को होती है। बेकार नमक के सेवन से घेंघा जैसी बीमारियां होती हैं।

नमक के कारीगरों से जुड़ा सबसे दुखद पहलू यह है कि तकरीबन 98 फीसदी कारीगर चर्म रोग के शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर कारीगरों की आंखें खराब हो जाती हैं, मोतियाबिंद हो जाता है। कई तरह के हड्डी रोग हो जाते हैं। घुटने जल्दी जवाब दे जाते हैं। उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। कच्छ में ही करीब 8 हजार नमक कारीगर अब भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 90 प्रतिशत कारीगर भूमिहीन हैं। अब सरकारी सहयोग नहीं मिलने से नमक के कारीगरों का मोहभंग होने लगा है। क्या हमारे स्वाद में इजाफा करने वालों की कड़वी होती जिंदगी को हम किसी तरह से सहारा दे सकते हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

कुछ पाने की प्रबल चाह

जल की भांति ज्ञान, बुद्धि, कौशल, आशीर्वाद आदि में प्रवाह ऊपर से नीचे, संपन्न से विपन्न की ओर रहता है। देवी-देवताओं और सिद्ध जनों से कुछ ग्रहण करके हम अपना जीवन संवार सकते हैं, शर्त है कि लाभार्थी में पाने की प्रबल चाहत हो। भक्ति परंपरा का यही सिद्धांत है। यह समझते हुए कि जिस कुएं से जल न निकाला जाए, उसका जल सूख जाता है, ज्ञानी-विज्ञानी, हुनरमंद, संत और सयाने लोग अपना अर्जित ज्ञान या कौशल योग्य व्यक्तियों से साझा करना चाहते हैं, बल्कि वे उचित पात्र की बाट जोहते हैं। किंतु लाभार्थी के खरेपन से संतुष्ट हुए बिना प्रभु सहित कोई दाता ज्ञान, बुद्धि या आशीर्वाद नहीं बरसाता।

समृद्धि के द्वार तभी खुलते हैं, जब उन्नति की भावना दाहकती-फड़कती हो, दाता के प्रति अगाध निष्ठा और समर्पण हो, उसकी मंशा या कार्यविधि पर संदेह लेशमात्र न हो। दाता को दिखावटी आचरण नहीं सुहाता, वह छद्म और वास्तविक में भेद समझता है। लाभार्थी को हाथ नीचे रखना होगा। उसे ज्ञान का अहंकार है, तो वह ग्रहण करने में अक्षम होगा। सुमार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की दुर्गा को जाग्रत रखना होगा। प्रसंग है, अत्यंत बलशाली, वरदान-प्राप्त महिषासुर के आतंक से पृथ्वी पर त्राहि-त्राहि मची थी और उसका विनाश आवश्यक था। राक्षसों की पराजय के निमित्त त्रिदेवों ने समेकित प्रयास से मां दुर्गा की उत्पत्ति की। सभी देवों ने अपने-अपने अमोघ अस्त्र प्रदान कर देवी को शक्ति-संपन्न बनाया और आसुरी साम्राज्य ध्वस्त किया गया। दशमी को समाप्त नवरात्रि में आसुरी भावों के उन्मूलन और सन्मार्ग पर चलने का संदेश है।

देवी-देवताओं की भांति सिद्ध पुरुष भी शक्ति के पुंज होते हैं। देवताओं और सिद्ध जनों को छोड़िए, दाता साधारण स्तर का हो, तब भी एक अन्य संबंध है, जिसमें मजबूती से बंधकर लाभार्थी को भारी लाभ मिलता है और वह है प्रेम का संबंध। भक्त में प्रेम और निष्ठा हो, तो प्रभु उसके हित में अपने नियम भी बदल डालते हैं और प्राणों को अभीष्ट वस्तु या कृपादृष्टि सहज प्राप्त हो जाती है।

जीवन में जो भी सर्वाधिक मूल्यवान है, उसे पाने के लिए लक्ष्य की स्पष्टता व परालौकिक शक्ति का संबल चाहिए, जो हमें उन देवों, पितरों व परिजनों से मिलता है, जो हमारी सोच, दिशा और कार्यों से आश्वस्त होते हैं और यह स्थिति तब बनेगी, जब हम उनसे अपने सरोकार साझा करेंगे और हमारे अहम कार्यों के पीछे उच्च शक्तियों का अनुमोदन होगा। मोहल्ले की देवी भी तभी तृप्त होगी, जब घर की मां प्रसन्न रहेगी। सेवा भाव से तुष्ट देवी का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए हमें श्रद्धा से अनुकूल वातावरण बनाकर उनकी कृपा दृष्टि का आह्वान करना चाहिए।

सुमार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की दुर्गा को जगाए रखना होगा। देवी या देवता को दिखावटी आचरण नहीं सुहाता, वे छद्म और वास्तविक में भेद समझते हैं।

हरीश बड़थ्वाल

सचिन तेंदुलकर | पूर्व क्रिकेटर

देश की सुरक्षा करने वाली सबसे बेहतरीन शक्तियों में से एक के साथ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय वायु सेना के बहादुर सैनिकों को उनकी सेवा और बलिदान के लिए हृदय से सलाम!

डबल इंजन पर मतदाताओं का फिर भरोसा

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक मार ली है। यह डबल इंजन सरकार की जीत है। कांग्रेस को अपनी इस हार का गंभीरता से मंथन करना चाहिए। उसे यह समझना होगा कि चुनावी जंग में जीत तश्तरी में परोसकर नहीं दी जाती। इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि चुनावी ऊंट को मतदाता किस करवट बैठाएगा? सियासी दल यह भी समझ रहे होंगे कि आम चुनाव में मतदाता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखता है, जबकि स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों में मूलभूत सुविधाओं व अन्य स्थानीय मुद्दों को। हरियाणा की डबल इंजन सरकार अपने कामकाज से मतदाताओं में भरोसा जगाने में सफल रही, जिसका फायदा भाजपा को चुनावों में मिला। मतदाता यह भली-भांति समझने लगे हैं कि केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से राजनीतिक भेदभाव नहीं हो पाता और विकास के काम कहीं अच्छे से संचालित होने लगते हैं। आमतौर पर यही देखा जाता है कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार होने के कारण राज्य सरकार केंद्र की नीतियों को अपने यहां उचित तरीके से लागू नहीं कर पाती। इसका राज्य को तो नुकसान होता ही है, आम लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ता है।

हालांकि, यह नतीजा कांग्रेस के लिए किसी सबक से कम नहीं है। उसे मतदाताओं के दिल में उतरने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। विरोधी दलों द्वारा बनाए गए माहौल का भी उसे जवाब देना होगा। जाहिर है, राहुल गांधी को अब राजनीतिक बाजी सोच-समझकर चलनी होगी। पार्टी में उनके अलावा कोई दूसरा विश्वसनीय चेहरा नहीं दिखता। क्या कांग्रेस हाईकमान के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, जो उसके सेनापति का साथ दे? बिना मजबूत सेना के सेनापति आखिर कब तक लड़ाई लड़ सकेगा? भाजपा को हराना है, तो उसकी तरह कुशल रणनीति ही नहीं बनानी होगी, बल्कि एक मजबूत सेना भी तैयार करनी होगी। 'पन्ना प्रमुख' जैसी संकल्पना उसे भी अपनानी होगी, तभी वह भाजपा से मुकाबला कर पाएगी।

साफ है, यह जनादेश कई संदेश देता दिख रहा है। भाजपा स्वाभाविक तौर पर खुश होगी, क्योंकि उसकी नीतियों को व्यापक स्वीकृति मिली है। एक मुश्किल चुनाव में, जिसके हारने की भविष्यवाणी तमाम सियासी पंडित कर रहे थे, भाजपा ने जीत ही नहीं हासिल की, बल्कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन भी किया। यह डबल इंजन सरकार के होने से ही संभव हुआ है। लोग विपक्षी दलों के झांसे में नहीं आ रहे। यही भरोसा केंद्र व राज्य की भगवा सरकार को मजबूत बनाता है।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

डबल इंजन

लोगों के लिए फायदेमंद नहीं ऐसी सरकार

हरियाणा चुनाव को यदि हम डबल इंजन की सरकार की जीत मानते हैं, तो जम्मू-कश्मीर के नतीजों को क्या नाम देंगे? असल में, विधानसभा चुनावों के इन अलग-अलग नतीजों का सिर्फ एक ही संदेश है कि लोग सरकार के कामकाज के आधार पर वोट देते हैं, किसी की हवा-बयार को देखकर नहीं। अन्यथा, दोनों राज्यों में नतीजा एक समान ही आता, जो नहीं हुआ। हरियाणा में जहां भाजपा को लगातार तीसरी बार जीत मिली, तो जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर लोगों ने भरोसा किया।

सवाल है कि डबल इंजन सरकार पर कितना भरोसा करें? मेरी मानें, तो ऐसी सरकारें शायद ही भरोसे पर खरा उतर पाती हैं। कुछ उदाहरणों से शायद आप मेरी बात बेहतर समझ सकेंगे। डबल इंजन की कथित सरकार मणिपुर में भी है और वहां की हालत क्या है, यह शायद ही बताने की जरूरत है। अभूतपूर्व हिंसा में यह राज्य जल रहा है। अविश्वास का आलम यह है कि यहां का सामाजिक ताना-बाना पूरी तरह से टूट चुका है। कुकी और मैतई को एक-दूसरे पर नाममात्र भी भरोसा नहीं रहा। बिहार का हाल भी जानना दिलचस्प होगा, जहां डबल इंजन सरकार होने के दावे किए जाते रहे हैं। यहां विकास का कितना काम कथित तौर पर हुआ, इसकी सच्चाई तो यहां के लोग ही बताएंगे, लेकिन पुल कितने गिरे, उसकी जानकारी देश-दुनिया में सबको हो गई। आखिर यह कैसा विकास है? यहां की डबल इंजन की सरकार पुलों को गिरने से नहीं रोक पाई। यहां तो अब भी ऐसी स्थिति नहीं बन सकी है कि प्रवासी बिहारी वापस लौटकर अपना कुछ काम-धंधा जमा सकें, जबकि यहां की सरकार विकास के तमाम दावे बेधड़क करती है। अगर माहौल सुधरा है, तो वे जमीन पर क्यों नहीं दिखते?

इन सबका एक ही संकेत है- सरकार यदि जनता के हित में काम करती है, यदि जनहितकारी नीतियों का निर्माण करती है, शासन कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करती है और तंत्र को जनहितैषी बनाने में सफल होती है, तो लोग उसे सिर-आंखों पर बिठाएंगे ही। वरना, दो इंजन लगा लीजिए या कई और, सत्तारूढ़ पार्टी का फिर से लौटना मुश्किल है। ताजा विधानसभा चुनावों की भी यही कहानी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार पर लोगों ने भरोसा किया है, जबकि जम्मू-कश्मीर में बदलाव की बयार बही है। हमें इन नतीजों को इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहां डबल इंजन जैसे कारकों का कोई महत्व नहीं। हरियाणा की जीत वास्तव में सैनी की जीत है।

दीप्ति, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 10 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

अगर तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते हो तो उसे बदल दो। अगर उसे बदल नहीं सकते तो अपना रवैया बदल दो।
-माया एंजिलो

अनुमान फिर गलत

भाजपा ने हरियाणा के चुनावी महाभारत में सत्ता विरोधी लहर को लेकर राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को धता बताते हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस के चुनावपूर्व गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेना तय है। मतगणना पूर्व तमाम सर्वेक्षणों में हरियाणा में भाजपा की हार की बात कही गई थी और इसके पीछे इसके दो कार्यकाल के चलते सत्ता-जनित जनाक्रोश को प्रमुख कारण के रूप में गिनाया गया था। जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ मतगणना पूर्व सर्वेक्षणों में त्रिशंकु विधानसभा जैसा परिदृश्य उभरने की बात कही थी। जिस तरह का नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन

रहा है, उससे यह अनुमान भी गलत साबित हुआ। पांच अक्टूबर को मतदान होने के तुरंत बाद जारी हुए विभिन्न सर्वेक्षणों में हरियाणा में कांग्रेस को 44-65 सीटें जबकि भाजपा को 18-32 सीटें मिलने की बात कही गई थी। मतगणना के दिन तक भाजपा के लिए हालात तनावपूर्ण और कांग्रेस के लिए उत्साह से लबरेज रहे। कांग्रेस नेताओं के बयानों से लग रहा था कि मुख्यमंत्री के लिए भारी खींचतान हो सकती है। पद के लिए पहले दावा करने के फेर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सैलजा ने मतगणना के रोज से दो दिन पहले ही दिल्ली में डेरा डाल लिया था। लेकिन सर्वेक्षणों के अनुमान उलटे रहने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। पहली दफा नहीं है, जब मतगणना पूर्व अनुमान गलत साबित हुए हों। लोक सभा चुनाव में भी भाजपा को जितनी सीटें जीतते बताया गया था, उससे कहीं कम सीटें उसे मिलीं। पूर्वानुमान तैयार करने वाली एजेंसियां बेहद एहतियात के साथ आंकड़े जुटाती हैं, और उनका विश्लेषण करके संभावित नतीजे जाहिर करती हैं। लेकिन अनुमानों को धता बताते हुए नतीजे ठीक उलट निकलते हैं, तो एजेंसियों की खासी किरकिरी भी होती है। बेशक, ये एजेंसियां खासी मेहनत करती हैं, पर मतदाताओं के मन की टोह लेने में चूक कर जाती हैं। पूर्वानुमान गलत साबित होने के साइड इफेक्ट के तौर पर ईवीएम में छेड़छाड़ का जिन्न फिर उठ खड़ा होता है। इस बार भी ईवीएम में छेड़छाड़ और उनमें स्लो सीट जैसी बातें कही जा रही हैं। हरियाणा में अपनी जीत को लेकर कांग्रेस पूर्वानुमानों के चलते इस कदर आश्वस्त हो गई थी कि अब हार को नहीं पचा पा रही। अपनी जीत की चोरी जैसी बात कह रही है।

भरोसा बनाए रखें

पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल के करीब पचास चिकित्सकों ने इसीपा दे दिया है। ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप-हत्या की घटना के बाद न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे चिकित्सकों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। इसके बाद राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी कहा कि वे एकजुटता दिखाने के लिए इसीपा दे सकते हैं। राज्य संचालित अस्पतालों के चिकित्सकों के एक संगठन का कहना है कि अगर सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों की उचित मांगों पर अपने पैर खींचती रही तो वह सरकारी चिकित्सकों से इसीपा देने के लिए राज्यव्यापी आह्वान के लिए मजबूर होगा। अस्पताल से दस डॉक्टरों को वित्तीय अनियमितता, यौन उत्पीड़न और धमकी की संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोपों में निष्कासित किए जाने के बाद से डॉक्टरों में गुस्सा बढ़ा है। इस मामले में मुख्य दोषी संजय राय के अलावा

सीबीआई द्वारा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया जा चुका है। रेप व मर्डर का मामला सामने आने के बाद इस अस्पताल में लगातार विभिन्न खुलासे हो रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो रहा है कि यहां अराजकता, लापरवाही और आर्थिक हेराफेरी चरम पर थी। डॉक्टरों का आक्रोश नाजायज नहीं कहा जा सकता। मगर इन अनियमितताओं में शामिल किसी भी शख्स को इसलिए छूट नहीं दी जा सकती कि वह पेशे से चिकित्सक है। इसीपा देने को उतावले नाराज डॉक्टरों को इस हकीकत को स्वीकारना चाहिए। उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है परंतु गंभीर मरीजों और नियमित जांच के लिए आने वाले बीमारों की दिक्कतों की उन्हें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सीबीआई, ईडी और अदालत आदि अपना-अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। चिकित्सकों को इन पर विश्वास करते हुए अपना प्रतिरोध सहजतापूर्वक करते रहना चाहिए। राज्य इस वक्त दुर्गा-पूजा के उत्सव में मग्न है। बावजूद इसके इस वीभत्स घटना के प्रति उपजी निराशा और क्षोभ कम नहीं हो पाया है। सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने में देरी नहीं करनी चाहिए। न ही चिकित्सकों को सामूहिक तौर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे जनता की उनके प्रति आस्था और सहानुभूति कम हो जाए। वे याद रखें कि इस घटना के बाद से समूचा देश पूरी तरह डॉक्टरों के पक्ष में है।

कटाक्ष/ सहीराम

की करिए, की करिए

जी वो पंजाबी का कोई गाना है न कि दिल चोरी साड़ा हो गया-की करिए, की करिए। कुछ उसी तर्ज पर हरियाणा में कांग्रेस की जीत चोरी हो गई जी! ऐसा हम नहीं, कांग्रेसी ही कह रहे हैं और दुविधा वही है-की करिए, की करिए! सचमुच कांग्रेस के यहां चोरी बहुत होती है जी! कई बार तो लूटपाट और डाकाजनी भी हो जाती है। सेंधमारी तो अक्सर ही हो जाती है। जिस तरह से कांग्रेस हरियाणा में हारी है, उसे फिल्मी अंदाज में यही कहा जा सकता है कि जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहा जाता है। कभी सुदर्शन की कहानी 'हार की जीत' पढ़ी थी। पर कांग्रेस में जीत की हार होती है। पहले मध्य प्रदेश और इतीसगढ़ में हुआ और अब हरियाणा में हो गया। कांग्रेस के यहां जीत की जो चोरी होती है, उसे कई लोग लूटपाट और डाकाजनी भी बताने लगे हैं। शायर लोग महफिल लूटा करते हैं। भाजपा वालों ने चुनाव ही लूट लिया। वैसे वे सरकारें भी लूट लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार लूटी। कांग्रेस के यहां सेंधमारी तो अक्सर ही हो जाती है। कभी इधर से पांच विधायक उठाए तो कभी उधर से आठ विधायक उठाए। नहीं गहने-वहने के लिए चोरी, सेंधमारी नहीं होती। असली पूंजी तो विधायक और सांसद ही होते हैं, वे मिल गए तो गहना, पैसा सब हो जाता है। वल्कि असाम के भाजपायी मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा तो कांग्रेस को भाजपा के एटीएम की ही संज्ञा देते हैं। जब जरूरत हो विधायक, सांसद निकाल लो।

खैर जी, समस्या यह हो गई है कि एग्जिट पोल फिर गलत निकल गए। लोक सभा चुनाव के वक्त भाजपा के पक्ष में दिखा रहे थे, तब गलत निकले और अब हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहे थे, तब भी गलत निकले। आगे से जिस पार्टी को जीतना हो वह एग्जिट पोल में हार जाए तो उसके जीतने का चांस बना रहेगा। खैर जी, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते वैसे ही सुबह की हार शाम को जीत में बदल जाए तो उसे भाजपा कह सकते हैं। इसी तरह सुबह की जीत शाम को हार में बदल जाए तो कांग्रेस कह सकते हैं। जीत का जश्न ऐसा था कि ढोल-नगाड़े ही नहीं वज रहे थे, पटाखे ही नहीं फोड़े जा रहे थे, बल्कि गड़गड़ाहट जलेबी के ऑर्डर भी हो रहे थे। लेकिन अंततः जलेबी भाजपा वालों ने ही खाई।

सामाजिक न्याय के योद्धा

मुलायम सिंह यादव

शिवपाल सिंह यादव

भारतीय राजनीति विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का नाम अपने आप में विशिष्ट और अनन्य है। 'नेताजी' व 'धरतीपुत्र' 'गरीबों की आवाज', 'किसानों का मसीहा', 'लोहिया के लेनिन' जैसे खिताबों से जनता द्वारा नवाजे गए पद्मविभूषण मुलायम सिंह भले ही सशरीर हमारे मध्य न हों लेकिन उनके विचार, उनका गरीबनवाज राजनीतिक जीवन-दर्शन एवं उनकी स्मृतियां सदैव हमारा और भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। उनका जन्म 22 नवम्बर, 1939 को सैफई में हुआ था और महाप्रयाण (10 अक्टूबर, 2022) के दिन जब वे बयासी वर्ष के थे। मुझे उनके साथ लंबा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है, वे मेरे गुरु, नेता और अभिभावक, तीनों थे। उनके बारे में कुछ लिखना या बोलना कठिन है, क्योंकि मेरे और मेरे जैसे लाखों-करोड़ों समाजवादियों के लिए नेता जी वहां हैं जहां शब्द नहीं पहुंच सकते। वे महान समाजवादी चिंतक राममनोहर लोहिया के शिष्य और किसान नेता चौ. चरण सिंह के सहयोगी थे। यदि कहूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव, लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सदृश मनीषियों के पश्चात नेताजी सबसे बड़े समाजवादी नेता और सामाजिक न्याय के योद्धा एवं सरदार पटेल व चौ. चरण सिंह के बाद के बाद सबसे बड़े किसान नेता थे, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

नेताजी ने लोकजीवन की शुरुआत मात्र 15 वर्ष की अवस्था में लोहिया के आह्वान पर सिविल नाफरमानी (सत्याग्रह) करते हुए गिरफ्तारी से की थी ताकि किसानों पर बढ़ाया गया सिंचाई-कर वापस हो। उनमें रचना और संघर्ष तथा क्रोध और करुणा का अद्भुत समावेश था। लोहिया जी ने एक बार इटावा में कहा था, 'आज देश को मुलायम जैसे जुझारू, संकल्प के धनी, गांव-गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मठ नेताओं की आवश्यकता है।' नेताजी ने अपने कर्म और कर्मों द्वारा विकसित किरदार से अपने आदर्श राममनोहर लोहिया के कथन को कालांतर में सही सिद्ध किया। उनकी जनसेवा और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता से ही प्रभावित होकर चौ. चरण सिंह ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बस्ती की जनसभा (1986) में घोषित किया था। बड़े समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री. सत्यनारायण रेड्डी ने 9 अप्रैल, 1991 को कहा था कि डॉ. लोहिया की विचारधारा और चरण सिंह की दृढ़ता का अद्भुत समन्वय श्री मुलायम में देखने को मिलता है।

संदर्भवश जननायक कर्पूरी ठाकुर के इस वचन का उल्लेख करना भी समीचीन होगा 'मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी

की आंच और अलख को धीमा पड़ने नहीं दिया, वे संघर्ष के बल पर नेता बने हैं, उनके महत्व को हम लोग समझते हैं।' हरिकिशन सिंह सुरजीत उन्हें सांप्रदायिकता से लड़ने वाला और अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का रक्षक मानते थे। नेताजी, लोहिया की भांति लोकतंत्र में लोकभाषा, लोकलाज व लोकभूषा के प्रबल पैरोकार थे। जब मुख्यमंत्री बने तो अंग्रेजी की प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अनिवार्यता को समाप्त किया जिससे गांव और गरीब परिवार से जुड़ी प्रतिभाओं को प्रशासनिक सेवाओं में सहभागिता का पट खुला। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम ने एक भाषण में कहा कि उन्हें हिन्दी सीखने की प्रेरणा मुलायम सिंह ने दी थी। नेताजी छोटे किसानों व व्यापारियों के दंश व दर्द को समझते थे। सरकार बनाने के बाद उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनसे किसानों व लघु व्यवसायियों को अन्यायी चुंगी प्रणाली, इंस्पेक्टर-राज आदि से मुक्ति मिली। नेताजी व उनकी समाजवादी पार्टी सरकार में होती थी तो जनता को लगता था कि उनकी अपनी सरकार है। वतौर रक्षा मंत्री नेताजी चीन के सामने कभी झुके नहीं। एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में उन्होंने घोषणा कि अब अगर युद्ध हुआ तो दुश्मन देश की धरती पर होगा। उनके रक्षा मंत्री बनने से पहले जवानों की टोपी व बैल्ट ही शहीदों के घर आती थी। नेताजी ने प्रावधान किया कि शहीदों का शव उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा ताकि अंतिम संस्कार आदि धार्मिक कार्य हो सकें। नेताजी की भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों में अथाह व असीम आस्था थी। वे हनुमानजी के परम भक्त थे, किंतु धर्म के पवित्र प्रतीकों का राजनीतिक लाभ उठाने वाली सांप्रदायिक सोच के सदैव खिलाफ रहे।

वे अक्सर कहा करते थे, 'मैं यहां रोशनी पहुंचाना चाहता हूं जहां सदियों से अंधेरा है।' एक बार नेताजी हिन्दी का प्रचार करने तमिलनाडु गए तो हंसी-मजाक में करुणानिधि जी ने कहा कि तमिलनाडु हम पर हिन्दी थोपने आए हैं तो नेताजी ने बड़े आत्मीय भाव से जवाब दिया कि नहीं, हम आप पर तमिल थोपने आए हैं और चाहते हैं कि आप हम पर हिन्दी थोपने आएं। वे सभी भारतीय भाषाओं को सहोदरी मानते थे और भाषाजनित शोषण समाप्त करना चाहते थे। नेताजी अंग्रेजी के खिलाफ नहीं थे, पर अंग्रेजी को माध्यम बना कर किए जा रहे शोषण के खिलाफ थे। उनकी एक सीख हम सभी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जनहित के लिए सब कुछ सहने की आदत डालनी चाहिए।

यह नेताजी की ही देन है कि लोहिया और जयप्रकाश नारायण के जाने के बाद भारतीय लोकमानस से समाजवाद का महान स्वप्न ओझल नहीं हुआ। उन्होंने अपने कुशल प्रशासनिक कौशल से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारत की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में एक बना दिया। जब नेताजी के मार्गदर्शन व श्री अखिलेश की अगुवाई वाली सरकार थी तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, देश में महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर थी। तमिलनाडु से हमारी अर्थव्यवस्था मात्र 0.2 लाख करोड़ रुपये कम थी। नेताजी भले ही कई बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय, सबसे बड़े सूबे के नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पदों पर रहे हों, पर कभी भी पद को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। अपने पद को अपने सहयोगियों व कार्यकर्ताओं के बीच दीवार बनने नहीं दिया। उनका कद हमेशा पदों से ऊपर ही रहा। देश की जनता चाहती है कि राममनोहर लोहिया और मुलायम नेताजी मुलायम सिंह को उनके अप्रतिम योगदान हेतु भारतरत्न विभूषण दिया जाए। समाजवादी विचारधारा और पक्ष को मजबूत करना ही नेताजी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

नेताजी ने लोकजीवन की शुरुआत मात्र 15 वर्ष की अवस्था में लोहिया के आह्वान पर सिविल सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तारी से की थी ताकि किसानों पर बढ़ाया गया सिंचाई-कर वापस हो। उनमें रचना और संघर्ष तथा क्रोध और करुणा का अद्भुत समावेश था। लोहिया जी ने एक बार इटावा में कहा था, 'आज देश को मुलायम जैसे जुझारू, संकल्प के धनी, गांव-गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मठ नेताओं की आवश्यकता है'

परिवर्तन

डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

परिवर्तन संसार का नियम है। मानव का जन्म, विकास और मृत्यु इसी परिवर्तन का प्रतिबिंब है। सूर्य-चंद्र का उगना और अस्त होना, फूलों का खिलना-

मुरझाना आदि प्रकृति के परिवर्तनों के साथ मानव ने अपने सुख-सुविधा के लिए अनेक कृत्रिम परिवर्तन भी कर लिए हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज व्यक्ति जितनी आसानी से आकाश में विहार कर सकता है, उतनी ही आसानी से समुद्र की गहराइयों को भी छू सकता है। जिस प्रकार 10 सेमी. दूर बैठे व्यक्ति से सुलभतापूर्वक बात हो सकती है, वैसे ही 10,000 किमी. दूर बैठे व्यक्ति से बात करना भी आज सुलभ है। वस्तुतः इन परिवर्तनों के पीछे मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जीवन में शांति से रहना था। लेकिन क्या आज मनुष्य सचमुच शांत है? नोबल पुरस्कार विजेता कवि टीएस इलियट कहते हैं, 'अनंत आविष्कार, अंतहीन प्रयोग गति का ज्ञान लाता है लेकिन स्थिरता का नहीं।' स्पष्ट है कि बाह्य वस्तु, व्यवहार, वातावरण और वेश के परिवर्तन केवल गति दे सकते हैं, स्थिरता-शांति नहीं। बाह्य परिवर्तन को ही सब कुछ मानने वालों को सावधान करते हुए कबीर कहते हैं-'बांबी कूटे बांवरा सर्प न मार्यो जाई; मूर्ख बांबी न डंसे सर्प सबन कुं खाई।' सर्प के बिल के ऊपर भले हजारों लाठी के प्रहार कर लीजिए किंतु इससे भीतर छिपे हुए सर्प को आंच तक नहीं आएगी। यहां मुख्य प्रयोजन तो विषधर सांप को नष्ट करना था परंतु केवल बाहरी और सतही प्रयास उस उद्देश्य को पूर्ण करने में अक्षम ही रहेंगे। अतएव महंत स्वामी महाराज ने कहा कि जब तक मानव अंदर से परिवर्तित नहीं होता, उसके लिए बाह्य परिवर्तन व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। गीता में भी अर्जुन के सार्थक बदलाव को ही कृष्ण विजय कहते हैं। समान शैक्षणिक एवं बौद्धिक अभियोग्यता वाले दो मित्रों में से एक का वेतन आकस्मिक बढ़ जाए तो दूसरे मित्र को किस प्रकार का परिवर्तन शांति दे पाएगा? वेतन बढ़ा कर या किसी ठोस आंतरिक समझ को अपना कर? स्पष्ट है कि पहला परिवर्तन न तो स्थायी है, न ही अपने वश में है। किसी मित्र की प्रगति देख कर तो कल किसी अन्य प्रतिकूलता को लेकर हम अशांत होते रहेंगे। अतः जब भी सुख, सुविधा, समाधान चाहें तब बाहर के वेश, परिवेश, व्यवहार, व्यक्ति या वस्तु में परिवर्तन शुरू न करके पहले अपनी सोच-समझ में परिवर्तन लाना चाहिए। यह कहीं बेहतर रास्ता है।

रीडर्स मेल

अति विश्वास ले डूबा कांग्रेस को

तमाम एक्जिट पोल के अनुमानों को धता बताते हुए बीजेपी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ली है। चूंकि बीजेपी को 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से पार पाने की चुनौती थी, और 2024 की लोक सभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए 5 सीटें जीती थीं। इससे वातावरण बना कि राज्य में लोग बीजेपी से ऊब गए हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट, राजनीतिक विश्लेषक सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा भी कर रहे थे। इन्हीं तथाकथित विश्लेषणों के आधार पर कांग्रेस ने अपनी जीत सुनिश्चित मान ली। प्रतीत होता है कि इसी अति विश्वास ने कांग्रेस की नैया डूबा दी। अन्यथा कांग्रेस के अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी बीजेपी ने अपनी सीटों में 2019 की तुलना में वृद्धि तो की है साथ ही साथ वोट शेयर में भी बढ़ोतरी की है। कांग्रेस-बीजेपी, दोनों को ही करीब-करीब 40 फीसद वोट मिले हैं, लेकिन सीटों के अंतर में निर्णायक अंतर है। जहां पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 8% अधिक वोट मिले हैं परंतु उसकी सीटों में सिर्फ 8 की ही वृद्धि हुई है वहीं बीजेपी के वोट शेयर में तो 3% की ही वृद्धि हुई है लेकिन उसे 8 सीटें अधिक मिली हैं। कांग्रेस की हार का अहम कारण यह भी है कि उसे जाटों में वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी उसे अपेक्षित था। चुनाव परिणाम इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करेगा जो लोक सभा परिणाम से बढ़ा हुआ था।

मो. फैयाज आलम, दिल्ली

कश्मीर में राज्य बहाली अभी न हो

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणामों ने मोदी के नेतृत्व को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। जम्मू-कश्मीर में भी परिणामों ने 'जनभागीदारी और बुलेट पर बैलेट को बना दिया भारी!' कश्मीर को पूर्ण राज्य देने की मांग वेशक, जोर पकड़ रही है मगर सत्ता की बागडोर संभालने वाले दलों के घोषणापत्रों को देखते हुए फिलहाल कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना उचित न होगा क्योंकि वे दल पाकपरस्त हैं। ऐसे में सत्ता के सूत्र राज्यपाल के हाथों में ही सुरक्षित रहेंगे क्योंकि दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति के बावजूद केजरीवाल ने जो गुल खिलाए हैं, उससे सबक लेकर कश्मीर को केंद्र के अधीन रखा जाना उचित होगा!

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

वृद्धाश्रम बनाने का बढ़ता चलन

अब समाज में एक चलन बढ़ गया है वृद्धाश्रम बनने का। लोग वृद्धाश्रम में वृद्धों को क्यों छोड़ रहे हैं, वही जानें। यह भी हो सकता है कि उनके काम से बचने के लिए। वे इसी में अपनी शान समझ रहे हैं। कुछ भी हो वृद्धों के प्रति बेरुखी अच्छी नहीं। वृद्ध के जीते जी काम नहीं आए तो उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध करना बेकार है। लोग वृद्धाश्रम जाकर फोटो खिंचाते हैं जबकि दिखावा करने की बजाय उन्हें अपने बीच में एडजस्ट करने की आदत डालें। बेसहारा गायों के लिए आश्रय स्थल बने हैं। सांसद, विधायक, सरकारी अमला महज गौशाला देखने के रह गए हैं। यह भी सनक का दबाव है। इन वेजुबानों के इतने चोचले, और जो वृद्ध हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम। पता नहीं लोगों को कब सुद्धि आएगी।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

डेंगू से लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ की वैश्विक योजना

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि विश्व में चार अरब लोगों को आर्बो वायरस से संक्रमण का खतरा है, और 2050 तक यह संख्या बढ़कर पांच अरब होने का अनुमान है
- डेंगू अब 130 से ज्यादा देशों में व्याप्त है। डब्ल्यूएचओ ने डेंगू और मच्छर-जनित अन्य बीमारियों से निपटने के लिए वैश्विक रणनीतिक तैयारी, तत्परता और प्रतिक्रिया योजना शुरू की है
- यह योजना सितम्बर, 2025 तक एक वर्ष के दौरान 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करके क्रियान्वित की जाएगी

(फोटो: मनीष शुक्ला)

भारत ने नकदी के संकट से जूझ रहे मालदीव को भारी वित्तीय मदद (360 मिलियन डॉलर तत्काल और करंसी स्वैप डील के रूप में अतिरिक्त 400 मिलियन डॉलर) की घोषणा की है ताकि वह अपने ऋण चुकता कर सके। सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भी 100 मिलियन डॉलर के मालदीवी बॉन्ड्स खरीदे हैं।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

माओवादी | **सुशील देव**

मुख्यधारा में लाने के ठोस उपाय जरूरी

नक्सलियों को जड़ से समाप्त करने या नक्सली समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते नक्सली हमलों में गिरि-घीरे कमी आ रही है, और नक्सल-प्रभावित क्षेत्र लगातार सिमटते जा रहे हैं। हर व्यक्ति बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, और ऐसे में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन इससे भी बेहतर परिणाम तब मिलेंगे जब सरकारें पुनर्वास, रोजगार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी। हालांकि, इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर किए गए हैं।

कई नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों पर भी जोर दिया है। कई स्थानों पर सड़कों का निर्माण हुआ है, और बुनियादी सुविधाएं भी बहाल की गई हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मिल कर जिला प्रशासन ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें 'नक्सलवाद छोड़ो और विकास से नाता जोड़ो' अभियान की विशेष चर्चा हुई। इस अभियान के तहत नक्सली आंदोलन छोड़ चुके लोगों को खेती, रोजगार और अन्य स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पहल की गई, जिससे बस्तर में पर्यटन व्यवसाय को उन्नत किया जा सके और आमदनी के स्रोत विकसित किए जा सकें। हथियार छोड़ चुके नक्सलियों के लिए यह महत्त्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ जिससे अन्य नक्सल समर्थकों में भी सकारात्मक परिवर्तन देखे गए। उन्हें समझ में आया कि हिंसा छोड़ कर वे अपने और अपने समाज का भविष्य संवार सकते हैं। कई पूर्व नक्सली सरकारी नौकरी कर रहे हैं जबकि कुछ स्वरोजगार के जरिए जीवन यापन। लोगों का मानना है कि इसी प्रकार के विकास कार्यों से नक्सल-प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा में लाया जा सकता है।

ज्ञात हो कि 2015 में बामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई थी, जिसमें सुरक्षा के साथ-साथ विकास को भी अहमियत दी गई थी। सच्चाई यह है कि नक्सल-प्रभावित इलाकों में सरकार समय-समय पर विकास कार्य करती रही है। सड़क, इंटरनेट, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सैकड़ों मोबाइल टावर लगाए गए और हजारों किमी. सड़कों का निर्माण हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे शैक्षिक संस्थान भी संचालित हो रहे हैं। 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक पहल शुरू की गई थी, ताकि सबसे अधिक नक्सल-प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। हालांकि, यह चिंता का विषय है कि 2015 तक बिहार और झारखंड राज्यों को ही इसके लिए फंड आवंटित हो सका था। पिछले साल नक्सलवाद समाप्त करने के लिए केंद्र ने 'समाधान' नामक 8 सूत्री पहल की भी घोषणा की थी, जिसके तहत नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीतियों और कार्ययोजनाओं पर बल दिया गया लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

दरअसल, नक्सल आंदोलन के उद्देश्यों और स्वरूप में बदलाव आया है। जहां उनकी लड़ाई आर्थिक-सामाजिक विषमता से है, वहीं दूसरी ओर वह समस्या राजनीतिक उलझनों में भी फंस गई है। राजनीतिक बयानबाजी के चलते उन्हें ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। कई राजनीतिज्ञ इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने से भी नहीं चूकते। चिंताजनक है कि आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित क्षेत्रों में समुचित विकास के ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। संविधान की पांचवीं अनुसूची को लागू करने में भी लापरवाही बरती गई। अनुसूचित क्षेत्रों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उस दिशा में ठोस पहल नहीं हो पाई।

नक्सलवाद की जड़ें गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी में गहराई से जुड़ी हैं। जब तक इन मुद्दों पर युद्ध स्तर पर काम नहीं होगा तब तक नक्सल समस्या का समाधान संभव नहीं है। हिंसा की घटनाओं के साथ-साथ ग्रामीणों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना और हथियार छोड़ चुके नक्सलियों से बातचीत कर समाधान निकालना आवश्यक है। गरीबी और भुखमरी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना हिंसा का समर्थन करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार मिलें और उसकी रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। उनकी सुरक्षा और विकास के मार्ग प्रशस्त किए जाएं।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़मी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहयोग लाल, नरूमेर सहारा, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - राकेश सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 57
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के चयन एवं संपादन तथा कानूनी पहलुओं के लिए उत्तरदायी

गाज़ा में युद्ध

एक साल से जारी

गाज़ा में युद्ध एक साल से जारी है और इसकी समाप्ति की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। युद्ध दूसरे साल में प्रवेश कर चुका है। इससे भयानक विनाश गंभीर होता जा रहा है तथा राजनीतिक व सैनिक टकराव पूर्णतः 'मानवीय संकट' में बदल गया है। इस्राइल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच हिंसक टकराव से शुरू हुए इस युद्ध में अब लेबेनान और ईरान जैसी क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हो गई हैं जिससे शांति की संभावनायें और धूंधली हो गई हैं। युद्ध का प्रभाव सीमाओं के पार भी दिख रहा है जिससे असंख्य सिविलियन हिंसा, विस्थापन और उत्पीड़न के दुष्चक्र में फंस गए हैं। युद्ध के एक साल बाद भी गाज़ा की जनता हिंसा का खामियाजा भुगत रही है। पूरा आस पड़ोस खंडहर में बदल गया है, आवश्यक ढांचागत संरचना बरबाद हो गई है तथा हजारों लोगों की जानें गई हैं। गाज़ा में 140 वर्ग मील की छोटी सी पट्टी में रहने वाले 2 मिलियन से अधिक लोग पहले ही गरीबी, बेरोजगारी और मूलभूत सेवाओं तक सीमित पहुंच के शिकार थे। युद्ध ने इन चुनौतियों को विनाशकारी स्तर तक पहुंचा दिया है। अस्पताल मरीजों से भरे हैं, स्वच्छ जल की कमी है तथा बिजली दिन में कुछ ही घंटे मिल रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस स्थिति को मानवीय विभीषिका कहा है। गाज़ा की अब लगभग आधी जनसंख्या विस्थापित है और सहायता तक सीमित पहुंच के बीच भीड़ से भरे शरणस्थलों या अस्थाई शिविरों में रह रही है। वर्तमान समय में जारी नाकेबंदी के कारण इस पट्टी में आवश्यक सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है जिससे आम नागरिकों की पीड़ा गहरा रही है। बच्चे खासकर भयानकतम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनमें से बहुतों की शिक्षा तक पहुंच नहीं है तथा उनको मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत है। इससे युद्ध की विभीषिका और भयावह हो गई है।

इस्राइल और हमास के बीच स्थानीय टकराव से शुरू हुआ युद्ध अब व्यापक क्षेत्रीय टकराव में बदल गया है। इसमें लेबेनान के हिजबुल्ला तथा ईरान की सहायक शक्तियां लगातार भाग ले रही हैं। लेबेनान में मौजूद शक्तिशाली शिया उग्रवादी समूह हिजबुल्ला ने उत्तरी इस्राइल में हमले कर युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। इससे इस्राइली सैनिक वहां पहुंच गए हैं जिससे लेबेनान के अस्थिर होने का खतरा पैदा हो गया है, जबकि यह देश पहले से ही अपने आंतरिक संकट से जूझ रहा है। हिजबुल्ला तथा अनेक अन्य फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन करने वाले ईरान की संलिप्तता ने मामला और जटिल बना दिया है। तेहरान द्वारा इन समूहों का समर्थन एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में इस्राइली और अमेरिकन प्रभाव का मुकाबला करना है। ईरान की संलिप्तता बढ़ने के साथ ही व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। अमेरिका तथा अन्य विश्व शक्तियों ने इस्राइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध की संभावना पर चिन्ता प्रकट की है। राजनयिक प्रयास अब तक विफल रहे हैं तथा वार्तायें बार-बार टूटी हैं। हिजबुल्ला और ईरान की संलिप्तता से स्पष्ट है कि अब युद्ध केवल इस्राइल और गाज़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक भू-राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन गया है। इससे शांति प्रक्रिया और जटिल हो गई है। तत्काल हस्तक्षेप न होने पर गाज़ा में मानवीय संकट और गहराएगा। यह टकराव ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां सैनिक तरीकों से मुद्दों का समाधान संभव नहीं है। समय तेजी से बीत रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ को फौरन हस्तक्षेप कर क्षेत्रीय विभीषिका को विस्तार लेने से रोकना होगा।

स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति

भूमिगत जल की गुणवत्ता तथा ठोस एवं द्रव कचरे के प्रबंधन तक स्वच्छ भारत अभियान की काफी उपलब्धियां हैं। लेकिन स्वच्छ भारत की दिशा में यह अभियान जारी रहना चाहिए।

बी.के. सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त वन अधिकारी हैं)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में गांधी जयंती के दिन 'स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया था। इस अभियान ने दस साल पूरे कर लिए हैं और इस कालखंड में 120 मिलियन परिवारों को उनके घरों में सुरक्षित सफाई तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण परिवारों में शौचालयों ने जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन किया है। इससे खासकर मानव स्वास्थ्य और बेहतरी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने खुले में शौच से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यूनीसेफ की 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार इससे प्रति वर्ष जीडीपी के 5.2 प्रतिशत की बचत हुई है। इसके अन्य लाभों में भूमिगत जल का प्रदूषण रोकना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में सुधार शामिल हैं। हालांकि, लगभग 4000 शहरों को स्वच्छता और सफाई बनाए रखने का प्रमाण मिला है, पर प्रयोगकर्ताओं और प्रबंधकों के लिए इसे लगातार कारगर बनाए रखने तथा निरंतर प्रयोग की चुनौती बनी हुई है।

इस वर्ष 17 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर, 2024 में गांधी जयंती तक भारतीय स्वच्छता का 'स्वर्णिम दशक' मनाया गया। इस लेख में मैंने इस अभियान की उपलब्धियों व कमियों को रेखांकित कर भविष्य के संभावित रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की है। स्थानीय संस्थाओं तथा सिविक संस्थाओं ने इस अभियान की सफलता में अपना योगदान दिया है। इस मोर्चे पर शहरी निगमों की वार्षिक रैंकिंग अत्यधिक प्रतियोगी रही है। इंदौर, मैसूरु तथा लखनऊ व अनेक अन्य शहरों ने इस रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त किया है। इसने अनेक अन्य शहरों को अपनी रैंकिंग सुधारने को प्रेरित किया है। ठोस कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में अलग-अलग करने में तेजी आई है। शहरी कचरे का प्रसंस्करण 2014 में 18 प्रतिशत था जो अब बढ़ कर 80 प्रतिशत हो गया है। लेकिन ठोस कचरे के निस्तारण स्थलों का प्रबंधन चुनौती बना हुआ है। सूखे कचरे से बिजली व वायोईंधन बनाने के काम में अभी तेजी नहीं आई है। हालांकि, गीले कचरे से कंपोस्ट तथा बायोगैस बनाने का काम तुलनात्मक रूप से बेहतर है। ज्यादा खोज, तकनीक का प्रयोग तथा निवेश गेमचेंजर साबित हो सकता है। बड़ी समस्या अनेक शहरों के आसपास लगभग 220 मिलियन टन कचरे का प्रबंधन है। राष्ट्रीय राजधानी के भीतर और उसके आसपास गाजीपुर, ओखला, भलस्वारा और बंधवारी में जमा कचरे के पहाड़ों से निपटना काफी कठिन है। हालांकि काफी समय से सरकारें, विशेषज्ञ और अदालतें इस पर ध्यान दे रही हैं, पर कोई कारगर समाधान नहीं निकला है।

द्रव कचरा ज्यादा बड़ी समस्या है। सिविक एजेंसियां सीवेज को खुले नालों में बहने की अनुमति देती हैं। उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी नाले ढके जांए नहीं तो सीवेज बाढ़ के पानी से मिल कर शहरी जल स्रोतों में मिल जाएगा। इसके साथ ही घरेलू सीवेज की लाइनों व सीक पिटों की समय-समय पर जांच होनी चाहिए और उनकी मरम्मत से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनसे लीकेज न हो तथा भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित न होने पाएं। जल भंडारों के प्रवेश स्थलों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट-एसटीपी कारगर स्थिति में होने चाहिए ताकि बिना शोधन के अशोधित सीवेज जल भंडारों में न मिलने पाए। स्थानीय निकायों तथा नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग अपने घरों की सीवर लाइनों को स्टार्मवाटर ड्रेनों से न जोड़ें, जबकि घनी बसी मलिन बस्तियों में अक्सर यही होता है।

स्टार्मवाटर ड्रेनों में बहने वाला पानी सीधे जलभंडारों में बिना किसी शोधन के मिलना काफी हानिकारक है और इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। बैंगलुरू नगर निगम 2005-2006 और 2006-07 में प्रति दिन 1400 मिलियन लीटर-एमएलडी सीवेज पैदा करता था, पर इसका 400 एमएलडी से भी कम एसटीपी से गुजरता था। एसटीपी से गुजरने का यह अर्थ नहीं कि इस मात्रा का शोधन हो चुका है, क्योंकि अक्सर एसटीपी के प्रबंधक बिजली से चलने वाली मशीने खर्च बचाने के लिए बंद कर देते हैं। वर्तमान समय में 1700 एमएलडी सीवेज बनता है और इसका लगभग तीन चौथाई एसटीपी से गुजरता है। दूसरे महानगरों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। देश भर में एसटीपी क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि भूमिगत जल का प्रदूषण रोका जा सके नहीं तो यह अनेक जल-जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके साथ ही प्रबंधन पर कठोर नजर रखनी चाहिए ताकि वे गलत काम न करें। प्लास्टिक और पालीथीन हमारे जीवन का अंग बन गई हैं। इससे हमारे, वन्यजीवों तथा मवेशियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खासकर सिंगल-यूज प्लास्टिक इधर-उधर फेंक दी जाती है और अंततः वह कचरे के पहाड़ों या जल भंडारों तक पहुंच जाती है। इसे मवेशी, जंगली जानवर व जलीय जीव खा लेते हैं जिनमें से कुछ की दम घुटने से मौत हो जाती है। इसे खाने वाली मछलियों और मांसाहारी लोगों द्वारा इन मछलियों के भोजन से खतरा और बढ़ जाता है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून तक पहुंच गई है और स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा बन गई है।

ट्रेनों में 'बायो शौचालयों' का प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम है। 2014 से पहले रेलों की पटरियों और यहां तक कि प्लेटफार्म भी मानव मल से भरे रहते थे। यह स्थिति बहुत घृणित थी और कोई इसे देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब आश्चर्यजनक खोज से यह स्थिति बदल गई है। लेकिन बड़े शहरों से गुजरने वाली रेल लाइनों के किनारे अब भी दोनों ओर प्लास्टिकों और पालीथीनों के ढेर देखे जा सकते हैं। अक्सर इनको देखना बहुत कष्टदायक होता है। हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लास्टिक और पालीथीन का न्यूनतम उपयोग हो। हमें केन्द्र सरकार द्वारा सिंगल-यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगाए प्रतिबंध का सम्मान करना चाहिए। इस संबंध में शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ऐसा करके ही हम महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के माध्यम से गति दी है। गर्मी के मौसम में कचरा जलाना अक्सर खर-पतवार और कचरे से मुक्ति पाने का आसान साधान माना जाता है। पंजाब और हरियाणा में किसान अक्सर धान की फसल लेने के बाद खेतों में पराली जलाना खेतों को खाली करने का आसान साधन मानते हैं। खेत जल्दी से खाली कर वे गेहूं बोना चाहते हैं। दुर्भाग्य से पराली जलाने का यह समय मौसम परिवर्तन के साथ होता है। इस मौसमी परिवर्तन के कारण हवा का प्रवाह लगभग नहीं होता है जिससे पराली जलाने से पैदा नाइट्रोजन आक्साइड और कार्बन डाईआक्साइड वातावरण के उच्च स्तरों पर जाने के बजाय बड़े शहरों में चारों ओर 'स्मॉग' के रूप में छा जाती है।

इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है तथा नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि, अधिकांश जागरूक नागरिक अब अपने आसपास खर-पतवार और कचरा जलाने से रोकने लगे हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत हमें अनेक शैक्षणिक व जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। हमें यह बताने की जरूरत है कि जब खर-पतवार व कचरे के साथ प्लास्टिक और पालीथीन जलते हैं तो बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं और आसपास खड़े रहना भी असंभव हो जाता है। ऐसे सारे उत्सर्जन 'ग्रीनहाउस गैसे' हैं जो उपयुक्त मौसम स्थितियों में वातावरण के उच्च स्तर तक पहुंच जाती हैं। इन गैसों में कार्बन डाईआक्साइड अक्रियाशील तत्व है जो वातावरण में सैकड़ों साल तक बनी रहेगी। इसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। सारी दुनिया के लोग ग्लोबल वार्मिंग के कारण पैदा होने वाली भयानक स्थितियों का सामना कर रहे हैं जो हर साल बढ़ती जा रही हैं। हमें वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों से स्वयं को बचाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। यह 'स्वच्छ भारत अभियान' का व्यापक संदेश है।

अतिवादी जगत का पथ प्रदर्शन

> केवल इस आंतरिक यात्रा के माध्यम से ही हम उस पवित्रता और शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो आज की तेज़-तर्रार, अति-जुड़ी दुनिया में इतनी मायावी लगती है।

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखिका, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

योग ध्यान, मूल्यों के साथ मिलकर, इन अशांत समयों को पार करने की हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह चरमपंथियों से भरी हुई है जो मानवता पर नियंत्रण करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से, आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसे गुटों से प्रभावित है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलनकारी दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्हें चरमपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संयम को त्याग देते हैं, अति-सक्रियता का सहारा लेते हैं और कई मामलों में अत्यधिक हिंसा करते हैं। ये समूह यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और अधिकारियों द्वारा उनकी मांगें पूरी की जाएँ। वे सार्वजनिक शांति को बाधित करते हैं और उनकी गतिविधियाँ अति-मुखरता, कठोर रवैये और अन्य समुदायों या समूहों के विचारों और हितों के प्रति प्रशंसा की कमी को दर्शाती हैं। इस प्रक्रिया में, अक्सर जिस चीज़ की बलि दी जाती है, वह है संवाद या आपसी समझ की कोई संभावना, जिससे प्रतिशोध और आक्रोश का चक्र चलता है।

आज के समाज पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि, कुछ हद तक, हम सभी किसी न किसी तरह से चरमपंथी हैं। विज्ञान और तकनीक अपने चरम की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। व्यापार, वाणिज्य और उपभोक्तावाद ने वैश्विक, विस्तृत रूप धारण कर लिया है, जो बहुराष्ट्रीय और मेगा-स्केल बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने प्रभाव और नियंत्रण के ऐसे स्तर हासिल कर लिए हैं जो कभी अकल्पनीय थे। कॉर्पोरेट विस्तार और एकाधिकारवादी व्यवहार नैतिकता की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे

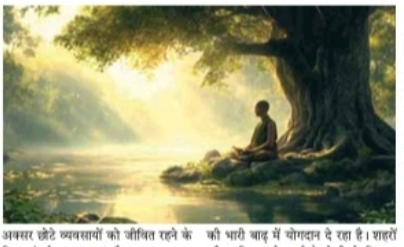

अक्सर छोटे व्यवसायों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

अनियंत्रित औद्योगिक विस्तार और कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण पर्यावरण प्रदूषण विनाशकारी अनुपात तक पहुँच गया है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को कगार पर धकेला जा रहा है, और जलवायु परिवर्तन अब एक गंभीर वैश्विक संकट बन गया है। कुछ व्यक्ति और निगम ग्रह के भविष्य की कीमत पर लाभ कमा रहे हैं। इंटरनेट का बढ़ता उपयोग सूचनाओं की भारी बाढ़ में योगदान दे रहा है। शहरों और परिवहन नेटवर्क के तेजी से विस्तार ने भी अराजकता का अपना हिस्सा लाया है। जबकि इन चरम सीमाओं को विकास के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, ये जीवन की गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सामंजस्य के क्षरण सहित महत्वपूर्ण व्यापार-नापसंद के साथ आते हैं। हालाँकि, इन सभी चरम सीमाओं के बीच, सबसे अधिक चिंताजनक प्रवृत्ति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, लालच और वासना का उदय है। ये भावनाएँ नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, जिससे पारिवारिक संरचना और सामाजिक सद्भाव में गिरावट आ रही है। उपभोक्तावाद, व्यवसायिकता और भौतिकवाद समाज के ताने-बाने को आकार दे रहे हैं, लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि उनका मूल्य उनके पास जो है उससे जुड़ा है, न कि वे कौन हैं। भौतिक सफलता की इस खोज ने कई लोगों को आध्यात्मिक रूप से दरिद्र बना दिया है, वे अपने भीतर से अलग हो गए हैं और सतही लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं जो स्थायी संतुष्टि प्रदान करने के लिए बहुत कम हैं।

वर्तमान रुझान हमें चिंता का कारण देते हैं, क्योंकि हम बढ़ते विभाजन, सामाजिक अशांति और हमारे पर्यावरण के क्षरण को देखते हैं। अब सवाल यह है: टूटने के बिंदु तक पहुँचने से पहले हम इस रास्ते पर कब तक चलते रह सकते हैं? ऐसे समय में, जब आत्म-नियंत्रण और संयम लगभग गायब हो गए हैं, और अतिवाद आदर्श बन गया है, हमें सीखना चाहिए कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को कैसे बहाल किया जाए। मूल्यों के साथ योग ध्यान, इन अशांत समयों को नेविगेट करने की हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। ध्यान हमें आत्म-नियंत्रण, शांति और संतुलन की स्थिति में लौटने में मदद कर सकता है। यह मन को शुद्ध करता है और शांति की हमारी गहरी प्यास को बुझाता है। ध्यान और नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की खेती के माध्यम से, व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से व्यस्त रहना सीख सकते हैं, फिर भी भौतिक लालसाओं से अलग रह सकते हैं। वे लालच और अतिरेक के आगे झुके बिना दुनिया में योगदान दे सकते हैं, भौतिक सफलता और आध्यात्मिक कल्याण के बीच संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। तो, आइए हम योग और ध्यान को एक दैनिक अभ्यास बनाएं, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने भीतर और अपने आस-पास की दुनिया में हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले अतिवाद से निपटने के लिए। केवल इस आंतरिक यात्रा के माध्यम से ही हम उस पवित्रता और शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो आज की तेज़-तर्रार, अति-जुड़ी दुनिया में इतनी मायावी लगती है।

आप की बात

मोदी का नेतृत्व

हरियाणा व जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणामों ने मोदी के नेतृत्व को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणामों ने जन-भागीदारी और बुलेट पर बैलेट को भारी बना दिया है। यह भारतीय लोकतंत्र की विजय है। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग बेशक जोर पकड़ रही है मगर वहां सत्ता की बागडोर संभालने वाले दलों के भीषणा पत्रों को देखते हुए फिलहाल कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना उचित नहीं होगा। यह दल पाक-परस्त हैं और उनके सत्ता में रहने से पाकिस्तानी आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। ऐसे में सत्ता के सूत्र उप-राज्यपाल के हाथों में ही सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति होने के बावजूद केजरीवाल ने जो गुल खिलाए हैं उससे सबक लेकर जम्मू कश्मीर की वर्तमान व्यवस्था बनाए रखना ही उचित होगा। जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल को अन्य पूर्ण राज्यों के राज्यपाल की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उप-राज्यपाल को ऐसे अधिकार देना उचित ठहराया है। उम्मीद करनी चाहिए कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनने वाली सरकार केन्द्र से टकराव के बजाय राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा उसके त्वरित विकास पर जोर देगी जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफी गति मिली है।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

यूरोपीय संघ पर संकट

31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने जो कारण बताकर यूरोपीय संघ की सदस्यता विधिवत छोड़ी थी, लगता है वही अब इस संगठन में टूट का कारण बनने जा रहा है। क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं व सांस्कृतिक कारणों के साथ लंबे समय से आर्थिक गिरावट से पीड़ित बहुत से लोग अप्रवासी-विरोधी और यूरोपीय संघ-विरोधी विचारों को अपनाने लगे हैं। आज भी संघ के भीतर कई देशों में यह विचार पनप रहा है कि यूरोपीय संघ की सदस्यता के कारण राष्ट्रीय संप्रभुता में कमी के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके साथ ही उनको जटिल नौकरशाही का सामना करना पड़ रहा है जिससे सांस्कृतिक और पहचान संबंधी चिंताएँ सताने लगी हैं, प्रवास संबंधी चिंताएँ बढ़ने लगी हैं तथा आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब यूरोपीय संघ के कई देश अंतरिक्ष सुरक्षा का हवाला देकर अपने अपने देश की सीमाओं को एक निश्चित समय के लिए बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। इनमें स्वीडन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, इटली, नॉर्वे व फ्रांस शामिल हैं। कई देश चीनी आयातों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी संघ के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

चुनाव परिणाम

हरियाणा व जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट है कि हरियाणा में भाजपा व जम्मू कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे है। हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल के उलट नतीजे दिए हैं। कांग्रेस 37 सीट पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने आश्चर्यजनक रूप से 48 सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी को बड़ा नुकसान कश्मीर संभाग में हुआ है जहां नेशनल कांफ्रेंस ने पीडीपी को भी पछाड़ते हुए बड़ी जीत हासिल की है। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में अप्रत्याशित रुख अख्तियार करते हुए कांग्रेस ने हरियाणा के परिणाम को सिरे से खारिज करते हुए शासन तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटायेगी। हरियाणा के चुनाव परिणामों को देखते हुए महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली व बिहार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। अब भाजपा अति-उत्साह से काम करेगी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के चुनाव सफलतापूर्वक बिना हिंसा के संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल, पुलिस तथा सेना व अर्धसैनिक बलों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

-वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

भाजपा की विजय

राजनीतिक विश्लेषक और एग्जिट पोल मैनेजर पक्षपातपूर्ण मिथकों के साथ भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद हरियाणा में भाजपा से एलर्जी थी। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा ने न केवल प्रचंड बहुमत हासिल किया है बल्कि उसके द्वारा विकास परियोजनाओं को दी गई गति भी मतदाताओं को बहुत पसंद आई है। इस प्रकार भाजपा बहुसंख्य जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी और देश में डबल इंजन वाली सरकारें सबसे ज्यादा पसंद की गई। सत्ता-विरोधी लहर भी राज्य में भाजपा को कमजोर नहीं कर सकी। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को पूरे राज्य में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए याद दिलाया कि हरियाणा राज्य बनने के बाद पहली बार दो कार्यकाल पूरे करने के बाद किसी पार्टी को ज्यादा सीटों और ज्यादा मत-प्रतिशत से जनता का आशीर्वाद मिला है। हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक विजय से उत्साहित कार्यकर्ता आगामी चुनावों में भी पार्टी को विजय दिलाएंगे।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 10 अक्टूबर 2024

AI पर नोबेल

साल 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कई वजहों से ध्यान खींच रहा है। 91 साल के अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन होपफील्ड और 76 साल के ब्रिटिश कनैडियन जैफ्री हिंटन को संयुक्त रूप से मिला यह पुरस्कार मशीन लर्निंग या AI के क्षेत्र में उनके अहम योगदान की वजह से दिया गया है, लेकिन इस पुरस्कार की घोषणा आज जीवन के हर क्षेत्र में AI के बढ़ते इस्तेमाल से आ रहे महत्वपूर्ण बदलावों को भी रेखांकित कर रही है।

तैयार की AI की जमीन | अगर इन दोनों वैज्ञानिकों के इस क्षेत्र में किए गए योगदान पर एक नजर डालें तो यह देखना दिलचस्प है कि कैसे उम्र के करीब डेढ़ दशक के फासले के बावजूद और एक-दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग काम करते हुए भी दोनों ने यह बात स्थापित कर दी कि मशीन सोच भले न पाए इंसानी दिमाग के पैटर्न की नकल करके याद रखने और सीखने के काबिल जरूर बनाई जा सकती है। उनकी बनाई हुई इसी नींव पर आगे चलकर AI को डिवेलप किया गया।

जॉन होपफील्ड जैफ्री हिंटन

आशंकाओं को भी दी आवाज | इसे लेकर आशंकाएं काफी पहले से जताई जा रही हैं। लेकिन जैसे-जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा, इससे जुड़ी भविष्य की संभावनाएं स्पष्ट होने लगीं वैसे ही वैसे इनके संभावित दुरुपयोग के खतरे भी ज्यादा ठोस रूप लेने लगे। स्थिति यह हो गई कि इस नोबेल पुरस्कार विजेता जोड़ी में से एक जैफ्री हिंटन जिन्हें AI का गॉडफादर कहा जाता रहा है, इसके संभावित खतरों से आगाह करने वाली प्रमुख आवाज बन गए।

इंसान से ज्यादा स्मार्ट | इन संभावित खतरों का एक पक्ष सच और झूठ की पहचान से जुड़ा है। हिंटन का भी कहना रहा है कि नए-नए AI टूल्स के इस्तेमाल का बढ़ता इस्तेमाल इंटरनेट पर कृत्रिम तस्वीरों और ऑडियो-विडियो क्लिपों की बाढ़ लाता जा रहा है। कुछ ही समय में इंटरनेट गलत सूचनाओं से इस कदर पटा नजर आ सकता है जिससे सच और झूठ की पहचान लगभग नामुमकिन हो जाए। इन खतरों का दूसरा पक्ष खुद इंसान की हैसियत से जुड़ा है। AI शारीरिक ही नहीं, बौद्धिक क्षमता में भी इंसान से आगे निकल सकता है। और इंसान को अपने से ज्यादा स्मार्ट प्रजातियों से निपटने का अनुभव नहीं है।

नया औजार | बहरहाल, AI का बढ़ता इस्तेमाल जिस तरह की सुविधाएं और सहूलियतें ला रहा है, चिकित्सा विज्ञान को नई बारीकियों से रू-ब-रू करा रहा है, उसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। जैसा कि नोबेल पुरस्कार समिति ने भी अपने बयान में कहा है, इन दोनों वैज्ञानिकों के कार्यों की बदौलत इंसानियत के टूल बॉक्स में एक नया औजार आ गया है और भविष्य में इसका प्रभाव-दुष्प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इंसान इस बेहद संभावनाशील औजार को किस हद तक और किस रूप में उपयोग में लाते हैं।

साड्डी दिल्ली

रेखा की ससुराल

विवेक शुक्ला

मुमकिन है कि अपने 70वें जन्मदिन पर मुंबई में अपने विशाल बांद्रा बैंड स्टैंड के बंगले से बाहर सागर की लहरों को देखते हुए रेखा को आज दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड के 3 नंबर बंगले का ख्याल भी आए। करीब 34 साल पहले रेखा इसी फ्लैग स्टाफ रोड में बहू बनकर आई थीं। वह तब अपने फिल्मी करियर के पीक पर थीं। रेखा ने मुकेश अग्रवाल नाम के एक यंग बिजनेसमैन से शादी करके सनसनी पैदा कर दी थी। यह शादी 4 मार्च, 1990 को हुई थी। मुकेश हॉटलाइन कंपनी के डायरेक्टर थे। वह दिल्ली की एक बिजनेस फैमिली से थे। मशहूर सोशलाइट बीना रमानी की मार्फत रेखा-मुकेश साउथ दिल्ली के एक फार्म हाउस में पार्टी में मिले थे। कुछ मुलाकातों के बाद ही मुकेश ने रेखा को अपना दिल दे दिया था। फिर एक दिन उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रेखा शादी के लिए तैयार भी हो गईं। मुकेश-रेखा की शादी तुरंत करवाने में मुकेश के बड़े भाई अनिल अग्रवाल का अहम रोल था। उन्हें सिविल लाइंस और फ्लैग स्टाफ रोड में सब अनिल मामा कहते थे। अनिल मामा ने अपने छोटे भाई की सुपरस्टार से शादी की खुशी में अपने फॉर्म हाउस में शानदार पार्टी दी। उसमें करीब तीन हजार मेहमान शामिल हुए। अफसोस कि रेखा-मुकेश की शादी में शुरू से ही ग्रहण लग गया। इनमें दूरियां बढ़ने लगीं। मुकेश अग्रवाल की पड़ोसी और सेसर बोर्ड की मेंबर रहीं डॉ. अरुणा मुकिम दावा करती हैं कि रेखा-मुकेश में खटास हनीमून से ही चालू हो गई थी। तब रेखा किसी शो में भाग लेने के लिए मुंबई जाना चाहती थीं। मुकेश चाहते थे कि रेखा उनके पास दिल्ली में ही रहें। पर रेखा नहीं मानीं। इसके बाद मुकेश डिप्रेशन में चले गए और फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। इनकी शादी सिर्फ सात महीने तक चली थी। कहने वाले कहते हैं कि मुकेश की मृत्यु के बाद भी रेखा अपनी ससुराल नहीं आईं जिससे मुकेश के परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा लगा था। हालांकि अग्रवाल परिवार मुकेश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रेखा के नाम करना चाहता था। रेखा के व्यवहार के कारण उन्होंने भी अपना इरादा बदल लिया। मुकेश अग्रवाल की असामयिक मौत के बाद अनिल मामा का भी निधन हो गया, फिर उनके परिवार ने फ्लैग स्टाफ रोड का घर भी छोड़ दिया। अब तो यहां के गिनती के ही लोग बता पाते हैं कि रेखा कभी यहां बहू बनकर आई थीं।

Subrata Dhar

एकदा

अदालतों में हिंदी

1897 की बात है। उस समय कचहरियों और स्कूलों में उर्दू और फारसी चलती थी। दस्तावेजों की लिखा-पढ़ी हिंदी में नहीं थी। उर्दू या फारसी न जानने वालों के लिए दस्तावेज काला अक्षर भैंस बराबर था। जरूरी होने पर उन्हें पढ़कर मुवक्किल को सुना दिया जाता था। ऐसे में जरूरत थी कचहरी में देवनागरी लिपि के प्रयोग की, जिससे हिंदी में साक्षर लोग कम के कम दस्तावेजों को पढ़ तो सकें। काम आसान न था क्योंकि इसके लिए शासनादेश की जरूरत थी और मुगलों के बाद अंग्रेज, अंग्रेजी को बढ़ावा देने में लगे थे। ऐसे में हिंदी लागू कराने का बीड़ा पंडित मदनमोहन मालवीय ने उठाया। उन्होंने एक याचिका तैयार की। याचिका पर साठ हजार लोगों के दस्तखत करवाए। फिर उन्होंने अवध के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी पैट्रिक मैक्डोनल्ड के यहां याचिका दायर की और निवेदन किया कि कचहरी के दस्तावेज देवनागरी में लिखे जाने के लिए शासनादेश दें। उनकी याचिका गवर्नर ने स्वीकार कर ली, लेकिन इस पर निर्णय देने के लिए तैयार नहीं हुए। उधर मदन मोहन मालवीय भी हार मानने वालों में नहीं थे। हिंदी प्रेम व जनहितकारी वकालत की उनकी लगन आखिरकार रंग लाई। तीन वर्ष पश्चात गवर्नर ने आदेश जारी किया कि कचहरी और स्कूलों में देवनागरी का प्रयोग हो। धीरे-धीरे कचहरियों और स्कूलों में देवनागरी ने जगह लेनी शुरू कर दी। इससे निचले पायदान के लोगों को आभास हुआ कि उनकी भाषा शासन की भाषा बन गई है। आज अगर अदालतों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो उसमें बड़ा हाथ पंडित मदन मोहन मालवीय का भी है।

Subrata Dhar

संकलन : हरिप्रसाद राय

हरियाणा की हार से महाराष्ट्र-झारखंड की चुनावी संभावनाओं पर विपरीत असर के आसार

कांग्रेस पर हावी होंगे गठबंधन के साथी?

आसिम अली

हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी असफलता साबित हुए हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के अहम विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने इसके पहले खुद को कमजोर स्थिति में ला दिया है।

हुड्डा पर भरोसा | कांग्रेस ने इस चुनाव की कमान एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा गुट को सौंप दी थी। पार्टी ने हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन यह साफ था कि संभावित चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। इसकी उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि हुड्डा गुट ने 90 में से 72 सीटों पर अपने करीबियों को टिकट दिलाया था। हरियाणा कांग्रेस में किसी एक गुट का इस हद तक नियंत्रण बिल्कुल नई बात है।

बड़े नाम बाहर | पिछले पांच बरसों में हुड्डा परिवार ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को या तो पार्टी से बाहर कर दिया या फिर उनके प्रभाव को खत्म कर दिया। उदाहरण के लिए कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर और किरण चौधरी का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा। हालांकि चुनाव से ठीक पहले तंवर की वापसी हो गई थी। इसी तरह, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव घटता गया।

गुटबाजी का फायदा | कांग्रेस में विभिन्न गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा का फायदा यह है कि इससे पार्टी को अलग-अलग जाति और क्षेत्र के जटिल समीकरणों को साधने में मदद मिलती है। साथ ही, उसकी छवि एक ऐसे दल के रूप में बनती है, जिसके तहत हर तरह के लोग काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गुटों का टकराव संतुलन लाने में मदद करता है, मसलन जाट नेताओं के प्रभाव के सामने OBC और दलित नेताओं को लाना।

कमजोर रणनीति | इस बार कांग्रेस की रणनीति में कुछ कमजोरियां थीं, जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ा। इसमें एक गलती यह रही कि हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाने और बाकी नेताओं को कोर नजरअंदाज करने से BJP को जाट बनाम गैर-जाट का नैरेटिव आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। यह याद रखना चाहिए कि राज्य में जाटों की आबादी केवल 19% है। जाट दबदबे का डर दिखाकर BJP ने अपने मुख्य वोट बैंक, अगड़ी जातियों और OBC को एकजुट किया।

दलित रहे दूर | हरियाणा में दलित वोट बैंक कुल आबादी का लगभग 21% है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस इसका फायदा नहीं उठा पाई। INLD-BSP गठबंधन को 6% वोट शेयर मिलना दिखाता है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के अभियान से दूरी बनाए हुए था। आखिरी चरण को छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनाव प्रचार से कुमारी सैलजा गायब रहीं। इससे भी कांग्रेस के पक्ष में दलितों को जुटाने में मुश्किल हुई।

बागियों की चुनौती | बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में बहुत चुनौती पेश की और कांग्रेस की रणनीति इसका सामना करने में नाकाम रही। चुनाव में कांग्रेस के 36 बागी नेता खड़े थे। वहीं, BJP के 33 नेताओं ने बागी रुख अपनाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी ने इन बागियों को संभाला कैसे।

हार की वजह
- हुड्डा गुट को चुनावी कमान सौंपना
- दलित वोटों में BJP की सेंधमारी
- केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर रुख

वोट शेयर | दोनों पार्टियों का कुल वोट शेयर लगभग समान था, करीब 40%। लेकिन, औसत वोट शेयर के मामले में BJP ने कांग्रेस पर काफी बढ़त हासिल कर ली। यहां BJP का डेटा रहा 45% और कांग्रेस का 40% (आंकड़े मंगलवार देर शाम तक के आधार पर)। औसत वोट शेयर का मतलब है एक खास निर्वाचन क्षेत्र में किसी पार्टी को मिला वोट शेयर। कांग्रेस को कई कड़ी टक्कर वाली सीटों पर हार मिली। इसकी वजह शायद निर्दलीय रहे, जिन्होंने 10% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए या फिर INLD-BSP का गठबंधन।

नेतृत्व पर असर | इस हार ने कमजोर हाईकमान की समस्या को उजागर कर दिया है, जो उग्रदराज नेताओं के दबाव में झुक जाता है। G23 विद्रोह में हुड्डा भी शामिल थे। सोनिया गांधी उनकी मांगों के आगे झुक गईं और हरियाणा में पार्टी से जुड़े मामलों पर उन्हें पूरी तरह नियंत्रण दे दिया। ऐसा ही मामला राजस्थान में हुआ, जहां अशोक गहलोत ने एक सफल बगावत की। फिर मध्य प्रदेश का भी उदाहरण है। वहां पुराने नेता कमलनाथ ने युवा नेताओं को उभरने से रोका। इन सभी राज्यों में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।

गठबंधन में कमजोर | गांधी परिवार इस असफलता की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। छोटे-से राज्य हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए तो पिछले 6 बरसों में कांग्रेस पार्टी विध्यांचल के उत्तर में किसी भी राज्य में BJP को सीधे मुकाबले में नहीं हरा पाई है। अगले साल महाराष्ट्र में NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, झारखंड में JMM, दिल्ली में AAP और बिहार में RJD से सीटों के तालमेल पर बात करते हुए कांग्रेस की स्थिति कमजोर रहेगी। यानी I.N.D.I.A. ब्लॉक की मजबूत दीवार बनने के बजाय कांग्रेस को फिर से क्षेत्रीय दलों के सामने झुक कर काम करना पड़ेगा।

इस्राइल की अजेय दीवार

चौतरफा जंग लड़ रहे इस्राइल पर कई मिसाइल अटैक हो चुके हैं। हाल में, ईरान ने भी इस्राइल को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। कैसा है वह एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कोई हमला भेद नहीं पा रहा? क्या भारत भी इस तरह की सुरक्षा प्रणाली अपना सकता है?

180 मिसाइलों से हमला किया था ईरान ने एक दिन में नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने को, हमास हजारों हवाई हमले कर चुका।

87% लगभग सक्सेस रेट है मौजूदा जंग में इस्राइल के एयर डिफेंस सिस्टम का, इन टारगेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया गया।

2000
Arrow 2 सिस्टम एक्टिव। Arrow 3 को 2017 में तैनात किया। खाड़ी युद्ध से काम शुरू हुआ इन पर।

2011
से सुरक्षा कर रहा आयरन डोम। 2006 में हिज्बुल्लाह के साथ हुई जंग के बाद सिस्टम की जरूरत महसूस हुई।

2017
David's Sling एक्टिव। राफेल अडवांस्ड डिफेंस सिस्टम-अमेरिका की Raytheon ने बनाया है।

सुरक्षा की भारी कीमत

$6 बिलियन से ज्यादा खर्च हुआ एक साल में आयरन डोम पर

$1,50,000 कीमत है एक Tamir मिसाइल इंटरसेप्शन की

$8,00,000: David's Sling की एक मिसाइल

$3.5 मिलियन: कीमत Arrow सिस्टम के एक इंटरसेप्शन की

3 स्तरीय एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इस्राइल के पास

0KM — 1,000KM — 2,000KM

IRON DOME
इस कम दूरी के रॉकेट मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल लॉन्चर से 70 किमी की दूर तक कारगर।

DAVID'S SLING
लंबी दूरी के रॉकेटों, क्रूज मिसाइल से सुरक्षा देता है। टारगेट को 300 किमी दूर ही मार गिरा सकता है। डिवेलपमेंट का काम अब भी चल रहा है।

ARROW SYSTEM
सबसे बाहरी लेयर, इसके तहत Arrow 2-3 सिस्टम। मारक क्षमता 2400 किमी। मध्यम, लंबी दूरी की मिसाइलों से निपटने में सक्षम।

दुनिया के टॉप एयर डिफेंस सिस्टम

विक्ट्री एस-400 : रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। मल्टिफंक्शनल है, 56 किमी की दूरी पर टारगेट को मार गिरा सकता है।

MIM-104 पैट्रियट : 170 किमी की दूरी और 24 किमी एल्टीट्यूड तक मार। अमेरिका में बनी, उसके सहयोगी देश भी इस्तेमाल करते हैं।

S-300VM : इसे Antey-2500 भी कहते हैं, रूसी कंपनी ने डिवेलप किया। 200 किमी की दूरी और 30 किमी ऊंचाई तक मारक।

THAAD : अमेरिकी सिस्टम, पूरा नाम- टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। 150 किमी तक की ऊंचाई तक लक्ष्य भेदने में सक्षम।

Aster 30 SAMP/T : यूरोपीय मैन्युफैक्चरर Eurosam ने डिवेलप किया है। एक मोबाइल एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है।

क्या भारत भी बना सकता है अपना 'आयरन डोम'?

दिक्कत भारत की विशालता

- **149 गुना** बड़ा है भारत का आकार इस्राइल से
- **147 गुना** ज्यादा है भारत की आबादी इस्राइल से
- **15 गुना** ज्यादा लंबी है भारत की जमीनी सीमारेखा इस्राइल की तुलना में
- **27 गुना** अधिक है भारत की कोस्टलाइन इस्राइल से

कंटेंट : शैलेंद्र पांडेय
ग्राफिक्स : अर्जुन सिंह

जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट 'पुष्कर' से बेहतर?

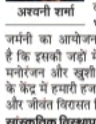

अश्वनी शर्मा

जर्मनी में अभी-अभी अक्टूबर फेस्ट संपन्न हुआ है। यह महीना हमारे यहां विश्व विख्यात पुष्कर मेले और बस्तर के दशहरे की तैयारी का भी है। पुष्कर मेले से जर्मनी का आयोजन इस मायने में भिन्न है कि इसकी जड़ों में संस्कृति नहीं, बल्कि मनोरंजन और खुशी है। वहीं, पुष्कर मेले के केंद्र में हमारी हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और जीवंत विरासत निहित है।

सांस्कृतिक विस्थापन | विडंबना यह है कि हम धीरे-धीरे संस्कृति से महज मनोरंजन पर केंद्रित होते जा रहे हैं, जबकि यूरोपियन इसे अपनी मजबूत सांस्कृतिक पहचान बनाने में जुटे हैं। यह सांस्कृतिक बदलाव नहीं बल्कि सांस्कृतिक विस्थापन है। जहां हम अपने सांस्कृतिक रंग खो रहे हैं, वहीं जर्मनी में यह रंग अपनी पूरी चमक के साथ फिजां में घुल रहा है। जर्मन लोगों के उत्साह को देखते हुए पूरा यूरोप यहां जुटने लगा है। अब यह फेस्ट महज जर्मनी का न होकर पूरे यूरोप का हो गया है। दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला सिमटता जा रहा है।

शादी के जश्न से शुरुआत | अक्टूबर फेस्ट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। महज 188 वर्ष हुए हैं उसे। 12 अक्टूबर 1810 को जर्मनी के एक राज्य बवेरिया के राजकुमार लुडविग (जो बाद में किंग लुइस प्रथम कहलाया) की शादी थी। लुडविग ने अपनी शादी के जश्न में शामिल होने के लिए पूरे शहर को आमंत्रित किया था। इस जश्न में पूरे 15 दिन फोक म्यूजिक बजाया गया। घोड़ों की रेस भी आयोजित की गई थी। तभी से लगभग हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। सितंबर 21 से अक्टूबर के प्रथम रविवार तक यह फेस्टिवल मनाया जाता है।

घुमंतू समुदायों का ठिकाना | पुष्कर मेला कितने हजार वर्ष पुराना है, यह कहने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं। दरअसल इसे किसी संस्था ने या किसी रजवाड़े ने नहीं शुरू किया। इसकी शुरुआत तमाम घुमंतू समुदायों ने अपने मिलने-जुलने, दुख-सुख साझा करने के एक ठिकाने के रूप में की थी। ऐसा ठिकाना, जहां वे अपने मुद्दे सुलझा सकें, शादी-ब्याह तय कर सकें। यह स्थान बना पुष्कर, जो व्यापारिक मार्ग पर स्थित था।

पशुओं की अदला बदली | पुष्कर में तमाम पशुचारक समुदाय (जैसे रायका रेबारी, बागरी), व्यापारी समुदाय (जैसे बंजारे और लबाना), ट्रेडिशनल हीलर्स (जैसे कालबेलिया, गोंड चितोड़िया, पारधी), शिकारी समुदाय (वन बागरिया), मनोरंजन वाले समुदाय (कलंदर, मदारी), मिट्टी के जानकार (कुंचिया) मिलते हैं। यहां पशुओं की अदला-बदली होती है, जिसे आटा साटा बोला जाता है। इससे खेती के लिए उन्नत नस्ल के पशु कम दाम में मिल जाते हैं।

कॉमन रूम

नाचने-गाने का जमघट | ये सामाजिक पक्ष जर्मनी के फेस्ट के साथ नहीं जुड़े हैं। वह केवल मनोरंजन का केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों से पुष्कर के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। उसे महज नाचने-गाने वाला एक जमघट मानने का चलन बढ़ता जा रहा है। पुष्कर मेले से फोक म्यूजिक को गायब कर दिया गया है। मोटी फीस देकर बंबईया कलाकार आमंत्रित करते हैं। वहां कालबेलिया नृत्य के बजाय अधिकारी लोग कॉलेज की लड़कियों को इकट्ठा कर, घूमर नाच करवाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा लेना बेहतर समझते हैं।

बदलता स्वरूप | पुष्कर मेले की शुरुआत ऊंट की शोभायात्रा से हुआ करती थी। उनके पीछे-पीछे रबारी लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में चलते थे। भोपा लोग, अपने लोक वाद्य रावण हत्थे की मधुर धुन सुनाते। पशुओं की सुंदरता की प्रतियोगिताएं होतीं। घोड़े और ऊंट की रेस होती। किंतु धीरे-धीरे यह सब गायब हो गया।

विकल्प नहीं | हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, लोक कलाएं और उनका आपसी सामाजिक संयोजन, सभी इस मेले से जुड़ा है। जब पुष्कर मेले से लोक कलाएं गायब कर दी जाएंगी, ऊंट को गैर जरूरी मान लिया जाएगा, तो बचेगा क्या? आने वाली पीढ़ियां शर्मिंदा होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे पुरखों की संस्कृति को तमाशे की बलि चढ़ा दिया गया।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

सफलता आपकी न मुरझाने वाली मुस्कुराहट है

श्री श्री रवि शंकर

यदि आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं तो अपने पुराने समय को याद करें और देखें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब आपको चिंता हो रही है। आप पहले भी चिंतित हुए हैं। पहले आप कॉलेज में प्रवेश के लिए चिंतित थे, उसके बाद आपको नौकरी की चिंता हुई। आपने अपने ऊपर संदेह और चिंता के उन सभी क्षणों को पार कर लिया और इसी तरह आप वर्तमान में हो रही चिंता से भी पार हो जाएंगे।

युवाओं को अपने भविष्य के लिए बड़े स्वप्न देखने चाहिए और अपनी मौलिक भावनाओं पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग चिंता करते हैं, वे बड़े सपने नहीं देख पाते। यदि आप यही सोचते रहेंगे कि इस दुनिया से आपको क्या मिलने वाला है, तो चिंता का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन यदि आप यह सोचते हैं कि 'मैं समाज में योगदान कैसे दे सकता हूं, मैं देश की अर्थव्यवस्था उन्नत करने में सहायता कैसे कर सकता हूं, लोगों को एकजुट करने में कैसे मदद कर सकता हूं' तो यह विचार प्रक्रिया आपको छोटी-छोटी चिंताओं से उबरने में सहायता करेगी।

आज दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य संकट ने दो चरम रूप ले लिए हैं- लोग या तो अवसाद या फिर आक्रामकता और हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। युवाओं को इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट होना चाहिए और दूसरों को अवसाद और आत्मघाती विचारों से उबरने में मदद करनी चाहिए। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के इस युद्ध में 'ध्यान' और 'सुदर्शन क्रिया' जैसी प्रभावशाली तकनीकें आपको तनाव से राहत देती हैं और मन को शांत करती हैं। एक बार जब लोगों की जीवनी शक्ति ऊपर उठती है और वे मन को शांत करना सीख जाते हैं, तब वे पाते हैं कि प्रसन्नता कोई बाहरी घटना नहीं है। यह तो उनका स्वभाव है।

बहुत सारे युवा सफल होना चाहते हैं। सफल होने का क्या अर्थ है? एक अटूट आत्मविश्वास और एक ऐसी मुस्कुराहट जो कभी न मुरझाए, वही सफलता है। यदि आप सफलता को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप में परिभाषित करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपनी क्षमता से अपरिचित हैं। सूक्ष्मतासे देखें तो आपने अपनी क्षमताओं को कम आंका होगा, क्योंकि आपने जो 'प्राप्त' किया है वह हमेशा आपसे और आपकी क्षमता से कम होता है।

जीवन को एक खेल की तरह लें। खेल में चाहे जीतें या हारें, आप फिर भी इसका आनंद लेते हैं। जीवन में इतना गंभीर होने जैसा कुछ भी नहीं है। घटनाओं और परिस्थितियों से सबक लें और आगे बढ़ें। पूर्ण स्वतंत्रता की भावना होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। यह चिंता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको स्वतंत्र होने से रोकती है। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

प्राणायाम, योग और ध्यान का नियमित अभ्यास आपके मस्तिष्क को चिंता करने की आदत से बाहर निकाल सकता है। ये आपको अधिक सहज और मेधावी बनाते हैं। इस तरह आध्यात्मिकता आपके व्यक्तित्व और रचनात्मकता को खिलने का अवसर देती है। जीवन अच्छे-बुरे अनुभवों का मिश्रण है। आप केवल एक प्रकार के अनुभव की कामना नहीं कर सकते। जीवन के सभी अनुभवों को समग्रता से ग्रहण करें, तभी आप वास्तव में जीवन का उत्सव मना सकते हैं।

[illegible]

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 202

स्पष्ट प्रतिबद्धता

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नए बाहरी सदस्यों के साथ इस सप्ताह नीतिगत समीक्षा की। उसने यह निर्णय लिया कि वह नीतिगत रीपो दर को 6.5 फीसदी के स्तर पर अपरिवर्तित रखेगी। परंतु एमपीसी ने नीतिगत रुख को समायोजन वापस लेने से बदलकर तटस्थ करने का निर्णय लिया ताकि कुछ बाजार सहभागियों की अपेक्षा के अनुरूप स्वयं को अधिक लचीला बना सके। परंतु इस बदलाव को वित्तीय बाजारों को ऐसे किसी संकेत के रूप में नहीं देखना चाहिए कि दिसंबर में होने वाली बैठक में नीतिगत दरों में कटौती हो सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित कुछ बड़े केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों में कमी की है लेकिन एमपीसी का नीतिगत प्रस्ताव और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का वक्तव्य स्पष्ट संकेत देता है कि भारतीय केंद्रीय बैंक महंगाई दर घटने की प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रतीक्षा करने का इच्छुक है।

आरबीआई ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने और रुख में बदलाव की बात को सही ढंग से संप्रेषित किया। यद्यपि मुद्रास्फीति का परिदृश्य अधिक अनुकूल हुआ है लेकिन एमपीसी केवल इसलिए कदम नहीं उठाना चाहती है क्योंकि बड़े केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों में कमी की है और भविष्य में और सरलता अपनाने के संकेत दिए हैं। यह सही है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर हाल के महीनों में कम हुई है, ऐसा आंशिक रूप से आधार प्रभाव के कारण हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आधार प्रभाव के कारण ही सितंबर में इसमें एक बार फिर उछाल आएगी।

खरीफ सत्र में अच्छी उपज के चलते चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अच्छा मॉनसून और जलाशयों का उच्च जल स्तर भी रबी के उत्पादन में मददगार होगा। चूंकि शीर्ष मुद्रास्फीति दर उच्च खाद्य कीमतों से संचालित है इसलिए उत्पादन में बढ़ोतरी से दबाव कम होने की आशा है। एमपीसी का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर औसतन 4.5 फीसदी रहेगी। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर के और कम होकर 4.3 फीसदी रहने का अनुमान है।

चूंकि मौद्रिक नीति की प्रकृति अग्रगामी है और उसका प्रभाव ठहरकर होता है इसलिए दरों से संबंधित निर्णय अगले वित्त वर्ष की शेष तिमाहियों के अनुमानों पर निर्भर होगा। रिजर्व बैंक के आधारभूत मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान की बात करें तो 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए वह 4.1 फीसदी है। इसका उल्लेख मौद्रिक नीति रिपोर्ट में है जिसे बुधवार को अन्य नीतिगत दस्तावेजों के साथ जारी किया गया। चूंकि उक्त आंकड़ा चार फीसदी के लक्ष्य के करीब है इसलिए यह आने वाले महीनों में रियायत की गुंजाइश पैदा कर सकता है। बहरहाल, यह भी कई कारकों पर निर्भर करेगा। इस संदर्भ में पिछले कुछ सप्ताह में अनिश्चितता बढ़ी है। भूराजनीतिक तनाव आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं और यह बात मुद्रास्फीति पर असर डाल सकती है। चूंकि एमपीसी का अनुमान है कि वृद्धि मजबूत बनी रहेगी इसलिए उसके पास अवसर है कि वह इंतजार करे और हालात पर नजर रखे। रुख में बदलाव एमपीसी को यह विकल्प देता है कि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय हालात में उल्लेखनीय गिरावट आने पर वह जल्द कदम उठा सके।

नीतिगत निर्णय के अलावा दास ने कम से कम दो ऐसी घोषणाएं कीं जिनका यहां उल्लेख करना उचित है। पहली, कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इक्विटी पर उच्च रिटर्न की तलाश में हैं। इस प्रक्रिया में ऋण मानक और ग्राहक सेवा के साथ समझौता होता दिख रहा है। यह वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। रिजर्व बैंक ने ऐसे संस्थानों के प्रोत्साहन ढांचे की समीक्षा करने का सुझाव देकर सही किया है। दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन जो वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, उसे लेकर आरबीआई ने डेटा रिपॉजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे विनियमित संस्थानों को जलवायु जोखिम का आकलन करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह पहल कैसे आगे बढ़ती है यह भी देखना होगा। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

अमेरिकी चुनावों का भारत पर कैसे हो सकता है असर

अमेरिकी चुनाव के बाद भारत के सामने नई और अलग चुनौतियां खड़ी होंगी और ये चुनौती कौन सी होंगी, यह चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। बता रहे हैं अजय छिब्बर

अमेरिका में 5 नवंबर तक नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और चुनाव परिणाम का अमेरिका ही नहीं भारत समेत पूरी दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। कमला हैरिस जीतीं तो वह कई नए रिकॉर्ड बनाएंगी - इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वह पहली अश्वेत महिला होंगी और अमेरिका की राष्ट्रपति बनने वाली भारतीय मूल की पहली शख्सियत होंगी। उनकी जीत अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के उभार का सबसे बड़ा प्रतीक होगी। वह अपने कार्यकाल में कुछ बदलाव जरूर ला सकती हैं मगर मोटे तौर पर वह अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगी। हां, अगर डॉनल्ड ट्रंप दूसरी दफा राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका की नीतियों और रुख में बड़ा बदलाव हो सकता है।

जैसा ट्रंप ने स्वयं कहा है, वह एक समझौता कराएंगे और यूक्रेन में युद्ध खत्म करा देंगे। रूस ने अब तक जितने इलाके पर कब्जा किया है, समझौते के बाद उसमें से ज्यादातर शायद उसी का हो जाएगा। युद्ध की शुरुआत में भारत को तेल और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का झटका लगा था मगर बाद में रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसने इस पर काफी हद तक काबू पा लिया।

ट्रंप में दूरअंदेशी की कमी और छोटे फायदों के पीछे भागने की आदत से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) फिर कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसके सदस्य देश पर हमला होने की सूरत में मदद मिलने की गारंटी नहीं होगी। किंतु हैरिस का रुख यूक्रेन और नाटो मामले में बाइडन प्रशासन जैसा ही रहेगा। पश्चिम एशिया में ट्रंप इजरायल को खुला समर्थन देते हैं और जो भी हो जाए, उसका समर्थन करते रहेंगे। हैरिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य दो-राष्ट्र समाधान की हिमायती हैं और बाइडन की तुलना में उनका रुख सख्त होगा। लेकिन युद्ध से निपटने में बाइडन का बुलमुल रवैया चुनाव से पहले ही बड़े युद्ध का कारण बन सकता है।

ट्रंप अमेरिका को एक बार फिर पेरिस समझौते से बाहर कर सकते हैं और ऊर्जा कंपनियों को मनचाहे तरीके से काम करने की छूट दे सकते हैं, जैसा वह कहते रहे हैं। इससे तेल सस्ता होगी और भारत को फायदा मिलेगा किंतु जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में चल रही कोशिशें कमजोर होंगी। वह 2025 में खत्म हो रही कर कटौती को भी आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाएगा। शुल्क में बड़े इजाफे की भी उनकी योजना है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने लगभग 300 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क लगाया था, जिसे बाइडन ने भी राष्ट्रपति बनने पर बरकरार रखा था। इस बार उन्होंने चीन पर 60 प्रतिशत शुल्क लगाने और लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर के आयात पर 10-20 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले इतना भारी शुल्क 1930 के स्मूट-हॉली टैरिफ एक्ट में देखा गया था। आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने की इन नीतियों ने वैश्विक व्यापार में होड़ बढ़ाई थी और वैश्विक मंदी गहरा गई थी।

अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। इसलिए भारत का हित अधिक खुली विश्व व्यापार व्यवस्था में है, व्यापार युद्ध में नहीं। भारत और अमेरिका के करीबी संबंधों के बाद भी ट्रंप की राष्ट्रवादी आर्थिक सोच अमेरिका के साथ व्यापार में भारत को होने वाले मामूली से अधिशेष पर लगी रह सकती है। ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ किंग' कहा और भारत से होने वाले स्टील आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क तथा एल्यूमीनियम पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया। मजबूर होकर भारत को भी अमेरिका से आने वाली 28 वस्तुओं पर ऊंचा शुल्क लगाना पड़ा। भारत के शुल्क अब और भी अधिक हैं और दवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वह चीन के मध्यवर्ती उत्पादों पर काफी निर्भर है, जिनमें नया आईफोन भी शामिल है। इसलिए दुनिया में व्यापार युद्ध छिड़ा तो भारत और भी जोखिम में पड़ जाएगा।

हैरिस का पूरा जोर लघु कारोबारों की मदद करने और रोजगार तैयार करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने पर होगा। वह चाइल्ड टैक्स क्रेडिट (17 साल से कम उम्र का बच्चा होने पर परिवार को कर में छूट) जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर ध्यान देंगी, जिससे गरीबी में तेजी से कमी की है। वह कॉरपोरेशन करों को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करेंगी, अमीरों के लिए आयकर दर बढ़ाकर करीब 40 प्रतिशत करेंगी (जितनी बिल क्लिंटन के कार्यकाल में थी) और पूंजीगत लाभ कर भी बढ़ाएंगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2018 में जब ट्रंप ने कॉरपोरेशन कर घटाकर 21 प्रतिशत किया था तब भारत ने भी इस कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर दी थी। मगर अमेरिका में इस कटौती से निवेश तो नहीं बढ़ा बल्कि शेयर बायबैक में बहुत तेजी आ गई। उम्मीद करते हैं कि भारत में इसका परिणाम बेहतर रहेगा।

इन सबको मिलाकर देखें तो ट्रंप के आर्थिक प्रस्तावों से अमेरिका पर चढ़े कर्ज में 4-5 लाख करोड़ डॉलर की वृद्धि हो सकती है। लेकिन हैरिस चुनी गईं तो कर्ज 1 से 2 लाख करोड़ डॉलर ही बढ़ेगा। ट्रंप फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं और डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों में वृहद अर्थव्यवस्था का प्रबंधन जटिल हो जाएगा।

हैरिस चीन पर सख्त रुख अपना सकती हैं जहां सैन्य तकनीकों के निर्यात पर बाइडन प्रशासन के प्रतिबंध ने चीन को अल्पावधि में तो नुकसान पहुंचाया ही है और यह नुकसान ट्रंप के शुल्कों से हुए नुकसान की तुलना में ज्यादा है। उनकी अगुआई में जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका का पुराना रुख बना रहेगा और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। वह चिप निर्माण आदि को भी बढ़ावा दे सकती हैं, जिनसे भारत को फायदा हुआ है। हैरिस चीन पर शुल्क और भी बढ़ा सकती हैं, जैसा हाल में देखा गया, जब चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत और सोलर पैनल पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया गया।

ट्रंप आव्रजन पर सख्त रुख अपना सकते हैं, जिससे एच1-बी वीजा पर प्रतिबंध और सख्त हो जाएंगे। इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक वीजा भारतीयों को ही जारी किए जाते हैं। इसमें 2,000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने से फायदा हुआ है। अब ये शोध एवं नवाचार का केंद्र बन गए हैं और इनमें करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन विनिर्माण चीन में पहुंचने और उसकी वजह से रोजगार खत्म होने के जैसे विरोध ने 2016 में ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचा दिया था, भारत में आउटसोर्स किए गए रोजगार पर भी वैसा ही विरोध हो सकता है, चाहे सत्ता में कोई भी आए।

चीन का मुकाबला करने के लिए दोनों ही भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा एवं प्रौद्योगिकी संबंध बढ़ा सकते हैं। भारत को भी इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में अमेरिका का अधिक सहयोग करना चाहिए। क्वाड जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल थी, जिसे ट्रंप ने 2017 में फिर जीवित कर दिया था। भारत को बाइडन प्रशासन की पहल वाले 14 देशों के इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) और अफ्रीका समेत दूसरे हिस्सों के साथ गठजोड़ पर भी जोर देना चाहिए। चीन के साथ सीमा समझौते की कोई संभावना नहीं होने के कारण भारत ने पिछले महीने क्वाड की बैठक में विभिन्न पक्षों के साथ अपना संपर्क बढ़ाया और आईपीईएफ के चार में से तीन स्तंभों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन व्यापार स्तंभ से जुड़ा कोई समझौता नहीं किया।

व्यापार समझौता न होने पर भी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में अकूत संभावनाएं हैं तथा वर्ष 2030 तक यह 500-600 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और आईटी सेवाओं, प्रसंस्कृत खाद्य, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक और रक्षा उत्पादन की बड़ी हिस्सेदारी होगी। वर्ष 2047 तक आधुनिक देश बनने की भारत की महत्त्वाकांक्षा अमेरिका के साथ घनिष्ठ आर्थिक, तकनीक और रक्षा सहयोग पर निर्भर है चाहे सत्ता में कोई भी आए। लेकिन राष्ट्रपति कौन बनता है, इसके आधार पर नई और अलग किस्म की चुनौतियां होंगी, जिनसे निपटने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षक हैं और हार्पर-कॉलिंस इंडिया से 2021 में प्रकाशित 'अनशैकलिंग इंडिया' के सह लेखक भी हैं)

हथियारों की बिक्री में कैसे आए और तेजी?

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात 22,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच गया। निर्यात की यह रकम 2013-14 से अब तक 31 गुना बढ़ चुकी है और इस वृद्धि में किसी तरह की सुस्ती की संभावना भी नहीं है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में निर्यात 32.5 फीसदी गुना बढ़ा है। 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 3,885 करोड़ रुपये से 78 फीसदी अधिक था।

पिछले दिनों रक्षा निर्यात को और गति मिली, जब निजी क्षेत्र की देसी रक्षा विनिर्माता टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने मोरक्को की रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के साथ समझौते की घोषणा की। इस समझौते के तहत मोरक्को की सेना के जवानों को ले जाने के लिए बख्तरबंद वाहन बनाए जाएंगे। इन्हें व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स या व्हाप 8x8 कहा जाता है। इन्हें मोरक्को के कासाब्लांका में बनाया जाएगा। यह पहला मौका है, जब कोई भारतीय रक्षा विनिर्माता देश से बाहर रक्षा विनिर्माण कारखाना लगा रही है। यह मोरक्को का भी पहला बड़ा रक्षा विनिर्माण संयंत्र होगा। व्हाप के आकार, सुरक्षा, तरह-तरह के इस्तेमाल और कम कीमत को देखते हुए माना जा रहा है कि उपद्रव से जूझ रही अफ्रीकी सेनाएं इसे खरीदने के लिए आकर्षित होंगी।

देश के रक्षा निर्यात में तेजी का कुछ श्रेय कीमत की सीढ़ी पर हमारी उछाल को भी जाता है। दशक भर पहले भारत कम कीमत के गोला-बारूद और हथियार ही निर्यात करता था। आज हम तेजस हल्के लड़ाकू विमान, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे महंगे हथियार प्लेटफॉर्म पूर्वी एशियाई देशों को बेच रहे हैं, जिनमें वियतनाम, मलेशिया और फिलिपींस शामिल हैं। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत करीब 36.5 लाख डॉलर है। दिलचस्प है कि दस साल पहले हम साल में कुल इतनी कीमत का रक्षा निर्यात कर पाते थे।

रक्षा निर्यात में इजाफे का गणित सीधा है: रक्षा मंत्रालय की 'रक्षा उत्पादन नीति 2018' में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 2025 तक रक्षा एवं विमानन वस्तु एवं सेवा क्षेत्र में 1.7 लाख करोड़ रुपये का सालाना कारोबार हासिल करते हुए 20-30 लाख लोगों के लिए रोजगार तैयार किए जाएंगे। इसके लिए निवेश में करीब 70,000 करोड़ रुपये का इजाफा भी किया जाना था। मगर 2018 की नीति के मुताबिक देश का रक्षा उत्पादन 2013-14 में 43,746 करोड़ रुपये था और मामूली इजाफे के साथ 2016-17 में 55,894 करोड़ रुपये तक पहुंच पाया। नीति में दिए गए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपये के हथियार खरीदने वाले विदेशी खरीदार चाहिए थे। इसका मतलब था कि आयात पर अपनी निर्भरता घटाते हुए हमें 2025 तक प्रमुख हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने में आत्मनिर्भर होना है। इनमें लड़ाकू विमान, मझोली भारवहन क्षमता वाले विमान, हमले और अन्य कामों में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, जमीनी लड़ाकू वाहन, स्वचालित हथियार प्रणाली, मिसाइल सिस्टम, गन सिस्टम, छोटे हथियार, गोला-बारूद, निगरानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, संचार उपकरण, रात में लड़ने में मदद करने वाली प्रणाली, मानवरहित हवाई वाहन और प्रशिक्षण उपकरण आदि शामिल हैं।

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

किंतु इस नीति के सात वर्ष बाद भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है और अपनी रक्षा जरूरतों का 50 फीसदी आयात करता है। रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए वह अब भी संघर्ष कर रहा है। ये लक्ष्य हासिल करना भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं से परे नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूरी बदलाव को गति चार कदम गति देंगे।

पहला, आरंभिक सफलता बेशक उन रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्यात में मिली है, जिन्हें भारत में डिजाइन किया गया और बनाया गया किंतु यह शुरुआती कदम भर है। इन प्लेटफॉर्मों को अपनी सेना में तुरंत शामिल करने की जरूरत है, जहां उनका विकास होगा और क्षमताएं भी दिखेंगी। जब कोई नया प्लेटफॉर्म अच्छा प्रदर्शन करता है या अद्भुत क्षमता दिखाता है तो मीडिया की एक टीम को उस पर नजर रखनी चाहिए, उसकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह संभावित खरीदारों की नजर में आए। देश में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा तभी विदेशी ग्राहक भी उसे गंभीरता से देखेंगे।

दूसरा, जो उपकरण या प्लेटफॉर्म विकास के आखिरी चरण में हो या सेना में आने वाला हो, उसका परीक्षण वास्तविक जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए। अर्जुन टैंक और तेजस युद्धक विमान ऐसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें बदलाव की मांग आती रहती हैं। आरंभ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) अर्जुन में बदलाव करता रहा मगर बदलावों की मांग खत्म ही नहीं हुई और अंत में टैंक अपनी ही अपेक्षाओं के तले दब गया। इससे देश की सेना को सबक मिल गया होगा कि संपूर्णता अक्सर अच्छाई की दुश्मन होती है। हमारी सेना किसी भी प्लेटफॉर्म में अक्सर इतना कुछ डालने के लिए कुख्यात है, जिसकी जंग के मैदान में शायद ही कभी जरूरत पड़े। यही वजह है कि डीआरडीओ या युद्धपोत डिजाइन निदेशालय अक्सर बदलाव पर बदलाव करता रहता है और अंत में उत्पाद खत्म ही हो जाता है।

तीसरा सबक यह है कि रक्षा निर्यात ऐसे वाणिज्यिक उपकरणों का होता है, जिनसे खरीदार के लिए उत्पाद या प्लेटफॉर्म की लागत कम हो और विक्रेता के लिए उनकी कीमत बढ़ जाए। जो सरकार हथियारों की बिक्री पर जोर दे रही हो उसे पूरा जोर इसी पर देना चाहिए। इसलिए सैनिकों, अधिकारियों, राजनियकों, अर्थशास्त्रियों, टेक्नोक्रेट्स और मीडिया को भी कम लागत पर ऑर्डर हासिल करने के लिए जोर लगाना चाहिए।

चौथा और आखिरी सबक यह है कि हमें रक्षा खरीद एजेंसियों को ऐसा बनाना है कि फायदा ज्यादा से ज्यादा हो और देर कम से कम हो। अमेरिका जैसे प्रमुख रक्षा निर्यातकों ने इसके लिए बाकायदा विभाग बनाया है, जिसे रक्षा सहयोग कार्यालय का नाम दिया गया है। यह विभाग हथियारों की बिक्री पर नजर रखता है और जिम्मेदारी बांटता है। इसकी वजह से नियंत्रण कड़ा करने के इरादे से युद्ध सामग्री की एक सूची बनाई गई है और निर्यात पर नियंत्रण के लिए मानक प्रक्रिया तय की गई है। हमारे देश में रक्षा संवर्द्धन विभाग में एक छोटे से प्रकोष्ठ के अलावा ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, जिसे निर्यात से जुड़े काम सौंपे गए हों।

ऐसा विभाग अंतिम उपभोक्ता के प्रमाणन जैसी समस्याओं से निपटने में संस्थागत विशेषज्ञता प्रदान करेगा और तेजस जैसे विमानों की बिक्री के लिए जरूरी पेचीदा मंजूरी भी प्रदान करेगा। पेचीदा इसलिए है क्योंकि तेजस में विभिन्न देशों के सिस्टम और सब सिस्टम लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए इजरायल से एयरबोर्न रडार, ब्रिटेन से इजेक्शन सीट और फ्रांस से कॉच के कॉकपिट के लिए मंजूरी की जरूरत होगी। रूसी इंजन के निर्माण में देर होने की समस्या अलग है। इन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए एक संस्थान का निर्माण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

आपका पक्ष

जम्मू-कश्मीर में केवल विकास लक्ष्य हो

जम्मू-कश्मीर के विधान सभा चुनावों के परिणामों के बाद राज्य के सभी राजनीतिक दल और जनमानस सफल चुनावों के शांतिप्रिय संपन्न होने के लिए बधाई के पात्र हैं। चुनावों में विजयी नैशनल कॉन्फ्रेंस को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत उससे अधिक है और इस नाते वह राज्य के शासन में एक बड़ी भागीदार है। जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना राजस्व संग्रहण बहुत कम है और पर्यटन ही देश के सभी नागरिकों को जम्मू-कश्मीर से जोड़ता है। केंद्र के बिना वित्त पोषण और राज्य की विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाएं नहीं चल सकतीं और यह सहायता जम्मू-कश्मीर को देश भर के करदाताओं के राजस्व से मिलती है। इस नाते जम्मू-कश्मीर के विकास में पूरा देश भी भागीदार है। इसलिए राज्य की राजनीति को कश्मीर तक सीमित नहीं रखा जा सकता और रखना भी नहीं चाहिए।

नैशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का श्रीनगर में बुधवार को चुनाव परिणाम के एक दिन बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया

यह स्वागत योग्य है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से सहयोग की बात की है। केंद्र सरकार के साथ नैशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के समय बहुत अमैत्रीपूर्ण प्रचार किया था परंतु अब आगे बढ़ने का समय है। राज्य के युवा रोजगार चाहते हैं और जनमानस ने आतंकवाद के विरुद्ध वोट दिया है। सौभाग्य से नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता राजग गठबंधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको नए वातावरण को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी।

विनोद जौहरी, दिल्ली

रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम हो जीएसटी

जब सरकार ने जीएसटी प्रणाली को देश में आरंभ किया था, तब यह उम्मीद थी कि एक देश एक टैक्स आमजन को महंगाई से राहत दिलाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार करने के लिए जीएसटी लाने का फैसला लिया था, लेकिन शायद यह फैसला बिना किसी तैयारी के किया गया, क्योंकि जीएसटी के लिए सरकार ने कई बार इसके नियम बदले। बार-बार जीएसटी में बदलाव करने से क्या उपभोक्ता और छोटे-बड़े दुकानदार असमंजस के चक्रव्यूह में नहीं घिरेंगे? जीएसटी लागू होने के बाद देश के आर्थिक व्यवस्था पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा, इस पर कई मत हो सकते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए कि क्या पेट्रोल-डीजल और बिजली के बिल भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आने चाहिए? सरकार ने बीमा पॉलिसियों की किस्त पर जीएसटी लगाकर क्या उचित किया है? गरीब और मध्यम परिवार अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बीमा की पॉलिसी लेते हैं और बहुत मुश्किल से बीमा की किस्त भरते हैं। 18 जुलाई, 2022 से सरकार ने कुछ जरूरी चीजों, जिनमें मुख्यतः दुग्ध उत्पादन, आटा, दाल, पेपर आदि पर जीएसटी कुछ नई वस्तुओं को इसके अंतर्गत लाकर या कुछ वस्तुओं की पुरानी जीएसटी दरों को बढ़ाकर आमजन पर महंगाई का बोझ डाला है। सरकार को रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी कम करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

कोलकाता हवाई अड्डे पर पहली बार बुधवार को सबसे बड़े एयरबस विमान 'बेलुगा एक्सएल' का पानी की बौछारों के साथ शानदार स्वागत किया गया। 'बेलुगा एक्सएल', 'बेलुगा एसटी' का उन्नत और बड़ा संस्करण है तथा यह बेलुगा श्रृंखला का सबसे बड़ा विमान है। बेलुगा एक्सएल विमान की लंबाई 207 फुट, ऊंचाई 62 फुट है। इसके डैने 197 फुट लंबे तथा 10 इंच चौड़े हैं।

सम्पादकीय

भीड़भाड़ वाली जगहों से खत्म नहीं हो रहा हादसों का सिलसिला एयर शो के दौरान हुई अनहोनी

भीड़भाड़ वाली जगहों पर हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी जगहों पर आवाजाही, निकासी, हवा-पानी, चिकित्सा सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था करे। भीड़ प्रबंधन को लेकर नियम-कायदे भी तय हैं। मगर इसे लेकर सरकारों और पुलिस-प्रशासन प्रायः लापरवाह ही देखे जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर भगदड़, तेज गर्मी, मंचों के टूटने, आग लगने आदि की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, पर प्रशासन उनसे कोई सबक लेता नजर नहीं आता। उसी की ताजा कड़ी चेन्नई के 'एअर शो' में तेज गर्मी और निर्जलीकरण के कारण पांच लोगों की मौत और करीब सौ लोगों की सेहत खराब होने के रूप में सामने आई।

बताया जा रहा है कि विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए भारतीय वायु सेना ने करीब सोलह लाख लोगों को चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर जुटा लिया। मगर इतने लोगों के लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे, वे नहीं किए गए। वहां का विपक्ष राज्य सरकार पर बदइंतजामी का ठीकरा फोड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि भारतीय वायु सेना ने जितने सुरक्षाकर्मी मांगे थे, उससे अधिक उपलब्ध कराए गए थे। साढ़े छह हजार पुलिस कर्मी और डेढ़ हजार होमगार्ड तैनात किए गए थे। फिर यह सवाल अपनी जगह है कि इसके बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा।

बताया जा रहा है कि लोगों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पुलिस कर्मियों ने समुद्र किनारे पानी वगैरह बेच रहे खोमचे वालों को हटा दिया था। इसलिए लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सका। फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों में ऐसी अफरातफरी मची कि घर पहुंचने के लिए बसों और मेट्रो आदि के लिए जगह-जगह भीड़ लग गई। चेन्नई की सड़कों पर घंटों वाहनों का जाम लगा रहा। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो अनुमानित भीड़ के मद्देनजर आने-जाने के रास्ते पहले से तय किए जाते हैं, लोगों के लिए पीने के पानी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं आदि का इंतजाम किया जाता है। मगर चेन्नई के 'एअर शो' में इसका नितांत अभाव देखा गया। आखिर क्यों भारतीय वायु सेना और चेन्नई पुलिस ने यह जानते हुए भी कि करीब सोलह लाख लोगों की भीड़ जमा होने वाली है, सुरक्षा संबंधी उपायों में लापरवाही बरती। ऐसे कीर्तिमान बना लेने का भी क्या लाभ, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। यह कोई ऐसा आयोजन नहीं था, जिसे स्थानीय और अननुभवी लोगों ने बिना कुछ सोचे-समझे आयोजित किया था। इसके लिए महीनों से तैयारियां की गई होंगी। प्रचार-प्रसार किया गया होगा। उसमें विशिष्ट लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया गया होगा। मौसम विभाग से जानकारी ली गई होगी। मौसम संबंधी जानकारी के लिए तो भारतीय वायुसेना का अपना भी इंतजाम रहता है। फिर, कैसे यह अनुमान लगाने में चूक हुई कि लोगों को गर्मी के कारण परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। यह भी समझ से परे है कि जब पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तो यातायात व्यवस्था संभालने में वे कैसे विफल साबित हुए।

हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का कम होगा इंडिया गठबंधन में बार्गिन पॉवर

इस चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन का अन्य राज्यों में यह सवाल दूसरे जोर पकड़ रहा है। इसका तुरंत असर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के अलावा उपचुनाव पर भी दिख सकता है। इस परिणाम ने सहयोगी दलों के इस अपरोक्ष आरोप को सही साबित किया कि अब भी कांग्रेस को भाजपा से मुकाबले के लिए क्षेत्रीय दलों के सहयोग की जरूरत है। साथ ही जब भी कांग्रेस अकेले भाजपा के सामने आती है वह कमजोर साबित हो जाती है। हरियाणा में चुनाव कांग्रेस हार गईस जहां वहां अकेले दम मैदान में थी। जम्मू-कश्मीर में जब नैशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन को लीड किया तो गठबंधन को जीत मिली। गौरतलब है कि 2014 से यह ट्रेंड लगातार जारी है, लेकिन 2023 दिसंबर में इस पर गंभीर बहस हुई थी।

अशोक भाटिया

किसी भी चुनाव में यदि दो दल एक दूसरे के सामने उतरते है तो यह निश्चित है कि एक की हार होगी तभी दूसरे दल की जीत होगी । यह बात सर्वविदित है । यही सब कुछ हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव में । चुनाव में भाजपा व इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस का सीधा मुकाबला था । इसमें भाजपा की जीत हुई और कांग्रेस की हार । अब किसे तो हारना ही था । पर कांग्रेस की इस हार के साथ ही गठबंधन में जो उसका बार्गिन पॉवर था वो कम पड़ता दिख रहा है । उत्तरप्रदेश में अब राहुल गाँधी अपनी तेजी से उड़ती पतंग देख अपने सहयोगियों पर ही दबाव बनाने की कोशिश करने लगे थे । बताया जाता है कि असल में उत्तरप्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है । इसके लिए कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फॉर्मूला चाहती है यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ,राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं । समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी। जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे।

राहुल गांधी से मिला ये धोखा अखिलेश शायद ही भूले होंगे और हरियाणा में इस मार के बाद हो सकता है कि उत्तरप्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को यही सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं भाजपा अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। वैसे कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है, जहां-जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं, जिसमें कांग्रेस 6 पर जीती थी। इसके बाद कहीं न कहीं अखिलेश यादव के कारण ही यूपी में अस्तित्व खोने की कगार पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली थी। अब विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस, अखिलेश यादव से उसी दरियादिली की उम्मीद जता रही है। साथ ही साथ उन्हें अकेले उपचुनाव लड़ने का तेवर भी दिखने लगी है। अब लगता है उसके यह तेवर नरम पड़ जाएंगे । कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास में मध्य प्रदेश में किसी भी सहयोगी दलों को न सिर्फ सीट देने से इनकार किया बल्कि पार्टी के सीएम उम्मीदवार कमलनाथ ने समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए उन्हें छोटा नेता बताते हुए टिप्पणी भी की थी। ऐसा तब हुआ था जब सभी विपक्षी दलों ने भाजपा से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपने ही सहयोगी दलों पर प्रतिकूल टिप्पणी की। नतीजा आया तब दोनों राज्य कांग्रेस हार गई। इसके बाद कांग्रेस ने अचानक डैमेज कंट्रोल करने की पहल भी की थी पर बाद में वाही ढ़ाक के तीन पात । फिर आम चुनाव में जद्दोजहद के बाद अंततः कांग्रेस गठबंधन करने में सफल रही। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आम चुनाव में भले कांग्रेस ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन उसे उन्हीं राज्यों में अधिक सफलता मिली जहां उसके साथ दूसरे क्षेत्रीय दलों का मजबूत साथ था। मसलन, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का साथ। परिणाम के तुरंत बाद जब हरियाणा चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस अकेले लड़ी और आप या समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। हालांकि, उनके साथ सीटों पर चर्चा हुई थी। इस पर क्षेत्रीय दल के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस वास्तविकता को नहीं समझेगी तो पार्टी को हाल में मिली यह बढ़त गंवानी पड़ सकती है। अधिकतर क्षेत्रीय दल अभी मानते हैं कि वे कितना भी एकजुट हो जाएं, अगर कांग्रेस ने अपनी स्थिति नहीं सुधारी तो इस लड़ाई का मतलब नहीं। इसके पीछे उनका तर्क है कि 2019 आम चुनाव में लगभग 225 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस-भाजपा का सीधा मुकाबला हुआ जिनमें 200 से अधिक सीटें भाजपा ने जीतीं। 2024 आम चुनाव में भी भाजपा ने अधिकतर सीटें कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में जीतीं। विधानसभा चुनाव में भी हाल के वर्षों में बहुत कम ऐसे चुनाव हुए हैं जहां कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीनी हो। ऐसा पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन हारी हुई राज्यों की लिस्ट लंबी है। मंगलवार को आए परिणाम के बाद अब क्षेत्रीय दलों का दबाव कांग्रेस पर बढ़ेगा इसमे कोई शक नहीं है । गठबंधन में शामिल कई दल बीते दिनों आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस इसमें मनमानी कर रही है और उनके स्पेस को स्वीकार नहीं कर रही है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों से महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में अगले दौर के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ सलाह मिली। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण आप कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने में विफल रही थी। उसका नतीजा यह है । यदि समाजवादी व आप पार्टी भी साथ होती और उसके वोट भी कांग्रेस के साथ जुड़ते तो परिणाम अलग होते । बता दें कि हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन करने में विफल रही थी। हालांकि शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र में कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां अगले महीने चुनाव होने की संभावना है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई दिनों तक यही सोचते रहे कि आप एक ऐसा रास्ता चुनते हैं कि आपको परिवार के लिए सोचना होगा कि क्या सही है, क्या आपको किसके बुरा लगेगा और दुखी करता, आपको किस बात से तकलीफ लगता पहेगा। हम ने किसी हमारे दिल की और अंदर हुई को सुनाकर कहा स्वास्थ्यकर उनके को मस्कुरा दीजिये, बौद्धिक प्रदर्शनीय तकनीकों में भी, जहां तक स्वास्थ्यकारक हमें लाभदायक और कामाशील में लाभ प्राप्त होगा

मेष
किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

वृष
विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

मिथुन
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

कर्क
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा।

सिंह
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कन्या
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और खेलीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

तुला
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

वृश्चिक
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

धनु
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

मकर
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

कुंभ
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

मीन
आज वाणी पर संयम रखें. खेलीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे। खेलीजनों के साथ चिन्ताता बढ़ेगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

डॉ.कुश कुन्दनानी
(वरिष्ठ सर्जन, राजीव गाँधी चिकित्सालय)

नमस्कार मित्रों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजकीय राजीव गाँधी हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉ. कुश कुन्दनानी। इनका जन्म 19 मई सन 1975 को श्री नानक कुंदनानी और लक्ष्मी कुन्दनानी के यहां हुआ। घर का वातावरण शैक्षणिक की रहा क्योंकि पेरेंट्स शिक्षा विभाग में शिक्षक थे। पिताजी एवं माताजी देश विभाजन की अद्भुत पीड़ा को झेलकर किसी तरह हिंदुस्तान पहुंचे थे। उनके पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से ओत-प्रोत रहे जिस वजह से उन्हें स्वर्गीय श्री लालकृष्ण आडवाणी का सानिध्य मार्गदर्शन मिला क्योंकि दोनों ही प्रारंभिक कार्यस्थली अलवर ही रही। डॉ.कुन्दनानी की स्कूली शिक्षा बाल विहार एवं हैप्पी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से हुई तत्पश्चात सन 1994 में इनका पीएनटी परीक्षा में चयन हुआ और डॉ.मेडिकल कॉलेज जोधपुर में प्रवेश लिया इसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल कॉलेज कोटा से की। इनकी प्रारंभिक राजकीय सेवा टेहला और राजगढ़ में हुई उसके पश्चात सन 2013 में निरंतर राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में सर्जन के पद पर कार्यरत हैं। डॉ. कुन्दनानी इस कॉलम के माध्यम से अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की संख्या अत्यधिक है परंतु फिर भी ये प्रयास यही करते हैं यहां के सभी मरीजों का बिना किसी धर्म जाति के और संपन्नता को देखते हुए अपने ही संसाधनों से उनका इलाज करके उन्हें स्वस्थ करके भेजें। ये लोगों के दिमाग से ऐसी मानसिकता व भ्रांति को मिटाना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में तो काम होता ही नहीं । संयमशील, सहज सुलभ और शांत व्यक्तित्व के धनी है डॉक्टर कुंदनानी। हर मरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं इसीलिए हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर मरीज और उनके परिजन उनको मन से इज्जत करते हैं। डॉक्टर कुश कुन्दनानी इस कॉलम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी मरीज और परिजन अस्पताल को साफ-सुथरा रखने में अपना भरपूर सहयोग दें। मरीज के साथ कम से कम परिजन आए। अनावश्यक भीड़ मरीज के इलाज में बाधा बनती है। अलवर शहर को स्वच्छ बनाए रखने में कलेक्टर डॉ.आर्तिका शुक्ला के इस मुहिम का सहयोग करें। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम ऐसे यशस्वी चिकित्सक के उज्जवल भविष्य की कामना करती है ।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

10 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने 1756 में कलकत्ता पर पुनः कब्जे के लिए मद्रास से कूच किया।
- ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेल ने 1846 में नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की।
- क्यूबा ने 1868 में स्पेन से स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह किया।
- वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन 1910 में किया गया था।
- शिकागो में स्थित लोयोला विश्वविद्यालय के लेक शोर परिसर में अल्फा डेल्टा गामा बिरादरी की स्थापना 1924 में की गई।
- सोवियत संघ ने 1942 में आस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंध की शुरुआत की।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 को होलोकोस्ट में 800 जीप्सी बच्चों को मार डाला गया था।
- टोकियो में 1964 को हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया।
- फिजी ने 1970 में स्वतंत्रता हासिल की।
- अमेरिका के एरिजोना के लेक हवासु शहर में लंदन ब्रिज को 1971 में पुनर्निर्मित किया गया। इसे ब्रिटेन से खरीदकर तोड़कर अमेरिका लाया गया था।
- रोहिणी खाडिलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला 1978 में बनी।
- सैन सल्वाडोर में 1986 को 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में 1,500 लोगों की मौत।
- अमेरिका का 67वां मानव अंतरिक्ष मिशन डिस्कवरी 11 अंतरिक्ष से 1990 में लौटा।
- भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब 1991 को जीता।
- दूसरा हुगली पुल 'विद्यासागर सेतु' 1992 में खुला।
- सन् 2006 में राइकुल खेल मेलबोर्न में कराये जाने की घोषणा 1999 में की गई।
- बांग्लादेश में खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ 2001 को ग्रहण की।
- भारत ने इस्रायल रूस के साथ एवाक्स निर्माण के लिए 2003 में समझौता किया।
- ऑस्ट्रेलिया के 2004 को संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जान हावर्ड की भारी जीत।
- एंजेला मार्केल 2005 में जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनीं।
- निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 2008 को भारी गिरावट दर्ज की गई।
- भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2014 में की गयी।

10 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति

- भारत के प्रारम्भिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद अमृत डांगे का जन्म 1899 में हुआ।
- भारतीय उपन्यासकार आर. के. नारायण का जन्म 1906 में हुआ।

विशेष आलेख

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : बेहतर दुनिया बनाने के लिये मन को स्वस्थ करना जरूरी

ललित गर्ग

मन की स्वस्थता शरीर की स्वस्थता से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन की पूर्णता, सार्थकता एवं सफलता मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। मन से स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हो सकता है। मन स्वस्थ रहे एवं आगे से आगे मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता जाये, इसी उद्देश्य से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालने, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले लोगों का समर्थन करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का महत्व मानसिक स्वास्थ्य को वैश्विक प्राथमिकता बनाने के अपने मिशन में निहित है। यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहल को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 के लिए थीम 'कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य' की घोषणा की है। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक तंदुरुस्ती की एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह से सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। यह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का एक अभिन्न अंग है जो निर्णय लेने, संबंध बनाने और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे आकार देने की हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं को रेखांकित करता है। सुरक्षित, मनोरम, हास्यवर्द्धक, भारहित, सहायक कार्य वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सुरक्षात्मक भूमिका निभाते हैं। हालाँकि भेदभाव, उत्पीड़न, असुरक्षित और खराब कार्य स्थितियों जैसी अस्वस्थ स्थितियाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकती हैं। ये चुनौतियाँ जीवन की समग्र गुणवत्ता, कार्य भागीदारी और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को ताजा करने और एक स्वस्थ और खुशहाल कार्य वातावरण बनाने की ज्यादा अपेक्षा है। शोध के अनुसार, 6 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करता है और हर साल 12 बिलियन कार्य दिवस अवसाद, तनाव और चिंता के कारण बर्बाद हो जाते हैं। देश में कार्यस्थलों में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता की स्पष्ट आवश्यकता है, जिससे न केवल व्यक्ति को बल्कि संगठन को भी लाभ होगा। वास्तव में, जो कर्मचारी खुश रहते हैं वे 13 प्रतिशत अधिक उत्पादक होते हैं, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना व्यावसायिक रूप से समझदारी है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता है। जैसे शरीर की सफाई दिन में कई बार आवश्यक है, वैसे ही मन की सफाई कई बार होनी चाहिए। मिल या अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम करने वालों का कपड़ा थोड़ा-थोड़ा करके शाम तक खराब हो जाता है, वैसे ही मन भी कार्यस्थलों पर तरह-तरह के संकटों, तनावों एवं परेशानियों से खराब होता है। इसके लिये लंबी, गहरी सांस से मानसिक स्वास्थ्य की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। मन से लड़े नहीं, बल्कि उसे समझाएं। प्रमोदभाव-गुणात्मक दृष्टि का विकास करें। मन को वॉचमैन बनाकर रखिये। क्योंकि जीने का वास्तविक अर्थ है हर पल स्वयं के द्वारा स्वयं का निरीक्षण। देखना है कि मन कब राग-द्वेष, तनाव, अवसाद, विकास एवं कुंठाग्रस्त हो रहा है। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। कार्यस्थल पर बढ़ते तनाव और उससे जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ, नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना और उसे प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चला है कि कार्यस्थल पर ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी दबाव और तनाव महसूस कर रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। 55 प्रतिशत कर्मचारियों को लगता है कि उनका काम ज्यादा तीव्र और मांग वाला होता जा रहा है। इसके अलावा, शोध से पता चलता है कि ब्रिटेन के पाँच में से एक कर्मचारी ने कार्यस्थल पर तनाव और दबाव को प्रबंधित करने में असमर्थता महसूस की। लगभग ऐसी ही स्थितियां भारत में भी देखने को मिल रही है। भारी कार्यभार, तंग समय सीमा और सहायता की कमी जैसे तनाव कर्मचारियों में चिंता, तनाव, अवसाद और बर्नआउट का कारण बन सकते हैं। कई कर्मचारी कमजोर समझे जाने, संभावित रूप से अपनी नौकरी खोने या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी परेशानियों के कारण मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने से डरते हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की आम बात को तेजी से पहचान रहे हैं और कर्मचारियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य को समझने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज के आँकड़ों के अनुसार, ज्ञान की कमी, मानसिक बीमारी के कलंक और देखभाल की उच्च लागत जैसे कई कारणों की वजह से 80 प्रतिशत से अधिक लोगों की देखभाल सेवाओं तक पहुँच नहीं है। वर्ष 2012-2030 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीपुरा रोड़ खण्डवा,जिलाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतिक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राव विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन न.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास जिलाई, टोंक फोन न.01432-244881 जिलाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-पेहलाद सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार